राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 26

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 6 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



मेरी कोम और मनप्रीत ओलंपिक में होंगे देश के ध्वजवाहक

>>12

आइटी एक्ट की धारा 66ए के तहत केस दर्ज करना चौंकाने वाला : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आइटी एक्ट) की रद की गई धारा 66ए के तहत लोगों के खिलाफ अब भी मामले दर्ज किए जाने पर सोमवार को आश्चर्य व्यक्त किया और इसे चौंकाने वाला बताया। शीर्ष अदालत ने ही 2015 में इस धारा को निरस्त किया था। इस धारा के तहत अपमानजक संदेश पोस्ट करने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रविधान था।

जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और बीआर गवई की पीठ ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज' (पीयूसीएल) की ओर से दायर आवेदन पर केंद्र को नोटिस जारी किया। पीठ ने पीयूसीएल की ओर से पेश अधिवक्ता संजय पारीख से कहा, 'क्या आपको नहीं लगता कि यह आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला है? श्रेया सिंघल फैसला 2015 का है। यह वाकई चौंकाने वाला है। जो हो रहा है, वह भयानक है।' पारीख ने कहा कि 2019 में अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी राज्य सरकारें 24 मार्च, 2015 के उसके फैसले को लेकर पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाएं, बावजूद इसके इस धारा के तहत हजारों मामले दर्ज कर लिए गए। पीठ ने कहा, 'हां, हमने वे आंकड़े देखें हैं। चिंता न करें, हम कुछ करेंगे।' पारीख ने कहा, मामले से निपटने के लिए किसी तरह का तरीका होना चाहिए क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, आइटी अधिनियम का अवलोकन करने पर देखा जा सकता है कि धारा 66ए उसका हिस्सा है और नीचे टिप्पणी है जहां लिखा है कि इस प्रविधान को रद कर दिया गया है।

सख्त टिप्पणी

- सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दी गई धारा के तहत मामले दर्ज किए जाने पर आश्चर्य भी व्यक्त किया
- कहा, जो हो रहा है वह भयानक है, केंद्र को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में मांगा जवाब



अटार्नी जनरल का सुझाव

वेणुगोपाल ने कहा, 'जब पुलिस अधिकारी को मामला दर्ज करना होता है तो वह धारा देखता है और नीचे लिखी टिप्पणी को देखे बिना मामला दर्ज कर लेता है। अब हम यह कर सकते हैं कि धारा 66ए के साथ ब्रैकेट लगाकर उसमें लिख दिया जाए कि इस धारा को निरस्त कर दिया गया है। हम नीचे टिप्पणी में फैसले का पूरा उद्धरण लिख सकते हैं।' जस्टिस नरीमन ने कहा, 'आप कृपया दो हफ्तों में जवाबी हलफनामा दायर करें। हमने नोटिस जारी किया है। मामले को दो हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाए।'

कोर्ट ने 2019 में भी दी थी चेतावनी

सात जनवरी 2019 को पीयूसीएल के आवेदन पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने कहा था कि यह चौंकाने वाला है कि 2015 में शीर्ष अदालत द्वारा आइटी अधिनियम की धारा 66 ए को खत्म करने के बाद भी इसके तहत लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। पीठ ने केंद्र से जवाब मांगा था और संबंधित अधिकारियों को उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए जेल भेजने की चेतावनी दी थी।

अदालत ने 2015 में रद किया था प्रविधान

शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2015 को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को 'प्रमुख' करार दिया था और यह कहते हुए इस प्रविधान को रद कर दिया था कि 'जनता के जानने का अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए से सीधे तौर पर प्रभावित होता है।'

महाराष्ट्र की दो लड़कियों की गिरफ्तारी से जुड़ा है मुद्दा : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के पालघर में इंटरनेट मीडिया पोस्ट को लेकर दो लड़कियों – शाहीन ढाडा और रिनू श्रीनिवासन को गिरफ्तार किए जाने के बाद अधिनियम की धारा 66 ए में संशोधन के लिए कानून की छात्रा श्रेया सिंघल ने पहली बार 2012 में इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी।

नए आइटी नियमों को लागू करने में ट्विटर नाकाम

नई दिल्ली : ट्विटर द्वारा नए आइटी नियम को लागू नहीं करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अमित आचार्य की अर्जी पर हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा है कि ट्विटर इसे लागू करने में नाकाम रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि नए आइटी नियम का अनिवार्य रूप से पालन आवश्यक है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। (पेज-7)

जागरण विशेष



भविष्य की चिंता में वर्तमान समय में बारिश की बूंदों का संचयन करने पर जोर दिया जा रहा है। वृंदावन का रंग जी मंदिर प्रबंधन काफी पहले ही जल संकट को लेकर सचेत हो गया था। यहां 183 साल पहले ही बारिश की बूंदों को सहेजने का काम शुरू हो गया था। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

दिल्ली में वकील के चैंबर में हुआ मतांतरण और निकाह

नई दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील के चैंबर को मस्जिद में तब्दील कर युवती का मतांतरण और निकाह कराने का मामला सामने आया है। युवती के पिता की शिकायत पर दिल्ली बार काउंसिल ने जांच के लिए तीन सदस्यीय अनुशासन समिति गठित की है। आरोपित वकील इकबाल मलिक का लाइसेंस निलंबित कर नोटिस जारी किया गया है।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

शक्ति भोग कंपनी का अध्यक्ष मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में की गई है। जांच एजेंसी ने कुमार को विशेष मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कुमार को नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

कोरोना से जंग ▶ पृष्ठ 6

कोविन प्लेटफार्म में दुनिया ने दिखाई दिलचस्पी

नई दिल्ली : कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को सुचारू रूप से चलाने वाले कोविन प्लेटफार्म में दुनिया के 142 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। प्लेटफार्म की खासियत की जानकारी देने के लिए वर्चुअल तरीके से आयोजित पहले ग्लोबल कानक्लेव में प्रधानमंत्री ने कहा, यह दुनिया के सभी देशों के लिए उपलब्ध है। स्थानीय जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया जा सकता है।

दो बार इम्तिहान देंगे 10वीं-12वीं के छात्र

तैयारी ▶ कोरोना के मद्देनजर सीबीएसई ने वर्ष 2022 के लिए घोषित की विशेष मूल्यांकन योजना

शैक्षिक सत्र में होंगे दो टर्म, पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बोर्ड की परीक्षाएं रद करनी पड़ीं। सीबीएसई मूल्यांकन प्रणाली के जरिए छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सीबीएसई ने 2021-22 में 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा की है। नए मानदंडों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया जाएगा। हर टर्म में 50 फीसद पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा।

सीबीएसई ने कहा, नया शैक्षणिक सत्र हर सत्र में पाठ्यक्रम के 50 फीसद हिस्से की पढ़ाई के साथ दो टर्म में विभाजित किया जाएगा। पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर और दूसरे टर्म की मार्च-अप्रैल में होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा, बोर्ड पाठ्यक्रमों को और अधिक तर्कसंकत बनाया जाएगा। नया पाठ्यक्रम जुलाई अंत तक अधिसूचित किया जाएगा।

- वहीं दूसरे टर्म की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में कराई जाएंगी



क्या बदलेगा

- शैक्षणिक सत्र के दो टर्म होंगे, हर टर्म में कुल पाठ्यक्रम के 50 फीसद हिस्से की पढ़ाई होगी
- नवंबर-दिसंबर में पहले और मार्च-अप्रैल में दूसरे टर्म की परीक्षाएं होंगी
- आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाया जाएगा
- निष्पक्ष तरीके से अंक दिए जाने के लिए बोर्ड द्वारा नीति की घोषणा की जाएगी
- सत्र 2021-2022 के लिए नए पाठ्यक्रम को जुलाई अंत तक अधिसूचित किया जाएगा

पहले टर्म में क्या होगा खास

- नवंबर-दिसंबर में 4 से 8 सप्ताह में संपन्न होंगी परीक्षाएं।
- बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होंगे। केस आधारित और रीजनिंग की परीक्षा का समय 90 मिनट होगा।
- टर्म 1 में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षा होगी।
- सीबीएसई स्कूलों को प्रश्नपत्र भेजेगा। बोर्ड द्वारा नियुक्ति आब्जर्वर की निगरानी में होंगी परीक्षाएं।
- छात्र उत्तर पुस्तिका के रूप में ओएमआर सीट का प्रयोग करेंगे।
- ओएमआर सीट स्कैनिंग के बाद पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- परीक्षा वाले दिन ही छात्र द्वारा पाए गए नंबर भी अपलोड कर दिए जाएंगे।

टर्म 2 में क्या होगा खास

- मार्च-अप्रैल में होने वाली परीक्षा को सीबीएसई ने वार्षिक परीक्षा भी कहा है।
- परीक्षा दो घंटे में संपन्न होगी। केस आधारित, स्थिति आधारित, शार्ट और लांग प्रश्न होंगे।
- यदि कोरोना से उपजे हालात परीक्षा की इजाजत नहीं देते हैं तो 90 मिनट की परीक्षा होगी।
- टर्म 2 के परिणाम समग्र होंगे।

विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेगा सीबीएसई

- यदि हालात सुधरे तो टर्म 1 एवं 2 की परीक्षाएं स्कूलों, केंद्रों पर होंगी। थ्योरी के अंक दोनों परीक्षाओं में समान होंगे।
- यदि टर्म 1 में हालात खराब और टर्म 2 में सुधरे तब टर्म 1 की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली होंगी। छात्र घर से परीक्षा देंगे। अंतिम स्कोर के लिए इस परीक्षा को कम वेटेज दिया जाएगा। टर्म 2 परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाएगा।
- यदि मार्च-अप्रैल में स्कूल बंद रहे, सिर्फ टर्म 1 परीक्षाएं हुईं तब छात्र के प्रदर्शन, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम जारी होगा। वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी करते समय टर्म 1 को वेटेज दिया जाएगा।
- यदि पूरे साल स्कूल बंद रहे, टर्म 1 एवं 2 की परीक्षाएं घर से छात्रों ने दी तब परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, टर्म 1 एवं टर्म 2 के थ्योरी अंक आदि के जरिए तैयार किया जाएगा।

सीबीएसई द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि स्कूल एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर और इनपुट का भी इस्तेमाल करेंगे। जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं नहीं दी जाते तब तक आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

जेईई मेन और नीट का एलान इसी सप्ताह होगा, एनटीए ने तैयार की योजना पेज>>3

आरक्षण पर राज्यों के अधिकार की बहाली पर केंद्र सरकार अड़ी

- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बोले, पहले वाली व्यवस्था होगी बहाल
- कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस संबंध में हो रही बातचीत, संसद के मानसून सत्र में लाया जा सकता है विधेयक
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को नहीं है पिछड़ों की पहचान का अधिकार, फैसले पर पुनर्विचार से भी कर दिया था इन्कार



प्रविधान पर कायम : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। फाइल फोटो/प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भले ही यह कहा हो कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन केंद्र इससे सहमत नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने साफ किया है कि पहले जो प्रविधान था, उस पर हम कायम हैं। जिसमें राज्यों के पास सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर सूची बनाने का अधिकार था। केंद्र के पास भी सूची बनाने का अधिकार था। इसे बहाल करने का प्रविधान किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री गहलोत ने सोमवार को 'दैनिक जागरण' से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सूची बनाने का राज्यों का जो अधिकार छिन गया था, अब उसे बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से इस संबंध में मार्गदर्शन लिया जा रहा है। जल्द ही संसद के जरिये राज्यों के पहले वाले अधिकारों को बहाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के इस रुख से साफ है कि संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस संबंध में विधेयक ला सकती है। हालांकि इससे पहले राज्यों को राहत देने से जुड़े उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग की सूची बनाने के राज्यों के अधिकार की बहाली को लेकर यह सक्रियता तब दिखाई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर सुनाए गए फैसले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच मई को मराठा आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए राज्यों को मिले इन अधिकारों को खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों के पास सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ों की पहचान कर सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। वह ही किसी वर्ग को सूची में जोड़ सकती है या फिर बाहर कर सकती है। बता दें कि सूची के आधार पर ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण प्रदान किया जाता है।

गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में कई शहरों में सीबीआइ के छापे

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआइ ने दो जुलाई को केस दर्ज करने के बाद सोमवार को आरोपितों के उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों के 15 जिलों में स्थित 42 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआइ ने सबसे अधिक लखनऊ स्थित 25 ठिकानों पर छानबीन की, जबकि, अलवर व कोलकाता स्थित दो स्थानों पर भी छापा मारा। लखनऊ, गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा, बुलंदशहर, एटा, मुरादाबाद, मेरठ व इटावा समेत उप्र के 13 जिलों में छापेमारी के दौरान घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज, लैपटाप व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए गए हैं। इनमें गोरखपुर में राप्तीनगर कालोनी स्थित भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल का आवास भी शामिल है। विधायक का छोटा भाई अखिलेश सिंह भी नामजद आरोपित है। अखिलेश की फर्म रिशु कंस्ट्रक्शन ने भी रिवरफ्रंट में काम किया था।

बता दें, सपा शासनकाल की 1500 करोड़ रुपये की गोमती रिवरफ्रंट परियोजना से जुड़े करीब 407 करोड़ रुपये के अन्य कार्यों में घपला पकड़ा गया है। सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने 407 करोड़ रुपये के 661 कार्यों की आरंभिक जांच के बाद सिंचाई विभाग के 16 तत्कालीन अफसरों समेत 189 आरोपितों के विरुद्ध अपनी दूसरी एफआइआर दर्ज की है। आपराधिक साजिश व धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज एफआइआर में निजी फर्म संचालकों, ठेकेदारों व अन्य के नाम भी शामिल हैं। जांच में पता चला है कि अफसरों की मदद से नियमों को दरकिनार कर निजी फर्मों को अधिक कीमत पर काम दिए गए थे। इस घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है।

- उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों के 15 जिलों में स्थित 42 ठिकानों पर छापेमारी
- उप्र की पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल में हुआ था यह घोटाला
- 16 लोक सेवकों समेत 189 आरोपितों के विरुद्ध दर्ज किया दूसरा केस



लखनऊ में सोमवार को गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आरोपित जीवन राम यादव के घर छापेमारी के बाद बाहर निकलती सीबीआइ टीम। पंकज ओझा

यहां मारे छापे : सीबीआइ ने नामजद आरोपित सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव, शिवमंगल यादव, जीवन राम यादव, सुरेन्द्र कुमार पाल, कमलेश्वर सिंह, तत्कालीन चीफ इंजीनियर ओम वर्मा, काजिम अली, एसएन शर्मा, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद यादव समेत अन्य अधिकारियों व फर्म संचालकों के ठिकानों पर छापे मारे हैं।

दो अधीक्षण अभियंताओं के घर से मिले लाखों रुपये : सीबीआइ छापों के दौरान दो अधीक्षण अभियंताओं के घर से लाखों रुपये नकद भी बरामद हुए। सूत्रों का कहना है कि आरोपित रूप कुमार यादव समेत दो अधीक्षण अभियंताओं के ठिकानों से पांच-पांच लाख रुपये से अधिक नकदी बरामद की गई है। कई जरूरी दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं।

योगी सरकार ने की थी सीबीआइ जांच की सिफारिश पेज>>6

महाराष्ट्र में एक साल के लिए 12 विधायक निलंबित

मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को कार्यवाहक अध्यक्ष से दुर्व्यवहार के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने अपनी पार्टी के विधायकों पर लगे आरोप को गलत बताया है। (पेज-3)

जागरण प्रभाव

दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद उपमुख्यमंत्री ने छात्रा से की फोन पर बात, एससी-एसटी छात्रों के दाखिला नियमों में बदलाव को लेकर छात्रा ने उठाए थे सवाल

अंबेडकर विवि अब नहीं लगाएगा नेहा पर जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार का अंबेडकर विश्वविद्यालय आखिर छात्रा नेहा पर जुर्माना नहीं लगाएगा। उसने अपना आदेश वापस ले लिया है। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को नेहा से फोन पर बात की और कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के छात्रों के लिए उनकी जो भी मांगें हैं, उन्हें लेकर वह उनसे आकर मिलें। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखकर जुर्माने के आदेश को निरस्त करने और छात्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे।

शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों को निर्देशित करें कि उनमें छात्रों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी मिले। उनका दृष्टिकोण यदि सरकार और विश्वविद्यालय के अनुरूप नहीं भी है तो भी उन पर भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाए, जब तक कि उससे सामाजिक तानाबाना न बिगड़े।



नेहा : इंटरनेट मीडिया



छात्रों के हक की आवाज उठाई, नहीं भरूंगी जुर्माना : नेहा

पांच जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर।

मालूम हो कि विश्वविद्यालय के वर्चुअल दीक्षा समारोह के दौरान छात्रा नेहा ने नियमों में बदलाव के कारण एससी-एसटी वर्ग के छात्रों को दाखिले में हो रही परेशानी व अधिक फीस वसूले जाने को लेकर सवाल उठाए थे। विश्वविद्यालय ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए उन्हें नोटिस जारी कर पांच हजार रुपये जुर्माना भरने के निर्देश दिए थे। यह भी कहा था कि जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पर नेहा ने रविवार को दैनिक जागरण से बातचीत में स्पष्ट कहा था कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों में मुख्यमंत्री या किसी अन्य के खिलाफ कोई असंसदीय या अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है, ऐसे में माफी मांगने व जुर्माना भरने का सवाल ही नहीं उठता।

स्कूल आफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में परास्नातक की पढ़ाई कर रहीं नेहा का कहना था कि उनका विरोध दरअसल, विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षित वर्ग के छात्रों के हितों को नजरअंदाज करने से उपजा आक्रोश था। बकौल नेहा, पहले एससी-एसटी वर्ग की पूरी फीस माफ थी, लेकिन गत वर्ष जून में विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस माफी वापस ले ली थी। छात्रों ने इसका विरोध किया तो विवि ने अपना निर्णय वापस ले लिया, लेकिन फीस वृद्धि करने व आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली के जाति प्रमाण की अनिवार्यता पर चुप्पी साध ली थी।

2020 के अप्रैल में दिल्ली सरकार ने गैर राशन कार्ड धारक को खाद्यान्न और सूखा राशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की थी। लेकिन योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी के आरोप लगे है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 6 जुलाई, 2021

हाई कोर्ट पहुंचा अनाज बर्बादी का मामला, जनहित याचिका दायर

आवाज की बुलंद ▸ दिल्ली सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गरीबों में बांटने के लिए खरीदे गए अनाज की बर्बादी का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। गैर सरकारी संगठन संपूर्णा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता प्रशांत रावत के माध्यम से दायर याचिका में संगठन ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा नहीं कर सकी। अनाज की बर्बादी होने के कारण प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, दैनिक मजदूरी करने वाले, बेरोजगार और वृद्ध लोगों को राशन नहीं मिल सका।

याचिकाकर्ता संगठन ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए हाई कोर्ट से उचित आदेश देने का आग्रह किया है। साथ ही राशन के वितरण को लेकर एक स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की। प्रशांत रावत ने बताया कि याचिका आठ जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

याचिका के अनुसार, अप्रैल 2020 में दिल्ली सरकार ने गैर राशन कार्ड धारक को खाद्यान्न और सूखा राशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की थी। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में राशन खरीदा गया, लेकिन दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पर लाभार्थियों को सूखा राशन किट और खाद्यान्न का उचित वितरण सुनिश्चित करने में विफल रहे। बाजार मूल्य पर खरीदा गया अनाज गरीबों को वितरित नहीं होने के कारण भंडारण में पड़े-पड़े बर्बाद हो गया। इतना ही नहीं वितरित न किए जाने के कारण रिफाइंड तेल, मिर्च, धनिया, हल्दी भी खराब हो गया। संगठन ने आरोप लगाया कि योजना के तहत खरीदे गए सामानों की बर्बादी के कारण न सिर्फ जनता को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि सरकारी राजस्व का भी नुकसान हुआ।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके कारण न सिर्फ लाभार्थियों को भोजन के मौलिक अधिकार से वंचित किया गया, बल्कि बिना किसी गलती के जनता पर भारी वित्तीय देनदारियों का बोझ डाल दिया गया। संगठन ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष की शिकायत के बावजूद दिल्ली सरकार ने मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की।


लोगों तक नहीं पहुंचा राशन। फाइल फोटो

यह है मामला

दैनिक जागरण ने अनाज की बर्बादी मामले का 29 मई को पर्दाफाश किया था, जिसमें कई स्कूलों में बर्बाद हो चुका अनाज मिला था। लगातार सामने आ रहे हैरान करने वाले तथ्यों को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल को नौ जून को मामले की जांच का आदेश देना पड़ा था। जांच के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों से बर्बाद हो चुके अनाज को हटा दिया था।

...तो दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक की नई आबकारी नीति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नई आबकारी नीति को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर याचिका दायर होने पर दिल्ली सरकार ने इसे सार्वजनिक कर दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि कुछ घंटे के अंदर नई आबकारी नीति को वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि अब मामले में कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है और याचिका का निपटारा किया जाता है। अदालत में दिए गए बयान के बाद दिल्ली सरकार ने नीति को वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने याचिका में वर्ष 2021-22 की नई आबकारी नीति को सार्वजनिक करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका का आधार नहीं है, क्योंकि निविदा के लिए नई नीति को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। वहीं, एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मोहन ने दलील दी कि नई नीति को मंजूरी देने के बाद भी इसे गोपनीय रखते हुए सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि निविदा भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है और नई नीति सार्वजनिक नहीं करने के कारण याचिकाकर्ता इसे भर नहीं पा रहे हैं।

विद्यार्थी नहीं तय कर सकते पेशेवर पाठ्यक्रम परीक्षा की शर्तें : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

ओपन बुक परीक्षा (ओबीई) को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने डीयू के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रम की परीक्षा की शर्तों को निर्धारित करने की अनुमति छात्रों को नहीं दी जा सकती है। इसलिए अदालत डीयू को असाइनमेंट आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए निर्देश नहीं दे सकती है। हालांकि, पीठ ने विश्वविद्यालय से परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित करने के लिए कहा है।

विधि के चार छात्रों ने इस संबंध में याचिकाएं दायर की हैं। सुनवाई के दौरान विधि संकाय की डीन प्रोफेसर वंदना ने बताया कि विचाराधीन परीक्षा के जुलाई में होने की संभावना है। पहले दौर की परीक्षा देने में असमर्थ छात्रों के लिए सितंबर में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी।

डीयू की ओर से पेश अधिवक्ता सीमा डोलो ने कहा कि बार काउंसिल आफ इंडिया ने परीक्षा आयोजन के संबंध में निर्णय संबंधित संस्थान के विवेक पर छोड़ दिया है। परीक्षा आनलाइन या आफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जाए। अंतिम वर्ष के विधि छात्र की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ सीम ने दलील दी कि पिछले साल के दूसरे और चौथे इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए आनलाइन ओपन बुक परीक्षा छात्रों के हित में नहीं थी। इसलिए असाइनमेंट आधारित परीक्षा कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि आनलाइन ओपन बुक परीक्षा की तारीखें अन्य प्रवेश परीक्षाओं के साथ टकरा सकती हैं। कोर्ट ने प्रोफेसर वंदना के आश्वासन को रिकार्ड पर लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां तक संभव होगा प्रवेश परीक्षाओं की तारीखों को ध्यान में रखकर ही डेट शीट तय की जाएगी। पीठ ने यह कहते हुए चारों याचिकाओं का निपटारा कर दिया कि जुलाई में जो छात्र परीक्षा नहीं दे सकते हैं, वे सितंबर में हिस्सा ले सकते हैं।

अहम टिप्पणी

- हाई कोर्ट का डीयू के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप से इन्कार
- ओबीई के जरिये लॉ की परीक्षा कराने को दी गई थी चुनौती



10वीं के मूल्यांकन नीति पर नौ को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट 10वीं के अंक निर्धारित करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की आंतरिक मूल्यांकन नीति को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले को 28 अगस्त के बजाय नौ जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। याचिका दायर करने वाले गैर सरकारी संगठन जस्टिस फार आल के अधिवक्ता खगेश झा ने पीठ को बताया कि यह गंभीर मामला है। अगर एक बार छात्रों के अंक अपलोड होने शुरू हो गए और परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया खत्म हो गई तो याचिका निष्फल हो जाएगी। सीबीएसई की नीति बच्चों के हित में नहीं है। इसमें संशोधन होना चाहिए। अदालत राष्ट्रीय स्वतंत्र स्कूल गठबंधन (एनआइएसए) की याचिका पर भी नौ जुलाई को सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।

बस खरीद में अनियमितता की एसीबी से कराएं जांच : भाजपा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों की खरीद को लेकर प्रदेश भाजपा ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के इस्तीफे की मांग करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से सोमवार को मुलाकात की।

आदेश गुप्ता ने कहा कि बसों की खरीद के मामले में पांच हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। एक हजार लो फ्लोर बसों की खरीद का कार्यादेश जारी होने के पांच माह बाद 11 जून को इसे अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया गया। डीटीसी की आंतरिक जांच में बसों की खरीद में अनियमितता पाई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति डीटीसी बसों की खरीद में होने वाले घोटाले की जांच का विकल्प नहीं है, इसलिए एसीबी को इसकी जांच की इजाजत दी जानी चाहिए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीटीसी चेयरमैन कैलाश गहलोत को हटाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही भाजपा ने उपराज्यपाल से शराब नीति, राशन खरीद, पानी और होम गार्ड नियुक्ति में भी हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए इनकी जांच की मांग की है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में गरीबों के लिए खरीदे गए राशन में गड़बड़ी हुई। उसे बांटना तो दूर की बात है, वह गोदामों में पड़े-पड़े सड़ गया।

मोहल्ला क्लीनिक भी पूरी तरह से बेकार हैं। कोरोना में न ही वह जांच के लिए काम आ सके और अब न ही उनमें टीकाकरण का काम हो रहा है। सिविल डिफेंस कर्मियों की भर्ती में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। कई असामाजिक तत्वों की भर्ती कर ली गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए और यह भर्ती दिल्ली पुलिस की निगरानी में कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का हाल बेहाल है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्री राजनीतिक पर्यटन पर दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं।

आरोप

- उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर गहलोत के इस्तीफे की मांग
- कहा, दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई जांच समिति नहीं है पर्याप्त

कोविड की वृद्धि के दौरान रंग–कोविड प्रणाली करेगी काम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत काम करने की योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वृद्धि के दौरान रंग प्रणाली काम करेगी। इसके लिए अभी से योजना तैयार की गई है। राजधानी में संक्रमण के मामले बढ़ते ही माल और बाजारों में आड-इवेन फार्मूला लागू किया जाएगा।

किस संकेतक में क्या होगी तैयारी

पीलाः यदि संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 फीसद से अधिक बनी रहती है या एक सप्ताह तक 1,500 कोरोना के नए मामले आते हैं या फिर अस्पतालों में 500 आक्सीजन बेड औसतन एक सप्ताह तक के लिए भरे रहते हैं तो यह अलर्ट प्रभावी रहेगा।

प्रतिबंधः इस दौरान बाजारों और माल में गैर-जरूरी सामान और सेवाओं वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आड-इवेन फार्मूले के अनुसार खोलने की अनुमति होगी। जबकि नगर निगम क्षेत्र में विक्रेताओं की आधी क्षमता पर एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी। निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने की अनुमति होगी।

अंबर (पीला-नारंगी मिश्रित) : यदि संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक एक फीसद से अधिक रहती है या एक सप्ताह में 3,500 नए मामले आते हैं या फिर एक सप्ताह के दौरान औसत 700 से अधिक आक्सीजन बेड भरे रहते हैं तो यह अलर्ट लागू होगा।

प्रतिबंध: निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। बाजारों और माल में दुकानों को आड इवेन के तहत सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोला जा सकेगा।

नारंगी: अगर लगातार दो दिनों तक कोरोना संक्रमण की दर दो फीसद से अधिक बनी रहती है या एक सप्ताह के दौरान 9,000 नए मामले दर्ज होते हैं या फिर अस्पताल में औसतन 1000 आक्सीजन बेड लगातार सात दिनों तक भरे रहते हैं तो यह अलर्ट लागू होगा।

प्रतिबंध: किराना, दूध व केमिस्ट जैसे आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी माल और बाजार बंद रहेंगे। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, बसों को केवल आवश्यक गतिविधियों में लगे यात्रियों के साथ 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।

लालः संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक पांच फीसद से अधिक हो रहती है या या फिर अस्पतालों में औसतन 3000 आक्सीजन बेड एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक भरे रहते है तो यह संकेत प्रभावी होगा।

प्रतिबंध: निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।


राजधानी में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तो गिर रहा है मगर वही लापरवाही तेजी से बढ़ रही है। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में ऐसी भीड़ जहां शारीरिक दूरी की धज्जियां व औपचारिकता के लिए मास्क लगाकर घूमते लोगों को देखकर लगता है कि तीसरी लहर जल्द ही आने वाली है अगर लोग नहीं चेते तो। संजय

कोरोना नियमों के उल्लंघन पर लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट को किया बंद

जासं, दक्षिणी दिल्ली : कोरोना दिशानिर्देशों का पालन न करने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर पांच दुकानों को सील भी किया गया है। दरअसल, कोरोना दिशानिर्देशों का पालन कराने के लिए डीडीएमए (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)की ओर से बनाई गई टास्क फोर्स ने मार्केट का निरीक्षण किया तो यहां कई तरह के उल्लंघन पाए गए। टीम ने पाया कि पूरी मार्केट में शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। वहीं, खाने-पीने का सामान बेचने वाले भी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे। मार्केट में जगह-जगह थूक के दाग मिले और कई लोग बिना मास्क के भी मार्केट में नजर आए। बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाए जाने के बाद प्रशासन ने मार्केट को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। हालांकि, सोमवार को इस मार्केट की साप्ताहिक बंदी रहती है। इस कारण ज्यादातर दुकानें वैसे भी बंद रहती हैं। लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट शापकीपर्स एसोसिएशन के महासचिव राकेश नारंग ने बताया कि मार्केट में एक हजार दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि सुबह 10 से रात आठ बजे तक दुकानें खुलने का समय है, लेकिन अगर दुकान में ग्राहक आ जाएं तो उन्हें दुकान से भगाया तो नहीं जा सकता।

वकील का हंगामा, कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई से किया इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : गत वर्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार छात्रा गुलफिशा फातिमा के अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा हंगामा करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने कहा कि तथ्यों का सहारा लेने के बजाय प्राचा हंगामे का सहारा ले रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति की दलील नहीं सुनेंगे जिसे कानून के मूल की जानकारी न हो। पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए याचिका किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

फातिमा ने दिल्ली दंगा मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता अमित महाजन ने कहा कि फातिमा के भाई की इसी संबंध में दायर याचिका बीते वर्ष हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, ऐसे में फातिमा की याचिका का कोई आधार नहीं है। इस पर महमूद प्राचा ने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका हाई कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के आधार पर ही वापस ली गई थी। प्राचा ने रिमांड आर्डर के संबंध में उनका बयान रिकार्ड पर लेने की भी मांग की। इस पर पीठ ने कहा कि यह उनकी याचिका का हिस्सा नहीं है।

निजी अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : कोरोनारोधी टीकाकरण में फर्जीवाड़ा करने पर गुरुग्राम सिविल सर्जन ने गांव झाड़सा रोड स्थित चिरंजीव अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। कुछ लोगों ने सिविल सर्जन कार्यालय में शिकायत की थी कि अस्पताल में पैसे लेकर सरकारी केंद्र पर टीका लगवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच में शिकायत को सही पाया।

सिविल सर्जन डाक्टर विरेंद्र यादव ने बताया कि 30 अप्रैल तक निजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन उपलब्ध कराता था। सरकार से आदेश आए कि अब निजी अस्पताल स्वयं वैक्सीन खरीदकर टीकाकरण करेंगे। इसी संबंध में निजी अस्पतालों को आदेश दिए गए थे कि 30 अप्रैल तक सभी टीका लगाकर डाटा स्वास्थ्य विभाग में जमा करा दे।

अधिवक्ता पैनल मामले पर एलजी से फिर टकराव के आसार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों के साथ हुई झड़प के मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को सही ठहराया है। उनके इस कदम से दिल्ली सरकार व एलजी के बीच फिर टकराव की संभावना बन गई है।

सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ एक जुलाई की बैठक में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित वकीलों के पैनल को नहीं रखे जाने पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। जैन ने दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए विशेष लोक अभियोजक के पैनल को अनुमति नहीं दी थी। उपराज्यपाल ने दो जुलाई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि वकीलों के पैनल की नियुक्ति पर मंत्रिमंडल एक सप्ताह में निर्णय ले और उन्हें अवगत कराए।

उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि 26 जनवरी को किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली उग्र हो गई थी, जिसमें 394 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। इससे संबंधित 48 एफआइआर दर्ज की गईं हैं। अब इन मामलों के ट्रायल के लिए दिल्ली पुलिस ने ग्यारह वकीलों को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है व दिल्ली सरकार के कानून विभाग से पैनल नियुक्ति पर अनुमति मांगी। उन्होंने लिखा है कि फाइल जब गृह विभाग से मंगवाई गई तो पाया कि गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त पैनल को अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।

कोरोना संक्रमण के चलते डीयू में डूटा चुनाव टला

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के चुनाव प्रत्येक दो साल बाद होते हैं। इस साल अगस्त महीने में चुनाव प्रस्तावित था। लेकिन कोरोना संक्रमण से उपजी परिस्थितियों के चलते डीयू ने चुनाव टाल दिया है। डूटा कार्यकारिणी की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया है। 1975 में लगे आपात काल और 1987 में शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बाद ऐसा तीसरी बार है जब डीयू शिक्षक संघ चुनाव टाला जा रहा है।

डूटा ने बताया कि शिक्षक संघ चुनाव में दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कालेजों के शिक्षक हिस्सा लेते हैं। चुनाव के बाद अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी चुने जाते हैं। डूटा कार्यकारिणी की बैठक अब सात अगस्त को एक बार फिर होगी। जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर चुनाव का निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली समेत उत्तर भारत के शेष भागों में 10 तक पहुंचेगा मानसून

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की राजधानी और उत्तर भारत के शेष भागों का मानसून को लेकर इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा अब इन क्षेत्रों तक 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। पहले आठ जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना जताई गई थी। नवीनतम गणितीय मौसम पूर्वानुमान माडल के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिमी तट और उससे सटे पूर्व-मध्य भारत समेत दक्षिण प्रायद्वीप के क्षेत्रों में आठ जुलाई से सक्रिय होने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने कहा है कि 11 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह क्षेत्र ओडिशा के तट से दक्षिण और आंध्र प्रदेश के तट से उत्तर में हैं। अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर पर चलने वाली नम पूर्वी हवाएं आठ जुलाई से पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में धीरे-धीरे मजबूत होंगी। इसके 10 जुलाई तक पंजाब और उत्तरी हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत तक फैलने की संभावना है।

आइएमडी ने कहा, इसके मुताबिक ही दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने और 10 जुलाई तक इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और भागों और दिल्ली के आसपास इलाकों तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके चलते उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 10 जुलाई से बारिश की संभावना बन रही है।

बता दें कि जून के पहले ढाई हफ्ते में अच्छी मानसूनी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भीषण गर्मी हो पड़ रही है। हालांकि, आइएमडी ने जुलाई में इन इलाकों में भारी बरसात का पूर्वानुमान व्यक्त किया था। एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने कहा था कि अभी इन इलाकों में सात जुलाई तक बारिश के अनुकूल माहौल नहीं बन रहा है।

- आइएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीप में आठ जुलाई से होगा सक्रिय
- बंगाल की खाड़ी में पश्चिम-मध्य और उससे सटे पश्चिम उत्तर क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना

प्रदूषण

बदलती नीतियों के बीच दिल्ली में प्रदूषण के नए स्रोत भी आ रहे सामने आइआइटी कानपुर ने किया नया पहला रियल टाइम मानीटरिंग अध्ययन

खाना बनाने के तौर–तरीके भी हवा को कर रहे दूषित

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

जानकर हैरानी भले ही हो, लेकिन हवा में प्रदूषण चूल्हा या तंदूर जलाने से ही नहीं होता बल्कि एलपीजी गैस से भी होता है। वजह, खाना बनाने के तौर तरीके। जब भी दाल-सब्जी में तड़का लगाया जाता है या फिर कुछ तला जाता है तो कढ़ाई या फ्राईपैन में धुंआ भी उठता है और कई बार आग की लपटें भी उठ जाती हैं। यह भी प्रदूषण ही है जिससे बचने के लिए लोग चिमनी या एग्जास्ट फैन लगाते हैं। यह जानकारी आइआइटी कानपुर के नए अध्ययन में सामने आई है। यह राजधानी में पहला वास्तविक समय प्रदूषण स्रोत विभाजन अध्ययन है। 'ग्रीष्मकाल के दौरान दिल्ली में कार्बनिक और तत्वों सहित सूक्ष्म कणों के वास्तविक समय की मात्रा का ठहराव और स्रोत विभाजन' शीर्षक वाले इस अध्ययन में राजधानी में प्रदूषण के कुछ प्रमुख स्रोत के रूप में दहन, वाहनों का उत्सर्जन, कचरा जलाना और खाना बनाना भी शामिल है।

इस अध्ययन के तहत पीएम 2.5 को एक इकाई मानने के बजाय शोधकर्ताओं ने इसे कई उप-श्रेणियों में बांट दिया, जिसमें कार्बनिक एरोसोल, ब्लैक कार्बन, सल्फेट्स, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरीन और नाइट्रेट शामिल हैं। इससे कुल प्रदूषण मिश्रण में हर स्रोत के अनुपात को सटीक रूप से निर्धारित करने में मदद मिली। अध्ययन बताता है कि शहर के कार्बनिक एरोसोल में कार्बनिक पदार्थों के दहन से निकलने वाले प्रदूषक की हिस्सेदारी 64 फीसद तक रही। जून और जुलाई के दौरान 27 फीसद प्रदूषक तत्व बिजली संयंत्र उत्सर्जन और औद्योगिक अपशिष्ट जलने से निकलने वाले धुएं में निलंबित धातु के कण थे। अध्ययन से पता चला है कि गर्मियों के दौरान दिल्ली की हवा में कार्बनिक एरोसोल बढ़ाने में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का 12.3 फीसद, ठोस ईंधन में खाना पकाने (घर में और खुले में दोनों जगह) का 16.2 फीसद, तत्व या धातु ज्यादातर धूल का 52.5 फीसद, बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन का 16.2 फीसद, कचरा जलाने और इस्पात उद्योगों के उत्सर्जन का 10.7 फीसद, ठोस ईंधन दहन का 10.5 फीसद, औद्योगिक अपशिष्ट का 1.5 फीसद और धातु प्रसंस्करण उद्योगों के उत्सर्जन का 1.4 फीसद योगदान रहा।

अध्ययन ने उन विभिन्न क्षेत्रों को भी चिह्नित किया है जहां से प्रदूषक राजधानी में आते हैं, ताकि स्थानीय स्रोतों और शहर के बाहर स्थित स्रोतों से प्रदूषण की हिस्सेदारी को समझा जा सके। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान में स्थित छोटी और मध्यम धातु प्रसंस्करण इकाइयां दिल्ली के पीएम 2.5 स्तर में क्लोरीन की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसी तरह पीएम 2.5 में क्रिस्टल तत्वों (जैसे एल्युमीनियम, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन) का उच्च योगदान गर्मियों के दौरान राजस्थान के रेगिस्तान से क्षेत्र में धूल भरी आंधी की उच्च तीव्रता के कारण देखा गया था।


प्रदूषण का यह भी एक कारण। फाइल फोटो

दिल्ली के प्रदूषण ग्राफ की पूरी तस्वीर प्राप्त करने के लिए इस अध्ययन को पहले के स्रोत विभाजन अध्ययन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इससे सरकारी एजेंसियों- नीति निर्माताओं को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि शमन के किन कदमों से मदद मिली है और अब क्या करने की जरूरत है।
- प्रोफेसर एसएन त्रिपाठी, विभाग प्रमुख (सिविल इंजीनियरिंग), आइआइटी-कानपुर

फेज चार के मेट्रो कारिडोर पर लांचर से चढ़ाए जा रहे यू–गार्डर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने फेज चार के एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण के लिए अत्याधुनिक लांचर का इस्तेमाल शुरू किया है। इस लांचर की मदद से सोमवार को जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो लाइन पर मुकरबा चौक से अशोक विहार के बीच 9.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेट कारिडोर के निर्माण के लिए पिलरों पर यू-गार्डर चढ़ाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह भी मौजूद थे। इस लांचर की मदद से कारिडोर का निर्माण जल्दी पूरा हो सकेगा। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर यातायात भी प्रभावित नहीं होगा।

डीएमआरसी का कहना है कि देश में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले यू-गर्डर चढ़ाने के लिए बड़े क्रेन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी क्षमता 350 से 400 टन की होती है। यू-गार्डरों की लंबाई करीब 28 मीटर होती है इसलिए इसे 42 मीटर लंबे ट्रेलर पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। इस वजह से सड़क पर यातायात प्रभावित होने की संभावना रहती है।


जनकपुरी पश्चिम -आर के आश्रम मार्ग मेट्रो लाइन के कॉरिडोर के निर्माण के लिए मजलिस पार्क के नजदीक पिलर पर यू-गार्डर चढ़ाते हुए ट्रांसपोर्टर युक्त लांचर। सौ.डीएमआरसी

100 करोड़ से ज्यादा वसूली के आरोप में सीबीआइ जांच का सामना कर रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख। उन्होंने ईडी द्वारा कानून का पालन न करने और जांच में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया है।

'भारत ड्रोन हमले का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम'

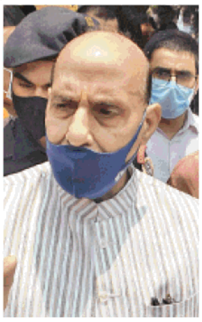
जागरण टीम, कानपुर

- संघ प्रमुख के बयान का समर्थन कर राजनाथ बोले- इंसान और इंसानियत हमारी राजनीति का आधार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश की हर नापाक हरकत, चुनौती और तकनीक का जवाब देने में भारतीय सेना सक्षम है। हम ड्रोन हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। हम एक ऐसी प्रणाली तैयार कर रहे हैं, जिससे सीमा पर ही आने वाले ड्रोन को रोका जा सकेगा और उसकी निगरानी भी की जा सकेगी। इतना ही नहीं, इस प्रणाली से हम सीमा पार होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। देश आश्वस्त रहे कि सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

सोमवार को रक्षा मंत्री उप्र के कानपुर के श्यामनगर में स्थित हरिहर धाम में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने यहां अपनी गुरुमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की और गुरु जी को सांत्वना दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक मोहन भागवत के 'सभी भारतीयों का डीएनए एक है' बयान का समर्थन कर उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख ने सच कहा है। भाजपा ने कभी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसान और इंसानियत ही हमारी राजनीति का आधार है। मतांतरण के मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, फिर चाहे कोई भी हों। कुछ लोग भय की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पर रक्षा मंत्री बोले- सेना अलर्ट है। इतना ही कहूंगा कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चेहरे पर रक्षा मंत्री ने कहा कि यह तो पहले से तय है। उनका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर था। बोले, वह मुख्यमंत्री हैं।

इससे पहले लखनऊ से कानपुर आते समय उन्होंने उन्नाव के नवाबगंज स्थित वन विभाग के निरीक्षण भवन में पत्रकारों से कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पार्टी की सफलता यह बताती है कि जनता का भाजपा पर विश्वास बढ़ा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश के लोगों की सेवा में लगे हैं। प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खुद को सुरक्षित महसूस करती है। इसलिए जनता का प्यार भाजपा को मिलता है।


कानपुर में श्याम नगर स्थित हरिहर धाम में गुरु संतोष द्विवेदी से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जागरण

'अटल टनल बनने से सुरक्षित हुईं देश की सरहदें'

जागरण संवाददाता, मनाली

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बनाई गई अटल टनल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इसका निर्माण होने से देश की सरहदें सुरक्षित हुई हैं। चीन व पाकिस्तान से लगती सीमाओं तक पहुंच आसान हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का निर्माण करवाकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार किया है। उन्होंने सोमवार को अटल टनल को निहारने के बाद साउथ पोर्टल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह टनल देश की सुरक्षा में मजबूती का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अटल जी का सपना था कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसी ही टनल बने, जो बन चुकी है। संयुक्त प्रगतशील गठबंधन(यूपीए) सरकार ने टनल के काम को लंबा खींचा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही तेजी से इस काम को पूरा किया गया। यह टनल लाहुल स्पीति के लिए वरदान साबित हुई है। जनजातीय जिला अब सालभर देश से जुड़ गया है। अटल टनल बनने से मनाली और लाहुल-स्पीति में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। प्रत्येक दिन छह से आठ हजार वाहन अटल टनल से गुजर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अटल टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी साथ रहे। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के चीफ इंजीनियर वीके सिंह ने टनल की खूबियों से अवगत कराया। नड्डा ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर किए। बीआरओ के कार्य को सराहा। अटल टनल निहारते हुए नड्डा टनल के नार्थ पोर्टल यानी जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति पहुंचे। नड्डा सोमवार को कुल्लू जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हेलीकाप्टर से मनाली के सासे हेलीपैड पहुंचे।


भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुल्लू में 103 वर्षीय बुआ गंगा देवी के घर पहुंचे। इस मौके पर गंगा देवी ने नड्डा की आरती उतार कर तिलक किया और आशीर्वाद स्वरूप 500 रुपये भी दिए। जागरण

तिलक लगा भतीजे का स्वागत, 500 रुपये दिया शगुन : दो साल से भतीजे की राह देख रही 103 वर्षीय बुआ गंगा देवी ने जेपी नड्डा के घर पहुंचने पर तिलक लगाकर गायत्री मंत्रोच्चारण और आशीर्वाद स्वरूप 500 रुपये देकर स्वागत किया। जेपी नड्डा ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। भतीजे को देख बुआ काफी खुश थीं। इस दौरान नड्डा ने बुआ द्वारा बनवाए सिड्डू (कुल्लू का स्थानीय व्यंजन) खाया। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी जेपी नड्डा की बुआ के पांव छूकर आशीर्वाद लिया।

पेट्रोल–डीजल की कीमत को लेकर ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी

राब्यू, कोलकाता : पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने मांग की है कि केंद्र की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लिया जाता है, उसको कम किया जाए। इसके साथ ही ममता ने पीएम मोदी से अपील की है कि देश में महंगाई का जो ट्रेंड है, उसको देखें। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत सौ के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। इस बढ़ोतरी से आम लोग परेशान हैं।

वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजाति समुदायों को मिलेंगे और अधिकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय पर्यावरण व जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजाति समुदायों को और अधिकार देने का फैसला किया है। इसे लेकर मंगलवार को इंदिरा पर्यावरण भवन में साझा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह पहल अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) कानून 2006, के प्रभावी अनुपालन के लिए की जा रही है। इसे सामान्य रूप से वन अधिकार कानून भी कहा जाता है। यह कानून जंगल में रहने वाले अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक समुदायों को वन भूमि पर आजीविका का अधिकार देता है।

महाराष्ट्र में एक साल के लिए निलंबित किए गए भाजपा के 12 विधायक

टकराव ▶ विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष ने दुर्व्यवहार के आरोप में की कार्रवाई

फड़नवीस ने पार्टी के विधायकों पर लगे आरोप को गलत बताया

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले ही दिन सोमवार को कार्यवाहक अध्यक्ष से दुर्व्यवहार के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने अपनी पार्टी के विधायकों पर लगे आरोप को गलत बताया है। निलंबित विधायकों ने अपने निलंबन के खिलाफ राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया है।

सिर्फ दो दिन के लिए बुलाए गए मानसून सत्र के पहले ही दिन राकांपा नेता एवं राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। महाविकास अघाड़ी यह मांग इसलिए कर रही है, ताकि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी आबादी का डाटा तैयार करने में मदद की जा सके और स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण बहाल कराया जा सके। भुजबल द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के दौरान भाजपा के विधायक ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनाव में राजनीतिक आरक्षण देने की मांग पर ही हंगामा कर रहे थे। इस हंगामे के दौरान ही यह प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करा लिया गया। इससे चिढ़े विपक्षी विधायकों ने अध्यक्ष के आसन के सामने जाकर हंगामा एवं नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर कार्यवाहक अध्यक्ष भास्कर जाधव सदन स्थगित कर अपने कक्ष में चले गए। इसके बाद भाजपा के कुछ सदस्य अध्यक्ष में केबिन में पहुंचे और उन पर बोलने का समय नहीं देने का आरोप लगाने लगे। जब सदन की कार्यवाही पुनः शुरू हुई तो जाधव ने सदन को बताया कि भाजपा सदस्यों ने केबिन में आकर उनके साथ दुर्व्यवहार एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। जाधव ने संसदीय मामलों के मंत्री से इस मामले की जांच करने को भी कहा और अपने केबिन में गए 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया। भास्कर जाधव के अनुसार जब भाजपा विधायक उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे।


महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित 12 भाजपा विधायकों ने सोमवार को मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। एएनआइ

दूसरी तरफ, फड़नवीस का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे हैं। एक कहानी गढ़ी जा रही है। भाजपा की ओर से किसी ने अध्यक्ष से अमर्यादित भाषा में बात नहीं की। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए हम 12 तो क्या, इससे ज्यादा विधायकों के बलिदान को तैयार हैं। निलंबित हुए विधायकों में मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आशीष शेलार भी हैं, जिनकी दो दिन पहले शिवसेना नेता संजय राउत से गुप्त मुलाकात की चर्चा गरम थी। शेलार ने विधायकों के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस सरकार ने तो तालिबान को भी शर्मिंदा कर दिया है। अध्यक्ष के चैंबर में शिवसेना विधायकों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। फिर भी हमने अध्यक्ष की मर्यादा का ख्याल रखते हुए माफी मांग ली। शिवसेना के लोगों में मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं सिर्फ छगन भुजबल द्वारा प्रधानमंत्री को लेकर कही गई बातों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था।

राफेल पर राहुल का वार जारी, कहा–नहीं दबाया जा सकता सच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने फ्रांस में शुरू हुई न्यायिक जांच के बाद भी सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल
- कहा, करार की संयुक्त संसदीय समिति से जांच के अलावा कोई रास्ता नहीं

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल लड़ाकू विमान सौदे की फ्रांस में शुरू हुई न्यायिक जांच के मद्देनजर भारत में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से इसकी जांच की मांग को लेकर अपना सियासी अभियान जारी रखे हैं। सोमवार को उन्होंने ट्वीट किया कि सच को दबाया नहीं जा सकता। वहीं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने भी कहा कि फ्रांस में शुरू हुई जांच से प्रथम दृष्टया अनियमितता का संदेह साफ है और सरकार के पास जेपीसी जांच कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बयान जारी करते हुए एंटनी ने कहा कि फ्रांस में शुरू हुई जांच के 48 घंटे बाद भी मोदी सरकार की चुप्पी यह संकेत दे रही कि सरकार भ्रष्टाचार के इस मामले को रफा-दफा करना चाहती है। साथ ही मामले की जांच करा दोषियों को दंडित करने से सरकार का इन्कार भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। एंटनी ने कहा कि आज तक प्रधानमंत्री या सरकार ने यह नहीं बताया है कि 126 की जगह अचानक केवल 36 राफेल जेट खरीदने का फैसला क्यों लिया गया, और टेक्नोलाजी ट्रांसफर का बलिदान क्यों किया गया? इतना ही नहीं राफेल जेट की कीमत बढ़ाए जाने का तर्कसंगत जवाब भी सरकार ने नहीं दिया है। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को सौदे से बाहर करने और रक्षा खरीद परिषद से मंजूरी मिले बिना प्रधानमंत्री की ओर से एकतरफा नए सौदे की घोषणा को लेकर भी पूर्व रक्षा मंत्री ने सवाल उठाया।


किया हमला : राहुल गांधी। जागरण आर्काइव

एंटनी ने कहा कि ताजा घटनाओं और सामने आए दस्तावेज से साफ है कि राफेल सौदे में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की कांग्रेस की बातें सही साबित हो रही हैं।

जन प्रतिनिधियों के उद्दंड व्यवहार का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

जताई चिंता
- कहा, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसे आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
- केरल विधानसभा में हुए हंगामे से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की यह टिप्पणी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसने संसद और विधानसभाओं में जन प्रतिनिधियों के उद्दंड व्यवहार का कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस तरह के आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने 2015 में केरल विधानसभा में हुए हंगामे के सिलसिले में दर्ज एक आपराधिक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह घटना राज्य में पिछली कांग्रेस नीत यूडीएफ शासन के दौरान हुई थी। न्यायालय ने कहा कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सदन में शिष्टाचार बना रहे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने केरल विधानसभा की घटना का जिक्र करते हुए कहा, प्रथम दृष्टया हमें इस तरह के व्यवहार का कड़ा संज्ञान लेना होगा। इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है।

पीठ ने कहा, हमें अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ शिष्टाचार बना रहे। इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। संसद में भी यह हो रहा है और इसके खिलाफ सख्ती बरतनी होगी। इस मामले में केरल सरकार ने एक याचिका के जरिये हाई कोर्ट के 12 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। इसमें राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी गई थी, जो राज्य विधानसभा के अंदर 2015 में हुए हंगामे से जुड़े एक आपराधिक मामले को निरस्त करने के लिए थी।

यह है मामला : केरल विधानसभा में 13 मार्च, 2015 को अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला था। उस वक्त विपक्ष में मौजूद एलडीएफ विधायकों ने तत्कालीन वित्त मंत्री केएम मणि को बजट पेश करने से रोकने की कोशिश की थी, जो बार रिश्वत कांड में आरोपों का सामना कर रहे थे।

देशमुख ही नहीं, पूरे मामले की जांच सीबीआइ की जिम्मेदारी

सख्त हिदायत
- बांबे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से मांगी जांच की प्रगति रिपोर्ट
- हर महीने 100 करोड़ की वसूली के आरोप की जांच कर रही सीबीआइ

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह सीबीआइ का कर्तव्य है कि वह न केवल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की, बल्कि उनसे जुड़े मामले में कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोगों की जांच करे। उसी के साथ अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता के खिलाफ चल रही जांच की प्रगति के बारे में भी बताने को कहा।

जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जामदार की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से पूछा कि अप्रैल में देशमुख के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच कितनी आगे बढ़ी है। पीठ ने कहा कि जांच की प्रगति क्या है। हम एक सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट देखना चाहते हैं।

पीठ राकांपा नेता द्वारा, 24 अप्रैल को भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में सीबीआइ द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच का आदेश दिए जाने के बाद देशमुख ने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआइ जांच एक वकील द्वारा मुंबई पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत पर हो रही है। इसमें मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनके खिलाफ जांच का अनुरोध किया गया।


अहम मामला : बांबे हाई कोर्ट। फाइल/इंटरनेट मीडिया

जब देशमुख की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई सोमवार को बहस कर रहे थे तो पीठ ने सवाल किया कि क्या इस स्तर पर जब जांच अभी भी चल रही है, तब अदालत को मामले को रद करने की याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रारंभिक जांच शुरू की गई और प्राथमिकी दर्ज की गई। सीबीआइ की यह जिम्मेदारी है कि वह इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करे। केवल याचिकाकर्ता (देशमुख) की ही नहीं। इसमें वे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो उस समिति में थे जिसने सचिन वाझे (पुलिसकर्मी) को बहाल किया था। वाझे इस समय अंटीलिया के पास गाड़ी में मिले विस्फोटक और ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में जेल में बंद है। आरोप है कि देशमुख ने वाझे को मुंबई के बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। वाझे को इन दोनों मामलों में गिरफ्तारी के बाद मई में पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पीठ ने हाई कोर्ट ने प्रशासन में जनता का विश्वास पैदा करने के लिए पांच अप्रैल के अपने आदेश में सीबीआइ को प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया था। पीठ ने सीबीआइ से यह भी जानना चाहा कि प्राथमिकी के आरोपी कालम में शामिल 'अज्ञात' व्यक्ति कौन थे। अदालत ने कहा कि चोरी और लूट के मामलों में आरोपी कालम में अमूमन अज्ञात व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। सीबीआइ की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अमन लेखी ने हाई कोर्ट से कहा कि वे अगली तारीख पर इन बिंदुओं पर अदालत को अवगत कराएंगे। अदालत इस मामले में सात जुलाई को आगे की सुनवाई करेगी।

पूछताछ के लिए देशमुख ईडी के समक्ष तीसरी बार भी नहीं आए

मुंबई, आइएएनएस : हर महीने 100 करोड़ से ज्यादा वसूली के आरोप में सीबीआइ जांच का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख लगातार तीसरी बार पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कानून का पालन न करने और जांच में पारदर्शिता न होने का आरोप लगाया है। इस मामले में वे अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। देशमुख ने सोमवार को ईडी मुंबई के सहायक निदेशक तस्सीन सुल्तान को लिखे एक पत्र में कहा कि वे मौजूदा समय में चल रही जांच में हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं लेकिन जिस तरह से ईडी जांच कर रही है उससे यह धारणा मजबूत हो रही कि जांच निष्पक्ष और भेदभाव रहित नहीं है।

टूलकिट की जांच करने की मांग वाली याचिका पर विचार नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए कथित तौर पर बनाई गई टूलकिट की प्रारंभिक जांच का अनुरोध करने वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इन्कार कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, यदि आप टूलकिट को पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे नजरअंदाज कर दीजिए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील शशांक शेखर झा से कहा, यह राजनीतिक दुष्प्रचार का हिस्सा है और यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो इसे नजरअंदाज करें। झा ने कथित टूलकिट का जिक्र करते हुए कहा कि (कोरोना के) भारतीय स्वरूप जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, भारत एक लोकतंत्र है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में इस तरह की राहत नहीं दी जा सकती। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, हमें अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में निर्देश क्यों जारी करना चाहिए?

खत्म होगा इंतजार

एनटीए ने मंत्रालय को सौंपा प्लान, जुलाई और अगस्त में ही इन सभी परीक्षाओं को कराने की तैयारी

जेईई मेन और नीट का एलान इसी हफ्ते होगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले से जुड़ी जेईई (ज्वाइंट एंट्रेंस एक्जाम) मेन व एनईईटी (नेशनल एलिजबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट-नीट) परीक्षाओं को लेकर छात्रों को अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। इसी हफ्ते में इनकी तारीखों का भी एलान कर दिया जाएगा। फिलहाल जुलाई और अगस्त में ही इन सभी परीक्षाओं को कराने की तैयारी है।

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो एनटीए ने जेईई मेन और नीट परीक्षा के आयोजन की पूरी योजना शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। जिसकी मंजूरी के बाद इसका एलान कर दिया जाएगा। हालांकि इन परीक्षाओं की शुरुआत जुलाई के अंतिम हफ्ते से होगी। जिसमें जेईई मेन के बचे दो सत्रों में से एक सत्र की परीक्षा कराने की योजना बनाई गई है।

एनटीए ने यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ी रफ्तार को देखते हुए बनाई है। साथ ही संक्रमण की किसी नई लहर के आने से पहले इसे पूरा भी कर लेना चाहती है। सूत्रों की माने तो लंबे मंथन के बाद परीक्षाओं के इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। जिसमें विशेषज्ञों की भी राय ली गई है। हालांकि इस पर अभी शिक्षा मंत्रालय और पीएमओ की मंजूरी मिलना बाकी है।

सूत्रों की मानें तो परीक्षाओं को ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। पंद्रह दिन की पूर्व सूचना के आधार पर ही इन परीक्षाओं को कराने की तैयारी है। वैसे भी मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को स्थगित करते समय यह साफ कहा था, कि इन परीक्षाओं को स्थिति सामान्य होने पर कभी भी पंद्रह की नोटिस पर कराया जाएगा। वैसे भी कोरोना की अगली लहर के बारे मैं जैसी आशंका जताई जा रही है उसे देखते हुए ये परीक्षाएं जल्द कराना ही उपयुक्त होगा।

स्कूलों में बच्चों को संख्या ज्ञान में शुरू से ही निपुण बनाने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्कूली बच्चों को अब प्री-प्राइमरी से ही संख्या ज्ञान और मूलभूत साक्षरता में दक्ष बनाया जाएगा, ताकि आगे की पढ़ाई में उन्हें कोई दिक्कत न महसूस हो। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर निपुण भारत नाम से एक राष्ट्रीय मुहिम शुरू की है, जिसमें बच्चों को प्री-प्राइमरी से तीसरी कक्षा तक मूलभूत शिक्षा से जोड़ा जाएगा। साथ ही समय-समय पर इसका मूल्यांकन भी किया जाएगा।

फिलहाल इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 तक देश भर के स्कूलों में प्री-प्राइमरी से तीसरी कक्षा तक में बच्चों को संख्या ज्ञान और मूलभूत साक्षरता में निपुण बनाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को इस योजना को शुरू किया। इस योजना में प्री-स्कूल से लेकर कक्षा तीन तक के तीन से नौ वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पर फोकस किया जाएगा व कक्षा चार और पांच के उन बच्चों को भी अतिरिक्त शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, जिन्हें इस मिशन के तहत निपुण नहीं किया गया है। इस मौके पर निशंक ने कहा कि साक्षरता व संख्यात्मक कौशल की अच्छी बुनियाद बच्चों की आगे की पढ़ाई में सकारात्मक प्रभाव डालती है और शिक्षा के प्रति बच्चे में रुचि भी विकसित करती है। साक्षरता व संख्या ज्ञान का सीधा प्रभाव व्यस्कों की आय व अगली पीढ़ी के लिए बेहतर स्वास्थ्य जैसे उनके भावी जीवन के परिणामों पर पड़ता है। इस पूरी योजना पर वर्ष 2021-22 में करीब 2,130 करोड़ खर्च किया जाएगा।

कह के रहेंगे माधव जोशी



21 पुरानी लोजपा पर वर्चस्व की लड़ाई उसके संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर एकबार फिर सड़कों पर आ गई। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस गुट ने इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 6 जुलाई, 2021

सियासी सोप-ओपेरा बन गया है राज्यों में कांग्रेस का झगड़ा

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कांग्रेस में पंजाब का झगड़ा अभी सुलझा भी नहीं है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में पार्टी की उठापटक खुलेआम सड़क पर आ गई है। अंदरूनी गुटबाजी और उठापटक की कांग्रेस की यह सोप ओपेरा केवल पंजाब-हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान से कर्नाटक और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टी हाईकमान को हलकान कर रहा है। सोप ओपेरा दरअसल टीवी पर चलने वाले लंबे धारावाहिकों को कहते हैं।

चौतरफा असंतोष, उठापटक और गुटबाजी से पार्टी की बढ़ रही चुनौतियों का हल निकालने के लिए हाईकमान ने बैठकों के दौर तेज कर दिए हैं मगर राज्यों में जारी कांग्रेस के संकट का समाधान अभी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मंगलवार को अहम मुलाकात अभी प्रस्तावित ही है कि सोमवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक 21 विधायकों ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सैलजा को हटाने का दबाव बढ़ा दिया है।


कैप्टन अमरिंदर सिंह


नवजोत सिंह सिद्धू


भूपेंद्र सिंह हुड्डा।


सैलजा

ढीली होती पकड़

- पंजाब के बाद अब सड़क पर आई हरियाणा कांग्रेस की उठापटक
- सैलजा को हटाने को वेणुगोपाल से मिले हुड्डा समर्थक 21 विधायक
- कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान में भी हो रही है मजे की किचकिच
- सिद्धू के मसले पर आज सोनिया गांधी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर

राज्यों में शुरू हो रहा घमासान सीधे कांग्रेस नेतृत्व के सियासी इकबाल को चुनौती है। खासकर इसलिए कि प्रदेश अध्यक्ष सैलजा कांग्रेस हाईकमान की करीबी हैं और सोनिया गांधी से उनकी निजी निकटता सार्वजनिक है। इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को दिल्ली में अपने समर्थक 21 विधायकों के साथ सैलजा को हटाने के लिए खुली बैठक की और फिर उसके बाद इन विधायकों को केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए भेज दिया। जाहिर तौर पर विधायकों ने सैलजा को हटाकर हरियाणा कांग्रेस की कमान हुड्डा को सौंपने की मांग करते हुए अपने तेवर भी दिखाए।

हरियाणा कांग्रेस की इस सिरदर्दी के बीच कांग्रेस नेतृत्व अब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के झगड़े का अंतिम समाधान निकालने के लिए बेचैन है। इस लिहाज से सोनिया गांधी और कैप्टन के बीच मंगलवार को होने वाली मुलाकात संकट के पटाक्षेप का रास्ता निकाल सकती है। इसमें सिद्धू की वापसी के फार्मूले पर हाईकमान कैप्टन को राजी करेगा। सिद्धू पहले ही हाईकमान से चर्चा कर चुके हैं और पिछले हफ्ते उनकी राहुल और प्रियंका से लंबी मुलाकातें हुई थीं। इन मुलाकातों में सुलह का रास्ता निकलने के संकेत दिए गए थे। इसके बावजूद पंजाब के बिजली संकट के बहाने सिद्धू ने कैप्टन पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा।

गुजरात कांग्रेस में भी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर खींचतान लंबे समय से चल रही है। भरत सोलंकी एक बार फिर सूबे की कमान थामने के लिए प्रबल दावेदार के रूप में पेशबंदी कर रहे हैं तो शक्ति सिंह गोहिल, अर्जुन मोडवाडिया से लेकर सिद्धार्थ पटेल भी इस रस्साकशी में शामिल हैं। इस अंदरूनी खींचतान के कारण ही गुजरात कांग्रेस का बदलाव अटका हुआ है।

इसी तरह कर्नाटक के चुनाव में भी दो साल से कम समय रह गया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और विधायक दल के नेता सिद्धारमैया के बीच खींचतान सार्वजनिक होने लगी है। शिवकुमार, कांग्रेस से बगावत कर पाला बदलने वाले 14 विधायकों को वापस पार्टी में लाने के पक्ष में हैं तो सिद्धारमैया ने साफ कह दिया है कि चाहे धरती फट जाए वे ऐसा नहीं होने देंगे। शिवकुमार कांग्रेस हाईकमान के नजदीकी माने जाते हैं। साफ है कि नेतृत्व की दुविधा और कमजोरी को भांप पार्टी के क्षेत्रीय छत्रप अपना दम खम दिखा रहे हैं।

राजस्थान में सचिन पायलट और उनके समर्थकों को पार्टी नेतृत्व सरकार व संगठन में उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने के पक्ष में है मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक तैयार नहीं हुए हैं।

उत्तराखंड में भाजपा की नई सियासत का सूत्रपात

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड में युवा हाथों को कमान सौंपने के साथ ही भाजपा ने नए राजनीतिक युग का सूत्रपात किया है। पार्टी हाईकमान ने इसके जरिये एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अभी तक की तस्वीर देखें तो अनुभवी हाथों में ही राज्य की बागडोर रही है। सभी ने अपनी क्षमतानुसार प्रदेश को दिशा देने की कोशिश की, लेकिन इस बार राजनीतिक तस्वीर एक एकदम अलग है। भाजपा के पास प्रचंड बहुमत के बावजूद सियासी अस्थिरता से पीछा नहीं छूटा। इसके पीछे भले ही तमाम ध्रुवीय व गुटीय समीकरण रहे हों, लेकिन मौजूदा फेरबदल में भविष्य के रोड मैप को सामने रखकर पार्टी ने नई शुरुआत की है। भाजपा के इस कदम को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को पटखनी देने के मकसद से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

खटीमा (ऊधमसिंहनगर) से दूसरी बार के विधायक 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी

भविष्य की बुनियाद

को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उत्तराखंड का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है। हालांकि, पार्टी ने बुजुर्गों का साथ नहीं छोड़ा है। उनके तजुर्बे का लाभ युवा नेतृत्व को मिले, इसे लेकर भाजपा आगे बढ़ी है। नेतृत्व परिवर्तन के बीच असंतोष के जो सुर उभरे थे, उन्हें भविष्य के रोड मैप का वास्ता देकर शांत करने की कोशिश की गई। पार्टी का एजेंडा स्पष्ट है और उसने भविष्य की राजनीति की आधारशिला रखी है।

मुख्यमंत्री धामी के सामने प्रदेश के विकास को नए स्थापित करने की चुनौती तो है ही, पार्टी के अनुभवी विधायकों का मान-सम्मान बरकरार रखने के साथ ही उनके अनुभवों का लाभ भी राज्यहित में उठाना है। भाजपा जिस तरह से युवाओं को तरजीह देती आ रही है, वह भविष्य की राजनीति का ही हिस्सा है।

कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत टीएमसी में शामिल

बदला पाला ▶ तृणमूल में शामिल होने की पहले से थी अटकलें, दो बार सांसद रहे हैं अभिजीत

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस को अब एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र व पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सोमवार को कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का दामन थाम लिया है।

कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय और वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी की उपस्थिति में अभिजीत ने टीएमसी की सदस्यता ली। तृणमूल नेताओं ने अभिजीत का पार्टी में स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी के परिवार का लंबे समय से कांग्रेस के साथ संबंध रहा है, लेकिन उनके निधन के बाद अब अभिजीत ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। इस मौके पर मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि बंगाल के सपूत दिवंगत प्रणब मुखर्जी की देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक पहचान रही है। वह हम सभी के मार्गदर्शक रहे हैं। अभिजीत के तृणमूल में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले महीने ही अभिजीत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की थी।

2019 के चुनाव में करना पड़ा था हार का सामना : अभिजीत ने वर्ष 2012 (उपचुनाव) और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जंगीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि, 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसी अटकलें हैं कि टीएमसी अभिजीत को जंगीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में उतार सकती है।

बहन शर्मिष्ठा बोलीं- सैड : अभिजीत का टीएमसी में जाना उनकी बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी को बिल्कुल भी रास नहीं आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसे 'सैड' यानी निराशाजनक करार दिया। शर्मिष्ठा दिल्ली कांग्रेस की प्रमुख नेता हैं।

एक कांग्रेस छोड़कर दूसरे कांग्रेस में आया हूं

तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद त्पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस में अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस छोड़कर वह दूसरे कांग्रेस में आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से भाजपा की हालिया सांप्रदायिक लहर को बंगाल में रोका, मुझे विश्वास है कि भविष्य में वह दूसरों के समर्थन से पूरे देश में ऐसा ही कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि वह एक सैनिक की तरह तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं और पार्टी के निर्देश के मुताबिक काम करेंगे।


सोमवार को कोलकाता में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने कांग्रेस से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्हें गले लगाते तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुदीप बंद्योपाध्याय (दाएं)। प्रेट्र

माकपा के वरिष्ठ नेता कांति गांगुली के बगावती तेवर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- विधानसभा चुनाव में करारी हार के लिए बंगाल माकपा नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार
- राज्य नेतृत्व को पत्र लिखकर पार्टी की केंद्रीय कमेटी भंग करने की मांग की

बंगाल विधानसभा चुनाव में माकपा की करारी हार को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्य के पूर्व मंत्री कांति गांगुली ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने इसके लिए बंगाल माकपा नेतृत्व को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए सभी शीर्ष नेताओं को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की केंद्रीय कमेटी को भी भंग करने की मांग की है। रायदीघी के पूर्व विधायक व अतीत में सुंदरवन विकास मंत्री रहे कांति गांगुली ने इसे लेकर राज्य नेतृत्व को पत्र लिखा है। दूसरी तरफ उनके बागी तेवर को देखते हुए वाममोर्चा के चेयरमैन विमान बोस व माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा ने उन्हें बातचीत के लिए मंगलवार को अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित पार्टी मुख्यालय बुलाया है।

कांति गांगुली ने विधानसभा चुनाव में माकपा समेत किसी भी वामदल को एक भी सीट नहीं मिलने के लिए कांग्रेस व फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नवगठित पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ चुनावी गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसे लेकर पार्टी की जिला कमेटी की बैठक में नाराजगी जाहिर की थी। राज्य कमेटी की बैठक में भी उन्होंने सबके सामने सूर्यकांत मिश्रा को बुरी हार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक में उनकी सूर्यकांत मिश्रा के साथ बहस भी हुई थी।

बंगाल विस में करीब आए मुकुल रॉय व सुवेंदु अधिकारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

हाल ही में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल रॉय को विधानसभा के प्रथम सत्र के पहले दिन ब्लॉक तीन में 42 नंबर सीट आवंटित की गई थी। उस दिन वह उसी सीट पर बैठे थे, लेकिन सोमवार को उनकी सीट बदल दी गई। उनकी विधानसभा की सीट फिर से बदलना सत्ताधारी पार्टी की रणनीति बताई जा रही है। मुकुल अब भाजपा विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की बाएं तरफ की सीट पर बैठेंगे, जो ब्लॉक दो में सीट नंबर 15 है। मुकुल सोमवार को इसी सीट पर बैठे।

इससे पहले मुकुल को विपक्ष की जो सीट दी गई थी, वह सुवेंदु की सीट से बहुत दूर थी।

एसजी मामले में राष्ट्रपति से मिला तृणमूल प्रतिनिधिमंडल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के भाजपा नेता व नारद स्टिंग मामले में आरोपित सुवेंदु अधिकारी से कथित मुलाकात के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से मेहता को पद से हटाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा शामिल थीं। उन्होंने कहा कि टीएमसी इस मुद्दे को संसद भी में उठाएगी।

गौरतलब है कि इससे पहले तृणमूल के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा और सुखेंदु शेखर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सॉलिसिटर जनरल को हटाने की मांग की थी। गौरतलब है कि टीएमसी ने सुवेंदु अधिकारी के साथ सॉलिसिटर जरनल की बैठक होने का आरोप लगाया है, जबकि अधिकारी और तुषार मेहता ऐसी किसी बैठक से इन्कार कर चुके हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल दूसरे बड़े विधि अधिकारी हैं और नारद मामले सहित महत्वपूर्ण कानूनी मामलों पर सरकार और उसकी एजेंसियों को सलाह देते हैं। नारद मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। ऐसी स्थिति में उनका इस मामले के आरोपित सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात करना सही नहीं है।

पासवान की सियासी विरासत की लड़ाई सड़कों पर आई

राज्य ब्यूरो, पटना

लोजपा में टूट के बाद चुनाव-चिह्न (बंगला) पर कब्जे की लड़ाई संसद और चुनाव आयोग से होते हुए सोमवार को जमीन पर उतर गई। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर चाचा-भतीजा (पशुपति कुमार पारस व चिराग पासवान) की ओर से अलग-अलग समारोह के जरिये समर्थकों की भीड़ जुटाने की आपाधापी देखी गई।

पारस ने अपने साथ के सांसदों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटाकर पटना स्थित प्रदेश लोजपा मुख्यालय में रामविलास की जयंती मनाई और संकल्प लिया कि बड़े भाई के खून-पसीने से स्थापित 21 वर्ष पुरानी पार्टी का अस्तित्व बचाने की कोशिश की जाएगी। उनके विचारों और सिद्धांतों के बूते सबको साथ लेकर चलने का वादा किया गया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी रहे लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान को उनकी जयंती पर याद किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पासवान के पुत्र चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस से टेलीफोन पर बातचीत की।

चिराग ने अपने तरीके से रामविलास पासवान की विरासत पर हक जताया। समारोह और आशीर्वाद यात्रा शुरू करने के लिए जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने भी अपने समर्थकों की ताकत दिखाने और रोड-शो के अंदाज में वाहनों का लंबा काफिला निकालकर अपने विरोधियों को करारा जवाब देने की कोशिश की। हवाई अड्डे से लेकर हाजीपुर की सुल्तानपुर बस्ती तक उमड़ी भीड़ संदेश दे रही थी कि लोजपा में टूट जरूर हुई है, लेकिन चिराग का जलवा अभी कायम है।


पटना में सोमवार को जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर उतरने के बाद चिराग पासवान जब बाहर आए, तो यहां पहले से मौजूद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जागरण

पारस बोले, अब मुझे किसी पद-प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं : अपने बड़े भाई रामविलास के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करने के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस भावुक हो गए। कहा कि उन्हें किसी पद-प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। बड़े भाई की बदौलत और समर्पित कार्यकर्ताओं के स्नेह से जीवन में बहुत सम्मान मिला। मुझे आने वाली पीढ़ी और समर्पित कार्यकर्ता कभी माफ नहीं करते, यदि मैं पार्टी को बर्बाद होते हुए मूकदर्शक बना देखता रहता। मैंने पार्टी के अस्तित्व को बचाया है।।

बैंड-बाजा और समर्थकों के जयकारे से निहाल हो गए चिराग : पटना हवाई अड्डे पर समर्थकों ने बैंड-बाजा, फूल-माला और जयकारे से चिराग पासवान का स्वागत किया। चिराग जिंदाबाद के साथ ही कई समर्थक पारस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उसके बाद चिराग हाजीपुर के लिए रवाना हुए।

राजद के कार्यक्रम में शामिल हुई रामविलास पासवान की पहली पत्नी

जासं, खगड़िया: रामविलास पासवान की जयंती पर सोमवार को उनका पैतृक गांव शहरबन्नी बंटा दिखा। राजद और लोजपा (पारस गुट) ने रामविलास पासवान की जयंती पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए थे। राजद ने रामविलास पासवान के शहरबन्नी स्थित घर पर, जबकि लोजपा (पारस गुट) की ओर से सैल भवन (यहां रामविलास पासवान के माता-पिता का स्मारक है) में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। घर पर हुए कार्यक्रम में रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी भी शामिल हुई। राजद ने राजकुमारी देवी को सम्मानित भी किया। वह कुछ ही देर कार्यक्रम में रहीं। कुछ नहीं बोलीं। बीपी बढ़ जाने के कारण चली गईं। लोजपा महासचिव (चिराग गुट) और खगड़िया की पूर्व सांसद डा. रेणु कुशवाहा ने कहा कि राजकुमारी देवी अपने बेटे चिराग के साथ हैं। उन्होंने बताया कि चिराग नौ जुलाई को खगड़िया आएंगे और गांव में अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से आशीर्वाद लेंगे।

फर्जी टीकाकरण के खिलाफ कोलकाता में सड़क पर उतरे भाजपाइयों की पुलिस से झड़प

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

महानगर में फर्जी टीकाकरण के खिलाफ सोमवार को सड़क पर उतर कर प्रदर्शन के लिए कोलकाता नगर निगम (केएमसी) मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसको लेकर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। पुलिस ने 51 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस की तरफ से कोविड-19 की गाइडलाइन व लाकडाउन के मद्देनजर प्रदर्शन के लिए मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद भाजपा नेता व कार्यकर्ता विरोध मार्च निकाल रहे थे। कोलकाता के सुबोध मल्लिक स्क्वायर में भाजपा कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे से ही एकत्रित होने लगे। यहां से निगम मुख्यालय की ओर बढ़ दिए, लेकिन पुलिस ने केएमसी कार्यालय की तरफ कूच करने के दौरान उनको सेंट्रल एवेन्यू मोड़ पर ही रोक कर हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने कानून तोड़ने के आरोप में कुल 51 भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसको लेकर आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार फर्जी टीकाकरण गिरोह के मुख्य षड्यंत्रकर्ता देबांजन देब और सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं के साथ ही केएमसी के आला अधिकारियों के बीच कथित संबंध को छिपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने इस 'मिलीभगत' का पर्दाफाश करने के लिए ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया था, लेकिन पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी जब विपक्ष में थी तब उसके नेता-कार्यकर्ता बिना किसी मंजूरी के कार्यक्रम आयोजित करते थे और अब जब हम कोई राजनीतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तब हमें ऐसा करने से रोका जाता है।


कोलकाता में सोमवार को फर्जी टीकाकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेते पुलिसकर्मी। प्रेट्र

भाजपा ने टीएमसी पर लगाए विधायक और कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप : दूसरी ओर, प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के गुंडों ने उनके विधायक और कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि भाजपा विधायक दिबाकर घरामी पर बांकुड़ा जिले में टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। इसमें विधायक सहित सात अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के घायल होने का उन्होंने दावा किया है।

राहुल ने बिहार के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली तलब किया

राज्य ब्यूरो, पटना : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहार के पार्टी विधायकों और विधान पार्षदों से रूबरू होंगे। उनके बुलावे पर पार्टी के सभी 19 विधायक और तीन विधान पार्षद मंगलवार को दिल्ली पहुंच जाएंगे। बुधवार को उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष डा. मदन मोहन झा भी इस टीम में शामिल हैं। वे विधान परिषद के सदस्य भी हैं।

हाल के दिनों में कांग्रेस विधायक दल में टूट की खबरों के बीच राहुल की इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के विधायक इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं।

लालू बोले, सत्ता के लिए देश को तबाह किया जा रहा

राज्य ब्यूरो, पटना : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 25वें स्थापना दिवस पर पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने अयोध्या के बाद मथुरा के मुद्दे को उठाने के प्रति देश को आगाह किया और भाजपा पर देश तोड़ने का आरोप लगाया। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा होने के बाद लालू दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास में रह रहे हैं। वहीं से साढ़े तीन साल बाद किसी कार्यक्रम में आनलाइन भाग लिया है। लंबी बीमारी के कारण राजद प्रमुख की आवाज में कुछ सुस्ती जरूर थी, लेकिन तेवर और तौर-तरीके में कोई फर्क नहीं था।

भाजपा पर पुराने अंदाज में ही हमलावर राजद प्रमुख ने कहा कि सत्ता के लिए सामाजिक तानाबाना को खंडित किया जा रहा है। नारा लगाया जा रहा है कि अयोध्या के बाद मथुरा.. क्या इरादा है? वह टूट जाएंगे, मगर बुनियादी मुद्दों से कभी समझौता नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव में राजद के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने का श्रेय उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व को दिया और समर्थन के लिए नेताओं-कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। बोले नई पीढ़ी के हाथों में राजद का भविष्य उज्ज्वल है और निकट भविष्य में हम देश का भी नेतृत्व करेंगे।


नई दिल्ली में सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पटना में कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रेट्र

अपने घर में ही बेगाने हो गए हैं तेज प्रताप

राजद स्थापना दिवस समारोह में थोड़ी देर से पहुंचे तेज प्रताप यादव ने मंच से ही नाराजगी जताई और कहा कि मुझे पीछे खींचा जाता है, ताकि मैं असली हीरो न बन जाऊं। भाषण देते समय तेज प्रताप का माइक खराब हुआ तो उन्होंने कहा कि सच कोई सुनना नहीं चाहता है। उन्होंने अपनी तुलना लालू प्रसाद से करते हुए कहा कि मेरी बातों का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही मेरे पिताजी की बातों पर भी लोग हंसते थे। मैं सच बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं।

अब राज्यपाल की किताब के जरिये विरोधियों ने गहलोत को घेरा

जासं, जयपुर: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के जीवन पर आधारित कॉफी टेबल बुक 'कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं मैं' पर उठे विवाद की आंच कांग्रेस तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरोधी नेता इस मुद्दे पर उन्हें घेर रहे हैं। विरोधियों ने सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व महासचिव अजय माकन को शिकायत भेजकर कहा गया कि जिस किताब में कांग्रेस विरोधी विचारधारा का उल्लेख किया गया है, उसका विमोचन गहलोत और जोशी द्वारा करना गलत है । इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा होगी । माकन मंगलवार को जयपुर आ रहे हैं, ऐसे में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट समर्थक यह मुद्दा उनके सामने उठा सकते हैं ।

भाजपा-शिवसेना के रिश्ते आमिर व किरण राव जैसे : संजय राउत

मुंबई, एएनआइ : शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने सोमवार को पूर्व गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अपनी पार्टी के रिश्तों की तुलना अभिनेता आमिर खान और किरण राव के बीच संबंधों से की। बालीवुड की इस चर्चित जोड़ी ने हाल ही में पति-पत्नी के तौर पर अलग होने की घोषणा की है।

राउत की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के रविवार उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा और शिवसेना दुश्मन नहीं हैं। राउत ने कहा कि हम लोग भारत-पाकिस्तान नहीं हैं। आमिर खान और किरण राव को देखिए, यह उनके जैसा है। हमारे (शिवसेना व भाजपा) राजनीतिक तरीके अलग हैं लेकिन दोस्ती बरकरार रहेगी। राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार में दरार और शिवसेना के साथ भाजपा के गठबंधन की अटकलों के बीच शिवसेना नेता की टिप्पणी आई है। हालांकि भाजपा ने दोनों पार्टियों के बीच ऐसे किसी गठबंधन की संभावना से इन्कार किया है। फड़नवीस की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि भाजपा, शिवसेना दुश्मन नहीं हैं। यह सौ फीसद सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक साथ आएंगे और सरकार बनाएंगे। उल्लेखनीय है रविवार को फड़नवीस ने कहा था कि भाजपा और शिवसेना के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन वे दुश्मन नहीं हैं।

5 किलो सोने के बिस्कुट के साथ तीन तस्करों को इंदौर में गिरफ्तार किया है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस ने। यह सोना स्विटजरलैंड से तस्करी कर मुंबई लाया गया था। तीनों आरोपित सोना लेकर इंदौर के रास्ते भोपाल जा रहे थे।

न्यूज गैलरी

उप्र के खेल मंत्री को अपशब्द, पांच सपा कार्यकर्ता गिरफ्तार

बलिया : उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी को अपशब्द कहने के मामले में पुलिस ने पांच सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। रविवार को वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए रात भर छापेमारी की। मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी व उनके पिता पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी समेत दस लोगों को नामजद किया गया है। सौ अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि सपा कार्यालय से पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। (जासं)

यूएई की जेल में बंद जासूसी के आरोपित की मां पहुंची हाई कोर्ट

कोच्चि : केरल निवासी एक महिला ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की जेल में बंद बेटे को जरूरी मदद उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसका बेटा कथित तौर पर भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शाहुबनाथ बीवी की तरफ से दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि उसके बेटे शिहानी मीरा साहिब जमाल मुहम्मद को जेल में यातना दी जा रही है। उसका उत्पीड़न किया जा रहा है और भारतीय दूतावास या केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। (प्रेट्र)

गैंगस्टर चिंकू पठान का गुर्गा ड्रग्स मामले में गिरफ्तार

मुंबई : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गैंगस्टर चिंकू पठान के गुर्गे सोनू पठान को ड्रग्स मामले में मुंबई के डोंगरी से गिरफ्तार कर लिया। वह पिछले पांच वर्षों से फरार था। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जारी बयान के अनुसार, 'एनसीबी को सूचना मिली थी कि सोनू पठान अपने परिवार से मिलने आने वाला है। इसके आधार पर एजेंसी ने जाल बिछाकर सोनू को रविवार की रात गिरफ्तार कर लिया।' मुंबई के कई थानों में सोनू के खिलाफ मामले दर्ज हैं। वह चिंकू पठान का करीबी बताया जाता है। चिंकू पठान को एनसीबी ने इसी साल 20 जनवरी को ड्रग्स के साथ डोंगरी इलाके से गिरफ्तार किया था। (एएनआइ)

नर्मदा नदी में खड़े होकर फेसबुक लाइव कर रहे तीन किशोर डूबे

नर्मदापुरम (होशंगाबाद) : हर्बल पार्क घाट पर नहाने पहुंचे तीन किशोर नर्मदा के गहरे पानी में गिर गए। इनमें से दो डूब गए, जबकि एक को होमगार्ड जवानों ने बचा लिया। नर्मदा में स्नान करने के दौरान तीनों किशोर मोबाइल से फेसबुक लाइव कर रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। तीनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। किशोर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद अन्य दो भी असंतुलित हो गए और गहरे पानी में गिर गए। (नईदुनिया)

परिसीमन मुद्दे पर एकमत नहीं गुपकार गठबंधन

घटक दलगत एजेंडे के मुताबिक परिसीमन आयोग से मुलाकात करेंगे

विस चुनाव से पूर्व राज्य का दर्जा और राजनीतिक बंदियों की रिहाई मांग रहे

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

बिना किसी हंगामे और विवाद के मिलें...

पीएजीडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एक प्रमुख राजनीतिक दल चाहता है कि बिना किसी हंगामे और विवाद को खड़ा किए बिना परिसीमन आयोग से मिलना चाहिए। उसे एक संयुक्त ज्ञापन भेंट करना चाहिए। एक अन्य घटक दल पहले केंद्र द्वारा कुछ विश्वास बहाली के कद उठाए जाने का यकीन दिलाए जाने पर जोर दे रहा है। वह चाहता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो, सभी कैदियों की रिहाई हो। अन्य तीन घटक इस मामले में तटस्थ बने हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ एकजुट पीपुल्स एलायंस फार गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) परिसीमन आयोग के साथ मुलाकात व इसके एजेंडे को लेकर बंटा हुआ है। इसलिए पीएजीडी के सभी घटक अपनी दलगत राजनीति और एजेंडे के मुताबिक आयोग से मुलाकात करेंगे। इस बीच, पीएजीडी ने सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्र सरकार के रवैये पर असंतोष जताया। उसने कहा कि वह अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली के लिए संघर्ष जारी रखेगा। उसने विधानसभा चुनाव से पूर्व जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने व राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर जोर दिया है।

पीएजीडी में नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अवामी नेशनल कांफ्रेंस और डेमोक्रेटिक पीपुल्स मूवमेंट शामिल हैं। पीपुल्स कांफ्रेंस भी शुरू में पीएजीडी का हिस्सा थी, लेकिन बाद वह इससे अलग हो गई। पीएजीडी जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त, 2019 से पूर्व की संवैधानिक स्थिति की बहाली की मांग कर रहा है। 24 जून को पीएजीडी के नेता जम्मू-कश्मीर के अन्य दलों के नेताओं की मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिले थे। इस बैठक में पीएजीडी के घटक बतौर पीएजीडी प्रतिनिधि नहीं, बल्कि अपने अपने दल के एजेंडे के आधार पर ही शामिल हुए थे। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिसीमीन की प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग का आह्वान करते हुए जल्द ही विधानसभा चुनावों का यकीन दिलाया है।

परिसीमन आयोग से मुलाकात को राजी, लेकिन एक एजेंडे पर सहमत नहीं : परिसीमन आयोग का जम्मू-कश्मीर दौरा अब तय हो चुका है। आयोग की अध्यक्ष रंजना देसाई के साथ चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा मंगलवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी पहुंच जाएंगे। वह चार दिन तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर स्थानीय राजनीतिक व अन्य संगठनों से मुलाकात करेंगे, लेकिन सभी की नजरें पीएजीडी के रुख पर टिकी हुई हैं। पीएजीडी के नेताओं के बीच गत रोज इसी मुद्दे पर बैठक भी हुई, जिसमें कोई खास नतीजा नहीं निकला। सभी परिसीमन आयोग के साथ मुलाकात को राजी हैं, लेकिन एक एजेंडे पर सहमत नहीं हैं।

पीएजीडी के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के परिणाम संतोषजनक नहीं हैं। केंद्र सरकार ने बैठक के बाद यहां कश्मीर में लोगों में विश्वास और सुलह की नई उम्मीद जगाने लिए विश्वास बहाली का कोई कदम नहीं उठाया है। पीएजीडी इससे निराश है। जम्मू-कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा दें फिर विधानसभा चुनाव होने चाहिए। इसके अलावा सभी प्रमुख राजनीतिक बंदियों को जिन पर कोई गंभीर आरोप नहीं है, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए था, जो केंद्र सरकार ने नहीं किया है। देश की विभिन्न जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को प्रदेश की विभिन्न जेलों में वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएजीडी ने कहीं भी अनुच्छेद 370 और 35ए के मुद्दे पर समझौता नहीं किया है। इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। हम अदालत में भी लड़ रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के डोडा पुलिस लाइन के पास ग्रेनेड हमला, दो घायल

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में फिर आतंकवाद को जिंदा करने की साजिश रची जा रही है। सोमवार को पुलिस लाइन डोडा के पास आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। इसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने आतंकी संगठन ने नहीं ली है। पूरे क्षेत्र को घेर कर सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान चल रहा है। घायलों का इलाज डोडा अस्पताल में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार दोपहर 2.30 बजे पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन इमारत में काम चल रहा था। वहां पर पुलिस कर्मी भी तैनात थे। लोगों की आवाजाही के बीच आतंकियों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका। संयोग से निशाना चूक गया। ग्रेनेड फटने से हुए विस्फोट में दो पुलिसकर्मी चपेट में आ गए। निर्माणाधीन इमारत में नुकसान हुआ है। तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

कश्मीर में आतंकरोधी अभियान तेज होने के कारण आतंकी अब डोडा जिले की तरफ रुख कर रहे हैं। यह इलाका दक्षिण कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पिछले दो साल भी डोडा से सटे किश्तवाड़ जिले में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं।

सुरक्षाबलों ने त्राल में ध्वस्त किया आतंकी ठिकाना : श्रीनगर : सुरक्षाबलों ने आतंकरोधी अभियान को जारी रखते हुए दक्षिण कश्मीर के मड्ूरा, त्राल में आतंकी ठिकाने को नष्ट कर दिया। सुरक्षाबलों ने विशेष सूचना पर मड्ूरा में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान जवानों ने एक बाग में आतंकियों के भूमिगत ठिकाने का पता लगाया। जवानों ने सावधानीपूर्वक ठिकाने की तलाशी ली। उन्हें वहां राशन, बर्तन, फौजी वर्दियां, कंबल व अन्य सामान मिले।

जम्मू एयरपोर्ट पर आरडीएक्स से ही हुआ था हमला

जागरण संवाददाता, जम्मू

वायुसेना के जम्मू स्थित एयरपोर्ट पर 27 जून की आधी रात के बाद हुए ड्रोन हमलों में नाइट्रेट युक्त आरडीएक्स से बने घातक विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। फोरेंसिक विभाग की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है। जम्मू एयरपोर्ट पर दो बम धमाके हुए थे। इन दोनों विस्फोटकों का मिश्रण भारी तबाही मचाने वाला था।

दैनिक जागरण ने 29 जून के अंक में पहले ही संकेत दे दिए थे कि जम्मू एयरपोर्ट पर हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ है। अब वैज्ञानिक जांच में भी यह बात सामने आ रही है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। इस तथ्य के आधार पर जम्मू एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने में काफी अहम सबूत मिलता है। ड्रोन को संचालित करने वालों का निशाना एयरफोर्स स्टेशन पर हैंगर में खड़े एमआइ-7 हेलीकाप्टर और छोटे एयरक्राफ्ट थे। जिस प्रकार से एयरफोर्स स्टेशन की इमारत में बम धमाके से विस्फोट हुआ, उसकी तीव्रता से छत में बड़ा छेद हो गया। इन विस्फोटकों में छर्रों और बाल बियरिंग का इस्तेमाल अधिक से अधिक जानमाल का नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि एयरफोर्स हमले में शामिल जीपीएस युक्त ड्रोन संभवतः चीन निर्मित था। इसे देखते हुए एंटी ड्रोन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए भारत को इजराइल की तकनीक पर काम करने की जरूरत है। गत दिनों जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी आशंका जताई थी कि ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान का प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। देश में ड्रोन से हमले की यह पहली घटना है। इसमें भारतीय वायु सेना के दो जवान घायल हुए थे। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) कर रही है। एसएसपी चंदन कोहली का मानना है कि हमले में दो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। आतंकी संगठन लश्कर कभी नहीं चाहेगा कि उसके ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) ड्रोन से हमला करें। दरअसल, सीमा पर बैठे लश्कर के आतंकी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई भी ओजीडब्ल्यू जम्मू में पकड़ा जाए, जिससे आंतकी संगठन की मुश्किलें बढ़ें।

जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को देखते हुए एंटी ड्रोन प्रणाली को स्थापित कर दिया गया है। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पहले ही कह दिया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले का मकसद सेना के साजोसामान को भारी नुकसान पहुंचाना था। फिलहाल इस मामले की विस्तार से जांच चल रही है।

ड्रोन हमला सीमा पार से संचालित था : एसएसपी

जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली का कहना है कि एनआइए के अलावा मामले की जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस भी कर रही है। कोहली ने आशंका व्यक्त की कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला पाकिस्तान से हुआ है। ड्रोन के संचालक ने पाकिस्तान की सीमा में बैठकर ड्रोन को उड़ाया था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से अंतरराष्ट्रीय सीमा 14 किलोमीटर दूर ही है। ड्रोन जम्मू एयरपोर्ट रनवे से सीधा आया। कहीं भी दाएं या बाएं नहीं गया और सीधे टेक्नीकल एयरपोर्ट पर हमला किया।

शक्ति भोग कंपनी का अध्यक्ष मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी कई करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में हुई है।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुमार को रविवार को गिरफ्तार कर विशेष मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया। विशेष अदालत ने उन्हें नौ जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी से पहले एजेंसी ने दिल्ली और हरियाणा में कम से कम नौ परिसरों पर छापेमारी की थी। बयान के मुताबिक, तलाशी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए की आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया था। सीबीआइ ने इस साल के शुरू में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के नेतृत्व वाले 10 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 3,269 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एसबीआइ ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। एसबीआइ के अनुसार निदेशकों ने लोगों के पैसे हड़पने के लिए कथित तौर पर खातों में हेराफेरी की और जाली दस्तावेज तैयार किए। बैंक ने कहा था कि 24 साल पुरानी कंपनी की 2008 में कारोबार वृद्धि 1,411 करोड़ रुपये थी, जो 2014 में बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी आटा, गेहूं, चावल, बिस्कुट आदि के व्यापार में है। ईडी ने कहा कि उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों द्वारा संदिग्ध खरीद-फरोख्त के जरिये कर्ज खाते के पैसे को हेराफेरी करके बाहर भेज दिया।

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे उप्र के 12 जिले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रयागराज से मेरठ तक बनने जा रहे देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का खाका उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में हुई सचिव समिति की बैठक में इसका प्रस्तुतीकरण हुआ। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 12 जिले और 519 गांव जुड़ेंगे।

लखनऊ में लोकभवन में सोमवार को आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुडापुर दांदू गांव तक बनेगा। यह कुल 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा।

एनआइए की विशेष अदालत ने पांच आतंकियों पर तय किए आरोप

जेएनएफ, जम्मू

▶ अप्रैल, 2019 को हुए हमले में पीएसओ व अस्पताल कर्मी की मौत हुई थी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने किश्तवाड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता चंद्रकांत की हत्या के मामले में हिजबुल मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों पर आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में तीन अन्य आरोपित भी थे जिन्हें सुरक्षाबलों ने दो मुठभेड़ों में मार गिराया। इन आरोपितों की मौत की पुष्टि होने के बाद कोर्ट ने शेष पांचों पर आरोप तय किए।

केस के मुताबिक नौ अप्रैल, 2019 को पुलिस को सूचना मिली कि किश्तवाड़ जिला अस्पताल के ओपीडी ब्लाक के निकट आतंकवादियों ने आरएसएस कार्यकर्ता चंद्रकात पर हमला किया है। इसमें उनके पीएसओ कांस्टेबल राजेंद्र कुमार व अस्पताल के एक कर्मचारी की मौत हो गई है। चंद्रकात गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। आतंकी राजेंद्र कुमार की एके-47 राइफल भी साथ ले गए। पुलिस ने चंद्रकांत को हवाई मार्ग से जम्मू शिफ्ट किया लेकिन उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने एफआइआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआइए को सौंप दी। एनआइए ने जांच के दौरान पाया कि हिजबुल मुजाहिदीन ने किश्तवाड़ में आतंकवादी गतिविधियों को फिर से जीवित करने व समुदाय विशेष में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए चंद्रकांत को अपना निशाना बनाया। हत्या से पूर्व आरोपितों ने बैठक की जिसमें हत्या की पूरी रूपरेखा तय की और निर्धारित दिन पर इन वारदात को अंजाम दिया गया।

सिरसा व रैना समेत तीन के खिलाफ एफआइआर के निर्देश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर में कथित लव जिहाद-मतांतरण पर दिए बयानों के मामले में श्रीनगर की निचली अदालत ने पुलिस को शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 12 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। अदालत ने सोमवार को यह निर्देश जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता नासिर खुहेमी की याचिका पर दिया है।

नासिर खुहेमी ने शनिवार को याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंद्र रैना व इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहने वाले अमन बाली नामक युवक के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आग्रह किया था।

एलगार परिषद मामले में गिरफ्तार स्टेन स्वामी का निधन

राज्य ब्यूरो, मुंबई



एलगार परिषद और भीमा कोरेगांव मामलों के आरोपित फादर स्टेन स्वामी पार्किंसन सहित कई अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। फाइल/प्रेट्र

एलगार परिषद और भीमा कोरेगांव मामलों के आरोपित फादर स्टेन स्वामी का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। 84 वर्षीय स्टेन ने बीमारी के कारण जमानत की अर्जी लगा रखी थी, लेकिन कोर्ट द्वारा उस पर सुनवाई से पहले ही उनका निधन हो गया।

स्टेन स्वामी पार्किंसन सहित कई अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। हाल ही में उन्हें कोरोना भी हो चुका था। एनआइए द्वारा आठ अक्टूबर, 2020 को रांची से गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल में थे। एनआइए ने उन्हें माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। स्टेन ने अपनी गिरफ्तारी को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी थी और बीमारी के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी।

बीमारी के कारण ही उन्हें तलोजा जेल से बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था। सोमवार को ही उनकी जमानत याचिका पर मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दोपहर 1.30 बजे उनका निधन होने के बाद 2.30 बजे उनके वकील मिहिर देसाई ने अदालत को बताया कि उनका निधन हो गया है।

असम में जघन्य मामलों में छह महीने में आरोप पत्र दाखिल करे पुलिस

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने राज्य पुलिस से जघन्य आपराधिक मामलों में छह महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुष्कर्म, हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध वसूली और अवैध हथियार रखने के लंबित मामलों की जांच छह महीने में पूरी की जाए।

सरमा ने ये निर्देश प्रदेश के सभी थानाध्यक्षों (एसएचओ) के साथ बैठक में दिए। राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की यह पहली बैठक थी। उन्होंने थाना प्रभारियों से कहा कि वे सभी लंबित मामलों के आरोप पत्र दाखिल करने और अपराधियों को दंडित कराने के कार्य में जुट जाएं। इस कार्य में वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग लें। सीआइडी की भी मदद लें।

स्वप्ना सुरेश ने हाई कोर्ट में लगाई जमानत अर्जी

कोच्चि, प्रेट्र : केरल सोना तस्करी की मुख्य आरोपित स्वप्ना सुरेश ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। राजनयिक माध्यम से की जा रही सोना तस्करी के इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने मुकदमा दर्ज किया है। एनआइए अदालत स्वप्ना की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।

जमानत अर्जी में स्वप्ना ने कहा है कि उसके खिलाफ दर्ज गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून का मुकदमा कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। उसने यह भी कहा है कि यह मुकदमा अंतहीन होता जा रहा है। एनआइए की विशेष अदालत ने 22 मार्च को स्वप्ना सुरेश, केटी रमीस, संदीप नायर और पीएस सरित समेत सात आरोपितों की याचिका खारिज कर दी थी।

पिछले साल पांच जुलाई को तिरुअनंतपुरम हवाईअड्डे पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी के नाम पर भेजे गए पार्सल से 15 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। सोना तस्करी के इस मामले की कई केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं।

भाजपा नेता ने कहा-मुसलमान हमारे भाई नहीं रहे

अलवर में दुष्कर्म मामला

जागरण संवाददाता, जयपुर

अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राजस्थान के भाजपा नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। अलवर जिले में दुष्कर्म की एक वारदात के बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग हमारे भाई नहीं रहे। अब हिंदुओं को शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा।

अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आहूजा ने पीड़िता और उसके स्वजन से मुलाकात की। इसके बाद सोमवार को उन्होंने 25 जुलाई को बहादुरपुर में हथियारों के साथ रैली करने की घोषणा की। इसमें 10 हजार लोगों के शामिल होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस रैली में किसी भी मुस्लिम को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई आएगा तो उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान अब हमारे भाई नहीं रहे। यह भाई तब होते, जब हमारी बहन-बेटियों के साथ दुष्कर्म नहीं करते। आहूजा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदुओं को शस्त्र उठाकर अपनी पहचान करानी होगी, क्योंकि समाज विशेष के लोग हिंदू बेटियों के साथ आए दिन दुष्कर्म और अत्याचार जैसी हरकते करते हैं। उन्होंने कहा कि नाबालिग पीड़िता के पिता को पैसे का प्रलोभन देकर समझौते के लिए कहा गया। वह इसके लिए तैयार नहीं हुए तो धमकियां दी जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोपितों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आहूजा ने आरोप लगाया कि मेवात में मुसलमान हिंदुओं का जबरन मतांतरण कराते हैं। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मंदिर में घंटी नहीं बजाएंगे, क्योंकि वह तो मस्जिद में टोपी लगा कर निकलते हैं। गहलोत भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की तरह बाईचांस हिंदू हैं। उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

वकील के चैंबर में हुआ मतांतरण और निकाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील के चैंबर को मस्जिद में तब्दील कर युवती का पहले मतांतरण और फिर निकाह कराने का मामला सामने आया है। युवती के पिता की शिकायत पर दिल्ली बार काउंसिल ने जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष अनुशासन समिति गठित की है। जांच पूरी होने तक आरोपित वकील इकबाल मलिक का लाइसेंस निलंबित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह में समिति को जवाब सौंपने का निर्देश है। कोर्ट परिसर में इस तरह की गतिविधि का यह पहला मामला है।

पटपड़गंज क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि उनकी 22 वर्षीय बेटी 28 मई को गायब हो गई थी। 15 जून को उनके पास बेटी का फोन आया, जिसके बाद उन्होंने पांडव नगर थाने में त्रिलोकपुरी निवासी कामरान खान पर बेटी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी बीच कामरान ने कड़कड़डूमा कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर कर दी। यहां से राहत मिलने में समय लगा तो उसने युवती के साथ मिलकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। बताया कि वे दोनों इस्लामी रीति-रिवाज से शादी कर चुके हैं। साक्ष्य के रूप में उसने निकाहनामा लगाया था, जो अल निकाह ट्रस्ट से जारी था। इसमें दर्ज था कि कड़कड़डूमा कोर्ट के एफ-322 स्थित मजार वाली मस्जिद में निकाह पढ़ा गया। कामरान ने हाई कोर्ट में दायर अर्जी में आरोप लगाया कि युवती के स्वजन उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके जीवन और स्वतंत्रता में किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए।

युवती के पिता के मुताबिक बाद में उन्हें बेटी के निकाह के बारे में मालूम हुआ। यह भी पता चला कि इससे पहले बेटी का मतांतरण कराया गया है। किसी तरह से उनके हाथ बेटी के मतांतरण का प्रमाणपत्र लग गया। इसे भी अल निकाह ट्रस्ट ने जारी किया था। इसके बाद उन्होंने पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त और दिल्ली बार काउंसिल से शिकायत की। इसमें आरोप लगाया कि कामरान खान ने उनकी बेटी का जबरन मतांतरण कराकर निकाह किया है। मतांतरण और निकाह कड़कड़डूमा कोर्ट के एफ-322 चैंबर में हुआ है। ये चैंबर वकील इकबाल मलिक है, उसने प्रमाण पत्र बनवाकर निकाह कराया। इन प्रमाण पत्रों में अनियमितताएं हैं, जिससे यह फर्जी प्रतीत होते हैं। आरोप लगाया कि काजी मुहम्मद अकबर देहलवी ने निकाह पढ़वाया, जो कोर्ट परिसर में ही एफ-73 सीट पर बैठते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में कई जगह इसी तरह से मतांतरण व निकाह करा चुके हैं। कामरान का आपराधिक रिकार्ड भी है। उस पर 14 मुकदमे दर्ज हैं। युवती के पिता का आरोप है कि वह थाने से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक भटकते रहे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। वहीं, दिल्ली बार काउंसिल के सचिव पीयूष गुप्ता ने बताया कि वकील पर कार्रवाई कर दी गई है। वकील का कृत्य पूरी तरह से शर्मनाक है और कानूनी पेशे की गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इधर, पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है।

> मैंने किसी का मतांतरण और निकाह नहीं कराया है। मुझे उर्दू भी नहीं आती। मुझे नहीं मालूम कि किसने मेरे चैंबर का नंबर लिख दिया। मुझ पर लगाए आरोप झूठे हैं। दिल्ली बार काउंसिल के नोटिस का जवाब दाखिल करूंगा।
> **- इकबाल मलिक, आरोपित वकील**

> मतांतरण और निकाह का एक मामला सामने आया है। सही से जांच की जाए तो गिरोह सामने आएगा। मेरे मुवक्किल की बेटी का जबरन मतांतरण कराकर निकाह कराया गया है। आरोपित का आपराधिक रिकार्ड है।
> **- रक्षपाल सिंह, पीड़ित के वकील**

> एसोसिएशन से सीधे तौर पर कोई शिकायत नहीं हुई। मामला संज्ञान में आने पर आरोपित अधिवक्ता से पूछताछ की गई है। उन्होंने आरोपों को नकारा है। फिर भी शादी-निकाह कराने वाले वकीलों और दस्तावेज तैयार करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसा कोई काम न करें, जिससे कानूनी पेशे की साख पर सवाल उठे।
> **- वीके सिंह, अध्यक्ष, शाहदरा बार एसोसिएशन**

विवाह, मतांतरण और निकाह के बाद क्रूरता करता था आरिफ

जागरण संवाददाता, आगरा



आरिफ हाशमी। जागरण

पूर्व आइएएस अधिकारी की बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाने वाला आरिफ हाशमी पहले युवतियों से हिंदू नाम रखकर दोस्ती कर मंदिर में विवाह करता था, फिर मतांतरण करा निकाह, उसके बाद क्रूरता पर उतर आता था। आगरा की होटल संचालक महिला से पहले वह गोरखपुर की युवती के साथ भी यही फार्मूला अपना चुका था। उससे आरिफ के एक बेटा भी है, जिसका उसने मुस्लिम नाम रखा है।

लखनऊ निवासी आरिफ हाशमी ने 20 वर्ष पहले लव जिहाद शुरू किया था। सबसे पहले उसने गोरखपुर की युवती को जाल में फंसाया था। उससे राणा सिंह बनकर दोस्ती की, आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद उसका मुस्लिम धार्मिक स्थल पर ले जाकर मतांतरण कराया और नाम बदलवा दिया। वहीं निकाह कर लिया। बेटा पैदा होने के कुछ समय बाद ही वह युवती से मारपीट करने लगा। परेशान होकर युवती ने तलाक ले लिया। बेटे को मां के पास ही छोड़ दिया। इसके बाद आरिफ ने पूर्व आइएएस अफसर की बेटी को जाल में फंसाया। उसके साथ भी आरोपित ने वही सलूक किया। आदित्य आर्य बनकर दोस्ती की, 2010 में लखनऊ में आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। एक वर्ष बाद अजमेर शरीफ ले जाकर मतांतरण कराया और निकाह कर लिया। कुछ दिन बाद महिला के ही होटल में रहकर उसका उत्पीड़न करने लगा। मारपीट करता, जलती सिगरेट से शरीर को जगह-जगह दागता। पुलिस को आशंका है कि आरोपित के जाल में पांच युवतियां और फंसी थीं।

महिला के होटल से लौटने के बाद आरोपित अय्याशी करता था, लड़कियां बुलाता था। शक होने पर महिला ने खुफिया कैमरा लगा दिया। इसमें उसकी पूरी करतूत रिकार्ड हो गई। महिला ने यह रिकार्डिंग पुलिस को सौंप दी है। महिला ने अपने साथ हुई ज्यादती के भी सुबूत दिए हैं। आरोपित इतनी मारपीट करता था कि उसके चेहरे पर निशान पड़ गए। महिला ने मारपीट के बाद का फोटो पुलिस को दिया है। यह फोटो भी विवेचना में साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

आरिफ हाशमी आलीशान होटलों रहता था। अपने अंदाज से उसने सपा में पैठ बना ली थी, जिसके चलते उसे गनर भी मुहैया कराया गया था। शीर्ष नेताओं से करीबी दर्शाकर वह लोगों पर रौब जमाता था। होटल में होने वाली उसकी पार्टियों में अधिकारी और नेता शामिल होते थे। सपा सरकार में वह पुलिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग के ठेके भी लेने लगा था।

यह है मामला

आरिफ हाशिम ने नाम बदलकर पूर्व आइएएस अधिकारी की विधवा बेटी से 2010 में आर्य समाज पद्धति से शादी कर ली। एक साल बाद असलियत सामने आने पर दबाव बनाकर उसका अजमेर में मतांतरण करा दिया। शनिवार को मारपीट करने पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला के चाचा उप्र पुलिस विभाग में उच्च पद पर रहे हैं, वर्तमान में राजनीतिज्ञ हैं।

कोविन प्लेटफार्म में दुनिया ने दिखाई दिलचस्पी

महामारी से मुकाबला ▸ कोरोना के खिलाफ जंग में अहम हथियार बनी भारत की डिजिटल उपलब्धि

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीकाकरण में पूरी दुनिया के लिए है यह स्वदेशी तकनीक

▸ पहले ग्लोबल कानक्लेव में 142 देशों के प्रतिनिधियों के सामने पीएम ने दिया 'वन वर्ल्ड, वन हेल्थ' का नारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण को सुचारू रूप से चलाने वाले कोविन प्लेटफार्म में दुनिया के 142 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। प्लेटफार्म की खासियत और उसकी तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने के लिए वर्चुअल तरीके से आयोजित पहले ग्लोबल कानक्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दुनिया के सभी देशों के लिए उपलब्ध है और स्थानीय जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ साझा लड़ाई की जरूरत बताते हुए उन्होंने 'वन वर्ल्ड, वन हेल्थ' का नारा दिया।

कोविन प्लेटफार्म की अहमियत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इसकी मदद से कोरोना रोधी वैक्सीन की 35 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं और उसका पूरा रिकार्ड भी सुरक्षित है। वैक्सीन लगाने वालों के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट भी उपलब्ध हैं और आसानी से उसका वेरीफिकेशन भी किया जा सकता है।

> 'भारतीय सभ्यता पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानती है। इस महामारी ने कई लोगों को इस दर्शन के मूलभूत सत्य का एहसास कराया है। इसीलिए, कोविड टीकाकरण के लिए हमारे तकनीकी प्लेटफार्म– जिसे हम कोविन कहते हैं– को ओपन सोर्स बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है।'
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



नई दिल्ली में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित किया। प्रेट्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान में लाभार्थियों को दी जाने वाली पहली और दूसरी डोज का पूरा रिकार्ड रखने वाले कोविन प्लेटफार्म का ओपन सोर्स संस्करण तैयार किया जा रहा ताकि कोई भी देश इसका अपने यहां इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं संबंधित देश अपने यहां की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं।

400 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए शामिल : विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की ओर संयुक्त रूप से आयोजित ग्लोबल कानक्लेव में 142 देशों के चार सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें यूरोपीय संघ और दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय से आए प्रतिनिधि भी शामिल थे। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और गुयाना के मंत्रियों का कहना था कि यह प्लेटफार्म उनके अपने देशों की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से निपटने में लाभकारी हो सकता है।

कोविन को सी-टीएपी में शामिल करने की पेशकश : कोविन प्लेटफार्म में दूसरे देशों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए भारत ने इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के कोविड टेक्नोलाजी एक्सेस पूल (सी-टीएपी) में शामिल करने की पेशकश की है। सी-टीएपी में शामिल होने से कोविन प्लेटफार्म की विश्वसनीयता काफी बढ़ जाएगी।

प्लेटफार्म के लिए कई देश कर रहें बातचीत

एनएचए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वियतनाम, साइप्रस, क्रोएशिया, जांबिया, मालदीव, मालावी, गुयाना, सियेरा लियोन और लाओ पीडीआर ने इस प्लेटफार्म को अपने यहां कोरोना टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखाई है और विदेश मंत्रालय के सहयोग से उनके साथ आगे की बातचीत चल रही है।

तकनीकी पहलुओं को समझाया

कानक्लेव में अलग से एक सत्र कोविन प्लेटफार्म की तकनीक की विस्तृत जानकारी देने के लिए रखा गया था। इसमें प्रतिनिधियों को बताया गया कि कैसे इस प्लेटफार्म को वैक्सीन की एक-एक डोज की सटीक जानकारी सुरक्षित रखने में सक्षम बनाया गया है। इस प्लेटफार्म की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति का सत्यापन किया जा सकता है। यही नहीं, टीकाकरण के डिजिटल सर्टिफिकेट में संबंधित व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर तक दर्ज हो सकता है और यह भी देखा जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति ने कौन-सी वैक्सीन ली है।

अगस्त के तीसरे सप्ताह में आ सकती है तीसरी लहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ एसबीआइ ने जताई मध्य सितंबर के बाद लहर के पीक पर पहुंचने की आशंका

कोरोना के नए मामले भले ही कम हो रहे हैं और तीसरी लहर को लेकर विज्ञानी एकमत नहीं हैं, लेकिन एसबीआइ का मानना है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह के बाद कोरोना संक्रमण के नए मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। कम-से-कम एक माह के बाद तीसरी लहर का पीक आएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि गत सात मई को दूसरी लहर का पीक आया था और जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद कोरोना संक्रमण के नए मामलों का स्तर रोजाना 10 हजार तक आ सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण के बावजूद कई देशों में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। इजरायल का हवाला देते हुए कहा गया है कि इजरायल की 60 फीसद आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। यहां तक कि इजरायल के 12-18 साल के 33 फीसद बच्चों को टीके की पहली डोज मिल चुकी है, तो 23.8 फीसद को दोनों डोज। इसके बावजूद इजरायल में कोरोना संक्रमण के नए मामले जून के आखिरी सप्ताह से बढ़ने लगे हैं। भारत में अभी सिर्फ 4.6 फीसद आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो पाया है और 20.8 फीसद लोगों को टीके की एक डोज मिली है, जो आबादी के फीसद के लिहाज से अमेरिका, ब्रिटेन, इजरायल, स्पेन व फ्रांस के मुकाबले कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिक समृद्ध देश या अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में कोरोना से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा व राजस्थान जैसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में प्रति 10 लाख पर होने वाली मृत्यु महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हिमाचल के मुकाबले कम रही।

एसबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस जैसे देशों में डेल्टा स्ट्रेन पाए गए हैं। ब्रिटेन में ठीक-ठाक टीकाकरण के बावजूद कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं। भारत में डेल्टा प्लस वैरिएंट के 51 मामले 12 राज्यों में पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सात दिनों से कोरोना के नए मामले 45,000 के आसपास हैं।

भारत को जल्द मिलेगी अमेरिकी वैक्सीन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अगले कुछ दिनों में अमेरिकी सरकार की तरफ से भारत को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की डोज देश में पहुंचने वाली हैं। दोनों देशों के बीच इसको लेकर लगातार संपर्क बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि संभवतः 25 से 30 लाख डोज दो हफ्तों के भीतर पहुंच जाएंगी। इस मदद से देश में टीकाकरण को गति मिल सकती है। इसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी क्षेत्र के कुछ चयनित अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों को भेजा जाएगा। ये वैक्सीन अमेरिका की तरफ से दुनिया के विभिन्न देशों को मदद के तौर पर दी जाने वाली आठ करोड़ डोज का हिस्सा है।

दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता के बारे में जानकारी रखने वालों का कहना है कि वैक्सीन से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। इसमें मदद के तौर पर मिलने वाली वैक्सीन भी शामिल है। इसको लेकर बहुत ज्यादा पेंच अब नहीं है। अमेरिकी प्रशासन की तरफ से पहले ज्यादा जरूरतमंद या उन देशों को वैक्सीन देने को प्राथमिकता दी जा रही है जहां इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश एवं पाकिस्तान को अमेरिकी वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है।

भारतीय वैक्सीन को मंजूरी को लेकर भी बातचीत जारी : दोनों देशों के अधिकारियों के बीच भारतीय वैक्सीन को अमेरिका में मंजूरी देने संबंधी मुददे पर भी बात हो रही है। पिछले दिनों जी-20 देशों की बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के साथ मुलाकात में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी वैक्सीन का मुद्दा उठाया था।



कोरोना से जंग में वैक्सीन अहम हथियार है। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

भारत में अमेरिकी वैक्सीन के उत्पादन पर वार्ता

भारत में अमेरिकी वैक्सीन बनाने की संभावनाओं को लेकर भी बात हो रही है। अमेरिका की दो वैक्सीन निर्माता कंपनियां माडर्ना और फाइजर ने भारत में वैक्सीन बनाने की बात कही थी लेकिन हाल के हफ्तों में इन दोनों कंपनियों की तरफ से इस बारे में किसी भी तरह की प्रगति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि एक अन्य अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी जानसन एंड जानसन की भारतीय अधिकारियों से निश्चित तौर पर बात हो रही है। इस महीने के अंत तक जानसन एंड जानसन की दो डोज वाली वैक्सीन के भारत में उपलब्ध हो जाने की संभावना जताई जा रही है। जानसन एंड जानसन सिंगल डोज वैक्सीन भी भारत में बनाने को इच्छुक है।

राज्यों के पास अभी 2 .01 करोड़ डोज उपलब्ध हैं : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोरोना रोधी वैक्सीन की 2.01 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक इन्हें 36.37 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं।

मंत्रालय ने कहा कि देश में टीकाकरण की रफ्तार को गति देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही दूसरे देशों से वैक्सीन मंगाने की भी कोशिश की जा रही है।

वहीं, कोविन प्लेटफार्म के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को रात 10 बजे तक 44,59,887 डोज दी जा चुकी थीं। कुल 42,139 टीकाकरण केंद्रों संचालित किए गए, जिनमें 40,222 सरकारी और 1917 निजी केंद्र शामिल हैं। अब तक कुल 35.23 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 28.75 करोड़ लोगों को पहली और 6.48 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लगाई गई हैं।

सोमवार रात 10 बजे तक किस राज्य में कितने टीके

उत्तर प्रदेश	8.23 लाख
मध्य प्रदेश	4.11 लाख
महाराष्ट्र	3.22 लाख
गुजरात	2.97 लाख
बंगाल	2.95 लाख
बिहार	1.08 लाख
हरियाणा	1.03 लाख
उत्तराखंड	0.96 लाख
छत्तीसगढ़	0.89 लाख
झारखंड	0.85 लाख
दिल्ली	0.80 लाख
हिमाचल	0.60 लाख
जम्मू-कश्मीर	0.54 लाख
राजस्थान	0.44 लाख
पंजाब	0.43 लाख

कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए केंद्र ने कल बुलाई बैठक

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है, महामारी से प्रतिदिन होने वाली मौतें भी कम हुई हैं और सक्रिय मामले भी घट रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पूर्वोत्तर के राज्यों समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें संबंधित राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की जाएगी।

केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उससे निपटने में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए तीन दिन पहले ही छह राज्यों में अपनी टीमें भेजी थीं। इनमें पूर्वोत्तर के तीन राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा भी शामिल थे।

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इन राज्यों के शीर्ष अधिकारियों की सात जुलाई को बैठक बुलाई है। यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होने की संभावना है।

बैठक में संबंधित राज्यों में कोविड प्रबंधन के क्रियान्वयन का आकलन किया जाएगा, विशेषरूप से जांच, निगरानी और कंटेनमेंट संबंधी उपायों का। कोरोना से बचाव के नियमों के अनुपालन, अस्पताल में बेड, एंबुलेंस, वेंटिलेटर, आक्सीजन की उपलब्धता के साथ ही टीकाकरण की प्रगति का जायजा भी लिया जाएगा।

88 दिन बाद सबसे कम 723 मौतें : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते देश में 88 दिन बाद 24 घंटे में सबसे कम 723 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों में तीन हजार से ज्यादा की कमी आई है और एक्टिव केस पांच लाख से नीचे बने हुए हैं। पिछले 53 दिनों से नए मामलों से ज्यादा मरीजों के ठीक होने का सिलसिला बना हुआ है और अब तक 2.97 करोड़ लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं।

सोमवार सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	39,796
कुल मामले	3,05,85,229
मौतें	723
कुल मौतें	4,02,728
कुल सक्रिय मामले	4,82,071
ठीक होने की दर	97.11 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.61 फीसद
मृत्यु दर	1.32 फीसद
जांचें (रविवार)	15,22,504
कुल जांचें	41,97,77,457

वैक्सीन न लेने वालों को नौकरी पर जाने से नहीं रोका जा सकता

आइजल, आइएएनएस : टीकाकरण के लिए मिजोरम सरकार द्वारा जारी नियमावली पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मिजोरम सरकार के टीकाकरण के सिलसिले में जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को मनमाना करार दिया है। कहा कि किसी भी व्यक्ति को आजीविका के लिए जाने से नहीं रोका जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन है।

मिजोरम सरकार ने 29 जून को जारी एसओपी में राज्य के लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। नियमावली में कहा गया है कि जो लोग टीका नहीं लगवाएंगे, वे खरीदारी के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे नौकरी या आजीविका के सिलसिले में भी घर से नहीं निकल पाएंगे। दुकान में काम, ड्राइविंग या अन्य कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे, जिसमें अन्य लोग उनके आसपास रहते हों। इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई कर हाई कोर्ट में जस्टिस माइकल जोथांखम और जस्टिस नेल्सन सेलो की पीठ ने मिजोरम सरकार के एसओपी को मनमाना करार दिया। कहा कि टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करना ठीक है, लेकिन टीका लेने और न लेने वालों में मुश्किल पैदा करने वाला भेद करना उचित नहीं है। यह संविधान के प्रविधानों के खिलाफ है। इसलिए एसओपी के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।

पूरे देश को एक सूत्र में बांधना ही लक्ष्य : मोहन भागवत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सोमवार को गाजियाबाद में वसुंधरा स्थित एक इंस्टीट्यूट में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच व अन्य कई प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने सभी को मिशन 'अखंड भारत' के तहत काम करने को कहा। सरसंघचालक ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना देश के हिंदुओं व मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए हुई हैं। पूरे देश को एक सूत्र में बांधना ही अब हम सबका लक्ष्य है।

रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के तत्कालीन सलाहकार रहे डा.ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक का विमोचन करने के बाद मोहन भागवत दिल्ली लौट गए थे। सोमवार सुबह 9.30 बजे वह वसुंधरा पहुंचे। सुबह 10 बजे पहली बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के गोसेवा प्रकोष्ठ, सेवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, पर्यावरण व बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजकों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब समय है मिशन 'अखंड भारत' के तहत पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का। इसके लिए लोगों से जुड़ने के साथ ही त्याग भी करना होगा। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में मंच ने बेहतर काम किया है। अब इस पर और मेहनत से काम करने व युवाओं को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का समय है।



वसुंधरा सेक्टर-चार स्थित मेवाड़ इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी। सौ. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच

उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों को भी समझना होगा कि आपसी भाईचारे व शांति में ही सबका भला है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ 2021-22 में काम करने के निर्देश दिए। सरसंघचालक ने तीन तलाक, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही गुलाम कश्मीर की समस्या पर भी चर्चा की। बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह डा. कृष्ण गोपाल, संपर्क प्रमुख रामलाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, राष्ट्रीय संयोजक शाहिद अख्तर, अफजाल, गिरीश जुयाल समेत 54 पदाधिकारी मौजूद थे।

शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने का करें प्रयास : सरसंघचालक ने दोपहर बाद पदाधिकारियों के साथ दूसरी बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय के साथ मुस्लिम समाज को भी बदलना होगा। तीन तलाक जैसे मुद्दे तभी खत्म होंगे जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। ऐसे में समाज के युवाओं को शिक्षा की ओर लेकर जाना होगा। उन्हें समझाना होगा कि वे इस देश के वासी हैं और उन्हें इसके विकास के लिए काम करना है। अखंड भारत का सपना तभी साकार होगा, जब सभी एक दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। बैठक में सेवा प्रकोष्ठ के ठाकुर राजा सिंह, महिला प्रकोष्ठ की रेशमा, पर्यावरण प्रकोष्ठ के फारूख खान, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के शिराज कुरैशी, उलेमा प्रकोष्ठ के कोकब मुज्तबा व विशाल भारत संस्थान के राजीव समेत अन्य संयोजक मौजूद थे।

अखाड़ा परिषद ने किया संघ प्रमुख का समर्थन

जासं, प्रयागराज : अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के इस कथन का समर्थन किया है कि 'सभी भारतीयों का डीएनए एक है।' परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने प्रयागराज में जारी बयान कहा कि यह सत्य है कि भारत में रहने वाले सनातन मतावलंबियों के साथ सभी मतों को मानने वाले लोगों का डीएनए एक है। लालच और दबाव में आकर काफी लोगों ने अपना मत बदल लिया, लेकिन सदियों पहले उनके पूर्वज हिंदू ही थे।

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि अखाड़ा परिषद हिंदुत्व की विचारधारा और सनातन संस्कृति के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है। जो लोग मत (धर्म) बदल चुके हैं, उनकी घर वापसी की मुहिम तेज की जाएगी। इसके लिए किसी पर न दबाव डाला जाएगा, न ही कोई लालच देंगे। महंत ने कहा कि हम सनातन धर्म व संस्कृति की खासियत, उसके वैभव को बढ़ाएंगे ताकि हमें छोड़कर जाने वाले पुनः उसे अपनाने पर विवश हो जाएं। उन्होंने मुस्लिम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों से अपील की कि वह हिंदू धर्म में वापस आएं।

डीएनए संबंधी भागवत के बयान पर बोला विपक्ष, कथनी व करनी एक हो

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के सभी भारतीयों का डीएनए एक होने संबंधी बयान पर दिग्विजय सिंह, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। भागवत ने यह भी कहा था कि मुस्लिमों के देश छोड़कर जाने के लिए कहने वाले खुद को हिंदू नहीं कह सकते।

आरएसएस प्रमुख के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर वह अपने शब्दों पर कायम हैं तो उन्हें उन सभी भाजपा नेताओं को पद से हटाने के निर्देश देने चाहिए जिन्होंने निर्दोष मुस्लिमों का उत्पीड़न किया है। भागवत का बयान टैग करते हुए दिग्विजय सिंह ने तंज कसा, 'भागवत जी, क्या आप अपने इन विचारों को अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचाएंगे? क्या आप इन्हें मोदी-शाह जी और भाजपा के मुख्यमंत्रियों को भी पहुंचाएंगे? अगर आप अपने शिष्यों को अपने इस विचार का पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक बन जाऊंगा'

आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि कायरता, हिंसा और हत्या गोडसे की हिंदुत्व की विचारधारा का अभिन्न अंग हैं और मुस्लिमों के साथ उन्मादी भीड़ की हिंसा इसी का परिणाम है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा। लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुश्त पनाही हासिल है।'

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संघ परिवार, भाजपा और सरकार जो कहती है और जो करती है, उसमें अंतर होता है। आरएसएस प्रमुख का बयान 'मुंह में राम बगल में छुरी' की तरह है। उनका बयान लोगों को अविश्वसनीय लगता है। जब तक आरएसएस, भाजपा एंड कंपनी और इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच और कार्यशैली में सर्व समाज हितैषी सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक इनकी बातों पर मुस्लिम समाज विश्वास नहीं करेगा। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि भाजपा की जहां भी सरकारें हैं, वे आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर चल रही हैं।

बीएसपी के लोकसभा सदस्य दानिश अली ने कहा, 'कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अगर वे उन्मादी भीड़ की हिंसा के प्रति इतने ही गंभीर हैं तो वे इसके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाते और उसे लागू क्यों नहीं करते।'

नकवी बोले, आरएसएस की सकारात्मक छवि से बौखलाया गुमराही गैंग



मुख्तार अब्बास नकवी बोले, संघ की सोच सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रवाद से भरपूर है। फाइल/इंटरनेट मीडिया

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरएसएस का बचाव किया और हमला बोलने वालों को गुमराही गैंग करार दिया। नकवी ने कहा कि आरएसएस के जो विचार हैं और जो सोच है वह हमेशा ऐसी ही रही है। उसकी सोच सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रवाद से भरपूर है। लेकिन पहले गुमराही गैंग का दुष्प्रचार हावी था और अब आरएसएस की सकारात्मक छवि बनती देखकर यह गैंग बौखला गया है। पिछले कुछ वर्षों से आरएसएस के कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से होते हैं और लोग उनके विचार और उनके काम को देख और समझ पा रहे हैं। भागवत के बयान से समाज में जहां कहीं भी भ्रम की स्थिति होगी, वहां स्पष्टता का रास्ता साफ होगा।

संघ की बैठक से दूर रखे जाएंगे राजनीतिक लोग

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्यधाम में नौ से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चार दिवसीय चिंतन शिविर (बैठक) है। उप्र व उत्तराखंड चुनाव के पहले हो रही बैठक में भले ही राजनीतिक चर्चा हो, लेकिन राजनीतिक लोगों को दूर ही रखा गया है। बैठक में अखिल भारतीय टोली पदाधिकारी और 11 क्षेत्र प्रचारक शमिल होंगे, जबकि 41 प्रांत प्रचारक वर्चुअल भाग लेंगे। बैठक की तैयारियों व व्यवस्थाओं को जिम्मेदारी संघ के स्वयंसेवक संभालेंगे।

बैठक की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी, दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव अतुल जैन, संगठन सचिव अभय महाजन, कोषाध्यक्ष वसंत पंडित आदि चित्रकूट में डेरा जमाए हैं। रविवार को चित्रकूट आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप्र सरकार के मंत्री डा. महेंद्र सिंह ने संघ पदाधिकारियों से बैठक को लेकर मंत्रणा की थी। सूत्र बताते हैं कि मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी चित्रकूट आ जाएंगे और बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा। शिविर को राजनीतिक रंग न दिया जाए, इसलिए राजनीतिक लोगों को बैठक से दूर रखने की तैयारी है। पांच दिन आने वाले अतिथियों के भोजन-नाश्ता, ठहरने आदि की व्यवस्था संघ के कार्यकर्ता देखेंगे। व्यवस्थाएं आरोग्यधाम के अंदर ही होंगी। पांच दिन संघ से जुड़े पदाधिकारी परिसर से बाहर नहीं जाएंगे।

योगी सरकार ने की थी सीबीआइ जांच की सिफारिश

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

योगी सरकार ने गोमती नदी चैनलाइजेशन परियोजना व गोमती नदी रिवरफ्रंट डेवलमेंट में हुई वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी। रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआइ ने अपनी पहली एफआइआर 30 नवंबर, 2017 को दर्ज की थी। यह एफआइआर लखनऊ के गोमतीनगर थाने में सिंचाई विभाग के आठ अधिकारियों व अन्य के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे को आधार बनाकर की गई थी।

सीबीआइ दो चरणों में इस घोटाले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पहली एफआइआर के तहत करीब 1031 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए 12 कामों की जांच की जा रही है। जबकि 407 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए 661 कामों की आरंभिक जांच के बाद 189 आरोपितों के विरुद्ध दूसरी एफआइआर दर्ज की गई है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए हुआ करोड़ों रुपये का खेल : जांच में सामने आया है कि तत्कालीन अधिकारियों की सांठगाठ से निजी फर्मों और ठेकेदारों को नियमों को दरकिनार कर काम दिए गए। इसके लिए फर्जी दस्तावजों का उपयोग किया गया।

मिलीभगत से एल-2 और एल-3 फर्मों के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए और बिना टेंडर के हाई रेट पर कामों का आवंटन किया गया। चहेती फर्मों को काम देने के लिए राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन भी नहीं दिए गए। पूर्व में सीबीआइ ने 20 नवंबर, 2020 को सिंचाई विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव (अब सेवानिवृत्त) और वरिष्ठ सहायक राजकुमार को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। रूप सिंह दोनों एफआइआर में नामजद आरोपित हैं।

यूपी कैडर के अधिकारी ने प्रभावित की जांच

सीबीआइ ने करीब चार साल पहले घोटाले में केस दर्ज किया था, लेकिन अब तक इस मामले में केवल दो आरोपितों की ही गिरफ्तारी हो सकी है। एक बार फिर इस मामले की सीबीआइ जांच ने रफ्तार पकड़ी है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पूर्व में सीबीआइ में तैनात रहे यूपी कैडर के एक अधिकारी के प्रभाव की वजह से जांच प्रभावित रही।

राष्ट्रीय संस्करण
मंगलवार 6 जुलाई, 2021
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की पिरामिड स्कीम पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली : एमवे और टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर सरकार रोक की तैयारी कर रही है। ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने ड्राफ्ट तैयार किया है। इस पर 21 जुलाई लोग सुझाव दे सकेंगे। 2016 की शुरुआत में सरकार ने एडवाइजरी के तौर पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। ड्राफ्ट में इन पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रविधान किया गया है। ऐसी स्कीम में ग्राहकों को अपने नीचे नए ग्राहक जोड़ने पर कमीशन मिलता है। (प्रेट्र)

ओईएम की ऑटो उद्योग में बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वाहन निर्माताओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा।
– नितिन गडकरी,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री



सेंसेक्स	52,880	395.33
निफ्टी	15,834.35	112.15
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 46,408	₹ 69
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 69,035	₹ 251
डॉलर	₹ 74.31	₹ 0.43
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 76.44	

अप्रैल–जून में मकानों की बिक्री में 83% की बढ़ोतरी

18 फीसद की वृद्धि साल की पहली छमाही में बिक्री में

- सात प्रमुख शहरों की रिपोर्ट में सामने आई तस्वीर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद इस साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल-जून में मकानों की बिक्री में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 83 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के प्रमुख सात शहरों में यह बढ़ोतरी रही। साल की पहली छमाही में मकानों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 18 फीसद का इजाफा रहा। रिसर्च फर्म जेएलएल की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इन सात शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई व पुणे शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल-जून में इन सात शहरों में 19,635 आवासीय यूनिट की बिक्री हुई, जो सालभर पहले 10,753 यूनिट थी। हालांकि जनवरी-मार्च के अप्रैल-जून में बिक्री में 23 फीसद की गिरावट दर्ज की गई। जनवरी-मार्च में 25,583 यूनिट की बिक्री की गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जनवरी-जून में 45,218 आवासीय यूनिट की बिक्री की गई, सालभर पहले 38,204 यूनिट थी। 2020 में कोरोना के कारण जनवरी-मार्च की तुलना में अप्रैल-जून में बिक्री में 61 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी। जनवरी-मार्च, 2020 में 27,451 यूनिट और अप्रैल-जून, 2020 में 10,753 यूनिट की बिक्री हुई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल जनवरी से जून के दौरान 61,010 नई आवासीय यूनिट लांच की गईं, जो पिछले साल के मुकाबले 10 फीसद अधिक है। इस दौरान सबसे अधिक हैदराबाद में एक तिहाई यूनिट लांच की गईं। जेएलएल ने कहा कि बिक्री में बढ़ोतरी के बावजूद इस साल की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही की इंवेंटरी में दो फीसद की बढ़ोतरी रही। दूसरी तिमाही में इन सात शहरों में 4,78,172 यूनिट की इंवेंटरी थी।

चालू सीजन में गेहूं की रिकार्ड खरीद, पुख्ता भंडारण बंदोबस्त का दावा

सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंची 84 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि



गेहूं उत्पादक राज्यों ने भी भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास किया है ● फाइल फोटो

50 लाख किसानों से 4.33 करोड़ टन की खरीद

- राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था भी हो रही लोकप्रिय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: रबी मार्केटिंग सीजन में इस बार रिकार्ड तोड़ 4.33 करोड़ टन से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर ने गेहूं खरीद में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कुल 50 लाख किसानों से गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल 43 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया था।

इस बार देश के सभी राज्यों के किसानों के गेहूं का शत प्रतिशत भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है। गेहूं की सरकारी खरीद का ब्योरा देते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि इस रबी सीजन में 84 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सीधा भुगतान किसानों के बैंक खाते में किया गया है। पांडेय सोमवार को वर्चुअल प्रेसवार्ता में बोल रहे थे।

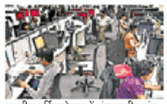
गेहूं के भारी स्टॉक के रखरखाव को लेकर जताई जा रही चिंता के बारे में पांडेय ने बताया कि खरीद सीजन के पहले ही तैयारियां कर ली गई हैं। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) की मौजूदा भंडारण क्षमता में 10 फीसद तक की बढ़ोतरी कर ली थी। गेहूं उत्पादक राज्यों ने भी भंडारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास किया है।

एफसीआइ के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक आतिश चंद्रा ने बताया कि खाद्यान्न भंडारण को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। इस बार केवल 17.18 लाख टन गेहूं का भंडारण अन साइंटिफिक तरीके से बाहर ढककर करना पड़ा है।

आतिश चंद्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का तीसरा और चौथा चरण शुरू होने से ज्यादा से ज्यादा अनाज उपभोक्ताओं के वितरण के लिए जा रहा है, जिससे भंडारण में काफी सहूलियत मिली है। इसके लिए कुल 2.78 करोड़ खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। एफसीआइ का दावा है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह तक बाहर रखा अनाज सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया जाएगा।

खाद्य सचिव पांडेय ने बताया कि 25 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2021 और एक अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 के दौरान कुल 9.45 करोड़ टन खाद्यान्न जारी किया गया है। जहां पहले हर महीने सेंट्रल पूल से 50 लाख टन अनाज का उठाव होता था, वह इस समय बढ़कर 77.40 लाख टन हो गया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' स्कीम की सफलता के बारे में पांडेय ने बताया कि जून में लगभग डेढ़ करोड़ लेनदेन हुआ है। अब तक कुल 29.3 करोड़ लेनदेन पोर्टेबिलिटी से हुआ है। इस स्कीम के माध्यम से 20 हजार करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है।

जून में दिखी सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में नरमी



भारतीय सर्विस सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय मांग लगातार कम चल रही है ● फाइल फोटो

पिछले साल जुलाई के बाद से सर्विस सेक्टर पीएमआइ अब तक के निचले स्तर 41.2 पर

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी के दबाव में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट का दौर जारी है। जून में सर्विस सेक्टर का परजेचिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) 41.2 रहा, जो मई में 46.4 रहा था। जुलाई, 2020 के बाद से पिछले माह गतिविधियों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। 50 पीएमआइ गतिविधियों में स्थिरता, इससे नीचे होने पर गतिविधियों में कमी व ऊपर होने पर गतिविधियों में विस्तार का पता चलता है।

आइएचएस मार्किट की इकोनॉमिक्स एसोसिएट डायरेक्टर पॉलिएना डि लीमा ने कहा, 'भारत कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पहले से यह अनुमान था कि सर्विस सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जून का पीएमआइ डाटा नए बिजनेस, आउटपुट और रोजगार के तेज गिरावट दिखा रहा है। हालांकि पहली लहर की तुलना में स्थिति बेहतर है।' भारतीय सर्विस सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय मांग लगातार कम चल रही है। जून में लगातार 16वें महीने नए निर्यात ऑर्डर में गिरावट आई।

इस बीच, कुल बिजनेस सेंटिमेंट भी जून में लगातार तीसरे महीने गिरा है। पिछले साल अगस्त के बाद से यह निचले स्तर पर पहुंच गया है। लीमा ने कहा, 'महामारी की अनिश्चितता से सेवा क्षेत्र की कंपनियों का भरोसा कमजोर हुआ है। भारत सरकार टीकाकरण बढ़ा रही है और इस साल के आखिर तक पूरी आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है महामारी नियंत्रण में आएगी व अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।'

रिटायर हुए जेफ बेजोस, अब एंडी जेसी के हाथ अमेजन की कमान

27 साल पहले जेफ बेजोस ने ही बनाई थी कंपनी, आज 1.7 लाख करोड़ डॉलर की कंपनी है अमेजन



जेफ बेजोस ● फाइल फोटो



एंडी जेसी ● फाइल फोटो

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएसः ठीक 27 साल पहले पांच जुलाई, 1994 को अमेजन की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस आधिकारिक रूप से रिटायर हो गए हैं। कंपनी की कमान अब अमेजन वेब सर्विसेज के एक्जीक्यूटिव एंडी जेसी के हाथ होगी। उनका नाम अमेजन डॉट कॉम के प्रेसिडेंट एवं सीईओ के तौर पर अपडेट कर दिया गया है। अमेजन इस समय 1.7 लाख करोड़ डॉलर की कंपनी है।

बेजोस ने मई में रिटायर होने का एलान किया था। उन्होंने पांच जुलाई से जेसी को यह जिम्मेदारी देने की बात कही थी। उन्होंने रिटायरमेंट के लिए यह तारीख चुनी, क्योंकि इससे उनकी संवेदनाएं जुड़ी हैं। अमेजन की स्थापना के तीन साल बाद यानी 1997 में जेसी इससे जुड़े थे। कई अलग-अलग भूमिकाओं में रहने के बाद उन्होंने अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) की स्थापना की और उसका नेतृत्व करते रहे। अप्रैल, 2016 में वह एब्ल्यूएस के सीईओ बने।

अमेजन का क्लाउड कारोबार संभालने वाली इकाई एडब्ल्यूएस ने इस साल मार्च तिमाही में कारोबार में 32 फीसद का जबर्दस्त उछाल दर्ज किया था।

बेजोस एयरोस्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजन के भी संस्थापक हैं, जो अंतरिक्षयानों की लागत कम करने और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही जेफ बेजोस वाशिंगटन पोस्ट के भी मालिक हैं। बेजोस ने ब्लू ऑरिजन द्वारा तैयार टूरिज्म रॉकेट न्यू शेपार्ड में सवार होकर 20 जुलाई को अपने भाई मार्क के साथ अंतरिक्ष में जाने का एलान भी किया है।

जेफ बेजोस ने फरवरी में ही कहा था कि वह करियर की ऊंचाई पर रहते हुए सीईओ का पद छोड़ेंगे, ताकि इनोवेशन पर ध्यान दे सकें।

ई–कामर्स नियमों के ड्राफ्ट पर सुझाव के लिए समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कामर्स) नियम, 2020 में प्रस्तावित संशोधनों पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए समयसीमा 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले इस पर सुझाव के लिए छह जुलाई तक का समय दिया गया था।

उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से तीन जुलाई को बुलाई गई बैठक में कई ई-कामर्स कंपनियों ने सरकार से टिप्पणियों के लिए समयसीमा बढ़ाने की अपील की थी। इस ड्राफ्ट को मंत्रालय ने 21 जून को जारी किया था। इसके तहत ई-कामर्स प्लेटफार्म की अनुचित गतिविधियों पर लगाम लगाना संभव होगा। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस आफिसर/ग्रीवांस रिड्रेसल आफिसर की भी नियुक्ति करनी होगी। किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जानकारी मांगने पर कंपनियों को 72 घंटे के भीतर जवाब देना होगा।

बाजार में तेजी कायम, बैंकिंग व मेटल ने दी गति

बेहतर संकेत

- बीएसई के सेंसेक्स में दर्ज की गई 395.33 अंकों की बढ़त
- एसबीआइ के शेयरों के सबसे ज्यादा 1.92 फीसद की तेजी



मुंबई, प्रेट्रः हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजारों ने बढ़त से शुरुआत की है। मिले-जुले वैश्विक संकेतों और बैंकिंग, मेटल व एनर्जी स्टॉक्स में खरीद से बाजार को गति मिली। चार दिन की गिरावट के बाद रुपये में सुधार ने भी बाजार को आगे बढ़ने में मदद की।

सोमवार को बीएसई का सेंसेक्स 395.33 अंक बढ़कर 52,880 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 112.15 अंक की तेजी के साथ 15,834.35 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में एसबीआइ ने सबसे ज्यादा 1.92 फीसद की बढ़त हासिल की। टाटा स्टील, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एमएंडएम और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई। मूल्य के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एफडीएफसी लिमिटेड और आइसीआइसीआइ बैंक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इनसे इतर, टेक महिंद्रा, डॉ. रेड्डीज लैब, एचसीएल टेक, टाइटन, भारती एयरटेल, टीसीएस और सन फार्मा के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'अमेरिका में रोजगार के बेहतर आंकड़ों से वहां की अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत मिला है। इससे फेडरल रिजर्व की ओर से समय से पहले दरें बढ़ाए जाने की निवेशकों की चिंता भी कम हुई है। इन सभी सकारात्मक संकेतों से बाजार में तेजी आई। मिड कैप और स्माल कैप भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।' हालांकि इन सकारात्मक संकेतों के बीच सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में गिरावट से निवेशकों की धारणा पर कुछ प्रतिकूल असर रहा, जिससे बाजार ज्यादा बढ़त हासिल नहीं कर पाए। रिलायंस सिक्युरिटीज के स्ट्रेटजी हेड बिनोद मोदी का कहना है कि मौजूदा हालात में कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले आने वाले दिनों में चिंता बढ़ा सकते हैं।

कई देशों में कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट के कारण बढ़ते संक्रमण के कारण चिंता बढ़ी है। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बेहतर संकेतों के बाद भी बाजार बहुत तेज कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यूरोपीय बाजारों में मिला-जुला कारोबार दिखा है। एशियाई बाजारों में चीन एवं दक्षिण कोरिया के बाजार बढ़त में रहे, जबकि हांगकांग और जापान के शेयरों में गिरावट आई। इस बीच, रुपया 43 पैसे मजबूत होकर प्रति डॉलर 74.31 पर बंद हुआ।

सोना और चांदी में बढ़त



राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को प्रमुख कीमती धातुओं में बढ़त दर्ज की गई। सोना 69 रुपये बढ़कर 46,408 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले सत्र में यह 46,339 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी भी 251 रुपये सुधरकर 69,035 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 1,793 डॉलर और चांदी का भाव 26.60 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) रहा।

राष्ट्रीय फलक

मोदी का योगी को निर्देश, कल्याण को मिले अच्छे से अच्छा इलाज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके पुत्र राजबीर से फोन पर बात की। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि कल्याण सिंह के इलाज में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिलना चाहिए। वहीं शाह ने इलाज में लगे डाक्टरों से भी बात की और आग्रह किया कि कोई कसर न छोड़ें।

भाजपा के शीर्ष नेताओं में शामिल रहे कल्याण सिंह की भूमिका राम मंदिर आंदोलन में रही है। वहीं जातिगत राजनीति के गढ़ उत्तर प्रदेश में उनका जातीय प्रभाव भी गहरा रहा है। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव है।

अपनी उम्र के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए कल्याण को मोदी सरकार के समय में ही राज्यपाल भी बनाया गया था। प्रधानमंत्री के साथ उनका रिश्ता सहज रहा है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने सोमवार की सुबह राजबीर को फोन किया और आश्वस्त किया कि वह ठीक हो जाएंगे।

शाह ने डाक्टरों से भी बात की। बताया जाता है कि डाक्टरों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कल्याण के स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखी जा रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

कल्याण सिंह की हालत में मामूली सुधार

जासं, लखनऊ: उप्र के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत स्थिर है। उन्हें रविवार शाम एसजीपीजीआइ (लखनऊ) के क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के आइसीयू में भर्ती किया गया था। वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम उनके उपचार का निरीक्षण कर रही है। सभी संबंधित प्रारंभिक जांचें कराई जा रही हैं और आने वाली रिपोर्ट के अनुसार ही उनकी स्थिति का प्रबंधन भी किया जा रहा है। संस्थान प्रशासन का कहना है कि रविवार की तुलना में सोमवार को उनकी स्थिति में हल्का सुधार है।

गुजरात में अब सिर्फ ई–गजट का होगा प्रकाशन

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात सरकार अब किसी भी गजट का मुद्रण व प्रकाशन नहीं करेगी। पेपरलेस गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने वेबसाइट पर ई-गजट सार्वजनिक करने का फैसला किया है। जरूरतमंद लोग वेबसाइट से गजट की प्रति प्राप्त कर सकेंगे। गजट पर क्यूआर कोड अंकित होगा। इससे प्रतिवर्ष 35 मीट्रिक टन कागज की बचत होगी।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को गांधीनगर स्थित अपने कार्यालय में ई-गजट की वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए कहा कि सरकार गवर्नेंस को पारदर्शी एवं उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के सभी गजट अब इलेक्ट्रानिक (ई) स्वरूप में प्रकाशित किए जाएंगे। सभी सरकारी विभागों के 30 साल पुराने साधारण व असाधारण गजट भी आगामी एक माह में इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट से गजट की प्रति डाउनलोड कर उसका उपयोग कर सकेगा। गजट पर क्यूआर कोड अंकित होंगे, जिसके जरिये उसकी वैधता को जांचा-परखा जा सकेगा। इससे सरकार को गजट की प्रकाशित कापी रखने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी।

ग्वालियर की जिस अर्चना से पीएम ने की थी बात, वह पति के इलाज में हुई कर्जदार

वरुण शर्मा, ग्वालियर



अपने चाट के ठेले पर अर्चना। नईदुनिया

आयुष्मान योजना में निर्धारित बीमारी का पैकेज होता है और तय राशि से ज्यादा अस्पताल भी नहीं ले सकता है। लाभ लेने वाले का न के बराबर ही खर्च आता है। अर्चना शर्मा के केस में रिकार्ड दिखवाते हैं, उन्हें क्यों कम लाभ मिला?
– आशीष तिवारी, अपर कलेक्टर व नोडल अधिकारी, आयुष्मान योजना, ग्वालियर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर की जिस अर्चना शर्मा से आनलाइन बात कर उसे अपना काम शुरू करने की बधाई दी थी, वह पति के इलाज के कारण कर्जदार हो गई है। पति की बीमारी में करीब एक लाख रुपये खर्च हो गए और आयुष्मान कार्ड होते हुए भी सिर्फ 27 हजार रुपये का लाभ मिला। अर्चना अब कर्ज की रकम वापस मांगने वालों से परेशान है। उसने आर्थिक सहायता के लिए जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई, पर एक रुपये की भी मदद किसी से नहीं मिली।

अर्चना ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत चाट का ठेला लगाकर रोजगार की शुरुआत की थी। तब प्रधानमंत्री ने नौ सितंबर, 2020 को अर्चना से बात की थी। मोदी ने कहा था कि वह ग्वालियर आएंगे तो अर्चना के हाथ से बनी आलू टिक्की खाएंगे। बताया जाता है कि अब पति राजेंद्र शर्मा को आंत संबंधी बीमारी होने के कारण अर्चना को चार महीने ठेला बंद रखना पड़ा। पहले सरकारी अस्पतालों में प्रयास किया, लेकिन इलाज नहीं मिला। मजबूरन शहर के एक निजी अस्पताल में पति को भर्ती कराया और दो आपरेशन कराए। आयुष्मान कार्ड था, लेकिन 27 हजार रुपये का ही लाभ मिल सका। परेशान अर्चना ने कर्ज लिया और इलाज के एक लाख रुपये चुकाए।

अब गुजारा मुश्किल : हजीरा क्षेत्र में इंद्रा नगर में करीब 20 दिन पहले ही अर्चना ने दोबारा चाट का ठेला लगाना शुरू किया है। वह खुद ठेले पर रहती हैं और दोपहर से लेकर रात तक काम करती हैं। उन्होंने बताया कि करीब तीन सौ रुपये प्रतिदिन ठेले से आते हैं, इसमें गुजारा मुश्किल है। अब रोटी खाएं या कर्जा चुकाएं। पति के इलाज के कारण कर्जदार हो गई हूं। प्रशासन से भी आर्थिक सहायता मांगी थी, लेकिन नहीं मिली।

पीएम ने कहा था-आयुष्मान में लाभ न मिले तो मुझे चिट्ठी लिखना : अर्चना ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब उनसे बात की थी तो पति की बीमारी की बात उन्होंने उन्हें बताई थी। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा था और कहा था कि कोई परेशानी आए तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना। अर्चना ने उन्हें चिट्ठी भी भेजी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

नए आइटी नियमों को लागू करने में ट्विटर विफल : केंद्र सरकार

जासं, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने फिर कहा है कि नए आइटी नियम देश का कानून हैं और अनिवार्य रूप से इनका पालन करना होगा। इंटरनेट मीडिया के महत्वपूर्ण प्लेटफार्म ट्विटर इन नियमों का पालन करने में नाकाम रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हलफनामे में केंद्र ने ये बातें कहीं। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साइबर ला ग्रुप में वैज्ञानिक-ई के रूप में काम करने वाले एन. समय बालन ने यह हलफनामा दायर किया है। इसमें केंद्र ने कहा कि ट्विटर इंक आइटी अधिनियम-2000 के प्रविधान के अर्थ में मध्यस्थ था और आइटी नियम 2021 के तहत महत्वपूर्ण इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी है। केंद्र ने कहा कि तीन माह का समय समाप्त होने के बावजूद ट्विटर इसका अनुपालन करने में विफल रहा है। बता दें कि अधिवक्ता अमित आचार्य ने याचिका में कहा था कि 25 मई से लागू हुए आइटी नियम के अनुसार ट्विटर को स्थानीय शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

पोलियो की तरह तैयार किया जाएगा कोरोना का भी टीका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान (आइसीएमआर-एनआइसीईडी) ने कोविड-19 के ओरल टीके पर अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग को एक प्रस्ताव सौंपा है। संस्थान की एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना पर एक जर्मन कंपनी के सहयोग से कार्य किया जाएगा। कोविड-19 का यह टीका विकसित होने पर पोलियो के टीके की तर्ज पर ड्रॉप के रूप में इसकी खुराक दी जा सकेगी। वर्तमान में कोविड का टीका इंजेक्शन के जरिये लगाया जाता है।

आइसीएमआर-एनआइसीईडी की निदेशक शांता दत्ता ने बताया कि हमने एक ओरल टीके के लिए प्रस्ताव सौंपा है।

वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

- कुरान से कुछ आयतें हटाने की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कुरान की 26 आयतें हटाने की मांग संबंधी उनकी याचिका खारिज करने और उन पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने वाले शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ उन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।

जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीआर गवई की पीठ को अधिवक्ता देब कुमार ने बताया कि रिजवी ने 12 अप्रैल के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और उनकी जुर्माना माफ करने संबंधी याचिका निष्फल हो गई है। उन्होंने इस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी जो अदालत ने प्रदान कर दी।

12 अप्रैल को अदालत ने रिजवी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कुरान की 26 आयतों को देश के कानून की विरोधी बताते हुए हटाने की मांग की थी। उनका कहना था कि ये आयतें कथित रूप से चरमपंथ व आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। इस तरह की अर्थहीन याचिका दाखिल करने और सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने के लिए जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। रिजवी ने याचिका में कहा था कि इस्लाम समानता, क्षमा व सहिष्णुता की अवधारणा पर आधारित है, लेकिन कुरान की उक्त आयतों की चरमपंथी व्याख्या की वजह से धर्म बुनियादी सिद्धांतों से दूर जा रहा है। इस याचिका का काफी विरोध हुआ था और कई मुस्लिम संगठनों व इस्लामी धर्मगुरुओं ने उनका विरोध किया था।

तीन संस्थाएं देश के आधा दर्जन प्रदेशों में लगाएंगी आक्सीजन प्लांट

प्रशांत यादव, मीरजापुर : कोरोना की तीसरी लहर के दौरान आक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए कुछ संस्थाएं आक्सीजन प्लांट लगाने को आगे आई हैं। ये संस्थाएं संयुक्त रूप से खुद के खर्च पर देश में प्लांट लगा रही हैं। देश के आधा दर्जन प्रदेशों के आठ स्थानों पर प्लांट लगाने की योजना है। इसमें उप्र के मीरजापुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद सहित कुछ अन्य प्रदेश शामिल हैं।

मुंबई, राजस्थान, दिल्ली आदि आइआइटी के छात्र-छात्राएं देश-विदेश में कार्यरत हैं, जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान आक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर चिंतित हैं। इसलिए देश में आक्सीजन प्लांट लगने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्लांट लगाने की स्वीकृति दे दी है। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के प्रबंधक चेतन कुमार ने कहा कि देश के आधा दर्जन प्रदशों में आक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे।

रामदेव व आइएमए के वकीलों में झड़प

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा– झगड़ो मत, मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई होगी

नई दिल्ली, आइएएनएस : कोरोना काल में एलोपैथी को लेकर योग गुरु रामदेव द्वारा की गई टिप्पणियों के मामले में कार्यवाही पर रोक की मांग लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान बाबा और डाक्टरों के निकाय (आइएमए व डीएमए) के वकीलों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस पर कोर्ट को हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों से झगड़ा न करने की हिदायत देनी पड़ी।

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस ए. एस बोपन्ना और ह्रषिकेश राय ने कहा कि कोर्ट को इस मामले से जुड़े बयानों व वीडियो की प्रतियों वाली भारी भरकम फाइलें रविवार की रात करीब 11 बजे मिली थीं। शीर्ष अदालत ने सोमवार को इन फाइलों का परीक्षण करना तय किया। रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने का अनुरोध किया। इस मामले में मुकदमा करने वाले दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल ने रामदेव द्वारा दिए गए सभी बयानों का हवाला देते हुए एक चार्ट बनाया है।

डीएमए ने रामदेव को योग गुरु के वेश में व्यापारी बताया और दावा किया है कि उनके पास आयुर्वेद का अभ्यास करने और दवाएं लिखने के लिए कोई डिग्री या लाइसेंस नहीं है। इस पीठ ने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर रहे हैं।

इस मामले में प्रतिवादियों में से एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि उनके मुवक्किल ने भी अपने आवेदन में रामदेव के बयानों के सभी अंश पेश किए हैं। इस पर रामदेव के वकील रोहतगी ने सुनवाई के इस मोड़ पर, आवेदन का विरोध किया और कहा कि यह सब दर्ज करने में आपकी कोई भूमिका नहीं। इस पर दत्ता ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह मत कहिए कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। आप जो कह रहे हैं (याचिका में) वह सब झूठ है।

इस पर पीठ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि 'झगड़ा मत करो'। पीठ ने कहा कि वह इस मामले को 12 जुलाई को उठा सकती है। उल्लेखनीय है रामदेव ने आरोप लगाया है कि आइएमए ने देश में अपने विभिन्न चैप्टर के माध्यम से उनके खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामलों की बाढ़ ला दी है। रोहतगी ने 30 जून को प्रस्तुत कर कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों एफआइआर दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने अदालत से इन एफआइआर को एक जगह संबद्ध कर दिल्ली में मामला चलाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने पिछले साल कोरोना के लिए कोरोनिल लांच की थी। तब सभी डाक्टर उनके खिलाफ हो गए थे। पीठ ने रोहतगी से पूछा आपने जो मूल बात कही थी वह क्या है।

दैनिक जागरण

जो विचार आकार न ले पाए वह व्यर्थ है

नेक विचार पर नाखुशी

अपने देश में किस तरह किसी सीधी-सच्ची बात पर भी सस्ती राजनीति की जा सकती है, इसका उदाहरण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस कथन पर आपत्ति और असहमति भरी प्रतिक्रिया कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। इस कथन पर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह ने जैसी प्रतिक्रिया दी, उससे विरोध के लिए विरोध वाली मानसिकता का ही परिचय मिला। इनमें से किसी ने भी यह समझने की कोशिश नहीं की कि मोहन भागवत अपने इस कथन के जरिये सभी देशवासियों में एकता की भावना का संचार करने के साथ यह रेखांकित करना चाह रहे थे कि भारत के लोगों में जाति, मजहब, पूजा-पद्धति की कितनी भी भिन्नता हो, उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि वे सब इस देश की संतान हैं और सबके पूर्वज एक हैं। इस विचार में ऐसा कुछ भी नहीं कि उस पर आपत्ति जताई जाए। बावजूद इसके किसी न किसी बहाने आपत्ति जताई गई और विमर्श को खास दिशा में मोड़ने की कोशिश की गई। इसका मकसद लोगों को गुमराह करना और अपने वोट बैंक को साधने के अलावा और कुछ नहीं नजर आता।

यह देखना दुखद है कि जब मोहन भागवत हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर दे रहे हैं, तब कुछ नेता इसके लिए अतिरिक्त कोशिश कर कर रहे हैं कि हमारा समाज एकजुटता-सद्भावना की ऐसी बातों पर ध्यान न दे। इस कोशिश से यही प्रकट हुआ कि कुछ लोगों की दिलचस्पी इसमें है हिंदू-मुस्लिम के बीच की दूरी खत्म न हो। इस संदर्भ में संघ प्रमुख ने यह सही कहा कि हिंदू-मुस्लिम एका की बातें इस अर्थ में भ्रामक हैं, क्योंकि वे तो पहले से ही एकजुट हैं और उन्हें अलग-अलग देखना सही नहीं। कायदे से इसका स्वागत करते हुए अपने-अपने स्तर पर ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि भारतीय समाज एकजुट हो और उसके बीच जो भी वैमनस्य है, वह खत्म हो। निःसंदेह कुछ लोग ऐसा नहीं होने देना चाहते और इसीलिए किसी ने संघ की कथनी-करनी में अंतर का उल्लेख किया तो किसी ने भीड़ की हिंसा का जिक्र। इतना ही नहीं, भीड़ की हिंसा के लिए संघ को कठघरे में खड़ा करने की भी कोशिश की गई। ऐसा तब किया गया, जब संघ प्रमुख गाय के नाम पर होने वाली भीड़ की हिंसा का विरोध करते रहे हैं। गत दिवस भी उन्होंने साफ-साफ कहा कि उन्मादी भीड़ की हिंसा में शामिल लोग हिंदुत्व के विरोधी एवं आततायी हैं और उन्हें किसी भी तरीके से राष्ट्रवादी नहीं कहा जा सकता। ऐसी दो टूक बात पर भी मीन-मेख निकालने वालों के बारे में यही कहा जा सकता है कि वे घोर नकारात्मकता में आकंठ डूबे हुए हैं।

जिंदगी चलती रहे

वैश्विक महामारी की दूसरी लहर के कारण हिमाचल प्रदेश में लगाई गई अधिकतर बंदिशें हट गई हैं। कार्यालयों में सौ फीसद उपस्थिति के साथ अन्य राज्यों के लिए बस सेवा भी शुरू हो गई है। धार्मिक स्थलों के साथ शिक्षण संस्थान भी खुल रहे हैं। तकनीकी शिक्षा से संबंधित संस्थानों में पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को ही बुलाया गया है जबकि अन्य कालेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा हो रही है। स्कूलों में शिक्षक आएंगे, लेकिन अभी बच्चों को नहीं बुलाया गया है। शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले शिक्षकों और संबंधित छात्रों का टीकाकरण जरूरी किया गया था। अधिकतर शिक्षकों और छात्रों ने टीकाकरण करवा लिया है, लेकिन कोविड नियमों का पालन अब भी किया जाना आवश्यक है। राज्य में डेल्टा प्लस वैरिएंट की भी पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह सैंपल मई में जांच के लिए भेजा गया था। अब प्रभावित स्वस्थ भी हो चुका है। बेशक सरकार ने बंदिशें हटा ली हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के कई स्थानों पर अब भीड़ उमड़ने लगी है। सार्वजनिक स्थलों पर लोग मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों को भूल रहे हैं। ऐसा कर वे खुद को ही नहीं दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। शिक्षण संस्थानों विद्यार्थियों और शिक्षकों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन संस्थानों में समय समय पर सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों को महामारी से बचाव से प्रेरित करना चाहिए। हाथ धोने के लिए साबुन, सैनिटाइजर इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था हो। पुलिस-प्रशासन को शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। यदि कहीं पर नियमों की अवहेलना हो रही है तो उन्हें सचेत किया जाना चाहिए। महामारी के कारण बहुत नुकसान हो चुका है। बच्चों की शिक्षा की भरपाई आनलाइन माध्यम से करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वैसी स्थितियां फिर से पैदा न हों इसके लिए हर तरह की हिदायतों का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर को तभी निष्प्रभावी बनाया जा सकता है जब लोग सजगता दिखाएं।

कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव कम होने से गतिविधियां सुचारू हुई हैं, लेकिन नियमों का पालन करना न छोड़ें

भारत विरोध पर आमादा पश्चिमी मीडिया



श्रीराम चौलिया

पत्रकारिता का पहला उसूल है निष्पक्षता, पर विचारधारा की पट्टी ने पश्चिमी मीडिया को एक तरह से अंधा बना दिया है



अवधेश राजपूत

बीते दिनों अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नौकरी का एक अनोखा विज्ञापन दिया। उसने भारत समेत दक्षिण एशिया क्षेत्र में बिजनेस संवाददाता की नियुक्ति के लिए उसके गुण और हुनर पर जोर नहीं दिया, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज पर एक लंबा भाषण देते हुए स्पष्ट किया कि वह ऐसे पत्रकार को ढूंढ रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए। विज्ञापन के विवादास्पद वाक्य ये हैं, 'मोदी का राष्ट्रवाद भारत के हिंदू बहुसंख्यकों पर केंद्रित है। यह देश के स्वाधीनता सेनानियों की सहिष्णुता और बहुसांस्कृतिक परंपरा के विपरीत है। मोदी सरकार मीडिया और ऑनलाइन टिप्पणियों पर पाबंदियां लगा रही है। इसके कारण भारत में वाक् स्वतंत्रता पर कठिन प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।' दरअसल इस विज्ञापन का मूल संदेश यह है कि पश्चिमी मीडिया में भारत के प्रति पूर्वनिर्धारित धारणाएं हैं और भिन्न विचार वाले आवेदन करने का कष्ट न करें।

न्यूयॉर्क टाइम्स की स्थापना 1851 में हुई थी। इसे कथित तौर पर 'स्वतंत्र' पत्रकारिता का स्तंभ माना जाता है, पर आज इसकी पहचान भारत को अत्यंत असहिष्णु और घृणा से पेश करने वाले मीडिया संस्थान की बन गई है। जबसे मोदी सरकार आई है, तबसे इसकी कलम भारत की बुराई के लिए ही चल रही है। भारत पर इसमें जितनी खबरें और संपादकीय लेख प्रकाशित होते हैं, उनमें यही धारणा रहती है कि मोदी एक कट्टरवादी और तानाशाह नेता हैं। वह देश की पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्षों से भारत की जनता के चहेते नेता हैं और आज भी जनमत सर्वेक्षण उन्हें विपक्षी नेताओं से काफी आगे बताते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को उनकी लोकप्रियता और कार्यकुशलता से कोई लेना-देना नहीं है। दरअसल अमेरिका के उदारवादी खेमे की जंग दक्षिणपंथी विचारधारा से है। यही वजह है कि वह भारत के मतदाताओं को ज्ञान बांटने से बाज नहीं आ रहा।

भारत से संबंधित किसी भी विषय पर न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखों को आप देख लीजिए। उनमें मोदी के निंदकों की राय प्रमुख रूप से रहती है। चाहे नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक मामले हों, पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक हो, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो, नागरिकता संशोधन कानून लाना हो, या कोरोना महामारी से निपटना और विश्व की सहायता करना हो-इन सबको न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके बंधुओं ने असफल, विनाशकारी और आत्मघाती ही घोषित किया।

कश्मीर हमारे देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर के बारे में जब भी खबरें छपती हैं तो उनमें मोदी और भारतीय सेना को खलनायक की तरह पेश किया जाता है और पाकिस्तान-प्रायोजित अलगाववादियों और आतंकियों के अभिप्राय ही उद्धृत होते हैं। भारत को कश्मीर में जुल्मी 'हिंदुत्ववादी' शक्ति और वादी के मुसलमानों को शोषित दिखाने का खेल कोई न्यूयॉर्क टाइम्स से बेहतर नहीं रच सकता। भले ही कश्मीर धीरे-धीरे भारत का अभिन्न अंग बन रहा हो, पर पश्चिमी मीडिया ने पहले से ही तय कर लिया है कि कश्मीर में 'आजादी' की पुकार को अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रोत्साहित करना उसका उदारवादी कर्तव्य है। तुलना के लिए स्पेन को ले लीजिए, जहां कातालोनिया प्रांत में दशकों से आजादी की मुहिम छिड़ी है। वहां न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों पक्षों-स्वाधीनता मांगने वालों और स्पेन की अखंडता एवं संप्रभुता चाहने वालों को बराबर प्रमुखता देता है और निष्पक्ष रवैया रखता है, लेकिन भारत के प्रति उसकी मानसिकता ठीक इसके उलट है। संभवतः वह मोदी विरोध की घृणा में ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि वह पहले ही मानकर चल रहा है कि उनकी हर नीति में धार्मिक बैर, बहुसंख्यकवादी षड्यंत्र और फासीवाद है।

पिछले आम चुनाव में लगभग 10 प्रतिशत मुसलमानों (दो करोड़ लोगों) ने भाजपा को मत दिए। आम अल्पसंख्यकों को विचारधारा की लड़ाई में कठपुतली बनना अस्वीकार है, पर न्यूयॉर्क टाइम्स को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह सत्य की अनदेखी करता है। अमेरिका के ही वाशिंगटन पोस्ट और सीएनएन एवं ब्रिटेन के गार्जियन और बीबीसी भी इसी प्रकार मोदी और भारत को नकारात्मक स्वरूप में दिखाते हैं। ये सभी राष्ट्रवाद और 'लोक लुभावनवाद' को पिछड़ी सोच बताकर उनसे इतर पश्चिमी मूल्यों से ओतप्रोत नई दुनिया बनाने का स्वप्न देखते हैं। बीते वर्षों में जब कई देशों में राष्ट्रवादी चुनावी लहर चल पड़ी, तब इन उदार मीडिया घरानों ने इससे मुकाबला करने का एक तरह से ठेका ले लिया। इस परिप्रेक्ष्य में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शेरी बेरमेन ने लिखा है कि 'अनियंत्रित उदारवाद आसानी से आभिजात्य कुलीनतंत्र में तब्दील हो सकता है।' यह बात न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे संस्थानों पर सटीक बैठ रही है। दुख की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया के इस कुलीनतंत्र में कुछ भारतीय और भारतीय मूल के टिप्पणीकार भी शामिल हैं। जिन भारतीयों को भारत के उत्थान से परेशानी है, वे पश्चिमी मीडिया में लिखते हैं, ताकि भारत की छवि पर लगातार आघात हो। पत्रकारिता का पहला उसूल है निष्पक्षता, पर विचारधारा की पट्टी ने पश्चिमी मीडिया को एक तरह से अंधा बना दिया है।

हालांकि बहुत कम भारतीय पाठक न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन जैसे विदेशी अखबार पढ़ते हैं। भारत इन पश्चिमी मीडिया घरानों के लिए महत्वपूर्ण बाजार नहीं है। लिहाजा मोदी और देश के भविष्य को बदलने में बाहरी मीडिया नाकाम रहेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि उनके पत्रकार भारत में रहकर हमारा अपमान और चरित्र हनन करते रहें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख को खराब करने के लिए इन्हें खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। 'फेक न्यूज' के दौर में पश्चिमी सूचना योद्धाओं की अनदेखी नामुमकिन है। भारत जैसे लोकतंत्र में इन्हें प्रतिबंधित तो नहीं किया जा सकता, पर उनकी निगरानी जरूरी है। हमारी कहानी विश्व को अपनी जुबानी भी सुनानी है। सरकार 'दूरदर्शन इंटरनेशनल' चैनल खोलने के प्रस्ताव पर अगर शीघ्रता और बुद्धिमानी से अमल करे तो भारत के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय लोकमत बनाना संभव है। विश्वगुरु को न्यूयॉर्क टाइम्स और उसकी बिरादरी को विश्वरूप दिखाने का समय आ गया है।

(लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)

response@jagran.com

मतांतरण का सुनियोजित धंधा



प्रणय कुमार

मतांतरण केवल आस्था, विश्वास, उपासना पद्धति का ही रूपांतरण नहीं, बल्कि राष्ट्रांतरण भी है



मतांतरण के खिलाफ विरोध करते प्रदर्शनकारी। फाइल

सर्वसाधारण ही नहीं, अपितु शिक्षित वर्ग भी बहुधा मत, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन आदि को धर्म का पर्याय मानने की भूल कर बैठता है। वस्तुतः धर्म और मजहब-रिलीजन में जमीन-आसमान का अंतर है। एक में विस्तार है तो दूसरे में सीमाबद्धता। मजहब या रिलीजन एक ग्रंथ, एक पंथ, एक प्रतीक, एक पैगंबर को मानने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा वह अन्य किसी मत या सत्य को स्वीकार नहीं करता। जो-जो उससे असहमत या भिन्न मत रखते हैं, उनके प्रति उसमें निषेध-अस्वीकार से आगे कई बार घृणा या वैमनस्यता भी पाई जाती है। भिन्न प्रतीकों-चिन्हों को ही वे अपनी अंतिम और एकमात्र पहचान बना लेते हैं। जबकि धर्म एकत्व तलाशने, चेतना-संवेदना को विस्तार देने तथा आंतरिक उन्नयन का लक्ष्य लेकर चलता है। वह समरूपता का पोषक नहीं, बल्कि विविधता, वैशिष्ट्य एवं चैतन्यता का संरक्षक है। वह किसी विशेष मत या सत्ता को येन-केन-प्रकारेण प्रतिस्थापित करने का बाह्य-आक्रामक अभियान नहीं, अपितु सत्य का अनुसंधान है। वह करणीय-अकरणीय, कर्तव्य-अकर्तव्य के सम्यक बोध या उत्तरदायित्व का दूसरा नाम है।

सनातन संस्कृति में धर्म एक व्यापक अवधारणा है, जो मानव मात्र के लिए है, किसी समूह या जाति विशेष के लिए नहीं। इसीलिए हर यज्ञ-अनुष्ठान के बाद सनातन संस्कृति में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो-जैसी मंगलकामनाएं की जाती हैं। यहां किसी विशेष मत, पंथ, संप्रदाय, समुदाय की जय-जयकार नहीं की जाती। गीता में भगवान श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं कि जब-जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, मैं अवतरित होता हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि जब-जब किसी मत या पंथ का नाश होता है। कुल मिलाकर धर्म धारण किया जाता है और मजहब एवं रिलीजन कुबूल या स्वीकार किया जाता है।

धर्म में समावेश, समन्वय, सह-अस्तित्ववाद पर जोर रहता है। वह सार्वजनिक समरसता के सिद्धांत पर अवलंबित होता है। धर्म व्यक्ति, समाज, प्रकृति, परमात्मा और अखिल ब्रह्मांड के मध्य सेतु-समन्वय स्थापित करता है। वह सबके कल्याण एवं सत्य के सभी रूपों-मतों को स्वीकारने की बात करता है। धर्म कहता है-एकं सत विप्राः बहुधा वदंति, सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुख भागभवेत। मनु ने धर्म की व्याख्या करते हुए जो दस लक्षण बताए उनमें किसी के प्रति अस्वीकार या असहिष्णुता तो दूर, कहीं रंच मात्र संकीर्णता और अनुदारता के संकेत तक नहीं हैं। जबकि सभी अब्राहमिक मतों में उनके पैगंबरों की वाणी को ही अंतिम, अलौकिक और एकमात्र सत्य माना गया है, शेष को लौकिक तथा मिथ्या। इस श्रेष्ठता ग्रंथि, भेद बुद्धि और आरोप-आक्रमण-विस्तार की नीति के कारण ही वह हरेक से संघर्षरत है। न केवल औरों के साथ, बल्कि उनके अपने मत के भीतर भी अधिक शुद्ध, अधिक सच्चा और अधिक धार्मिक होने को लेकर लगातार संघर्ष देखने को मिलता है। दुनिया के कल्याण की इस एकांगी-मनमानी मान्यताओं-व्याख्याओं ने स्थिति को और विकट, भयावह एवं संघर्षपूर्ण बना दिया है। ऐसी जिद-जुनून, सोच-सनक का ही परिणाम है मतांतरण।

मतांतरण का सुनियोजित धंधा वर्षों या दशकों से नहीं, अपितु सदियों से चलाया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में बीते दिनों उजागर हुआ मुफ्ती जहांगीर कासमी, मोहम्मद उमर गौतम और उसकी संस्था इस्लामिक दावा सेंटर द्वारा कराया जा रहा मतांतरण का खेल भी जुड़ गया है। सनातन धर्म और दर्शन अपने उदार, सहिष्णु, सर्वसमावेशी सोच के कारण उनके निशाने पर हमेशा से रहा है। आज भारत का कोई ऐसा प्रांत, कोई ऐसा जिला नहीं जहां ईसाई और इस्लामिक संस्थाएं मतांतरण के धंधे को संचालित नहीं कर रहीं। निर्धन-वंचित समाज एवं भोले-भाले आदिवासियों को वे अपना आसान शिकार बनाते हैं। उनकी कट्टर-मजहबी सोच का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मूक-बधिर, बीमार, बेसहारा, दिव्यांग जनों को भी वे नहीं छोड़ते। कोई सेवा-चिकित्सा के नाम पर यह धंधा चला रहा है तो कोई दीन-ईमान, जन्नत-दोजख और जन्नत के बाद नसीब होने वाले तमाम काल्पनिक ऐशो-आराम और सुखों के नाम पर। किसी इलाके की तेजी से बदलती हुई जनसांख्यिकीय स्थिति और घुसपैठ भी अब इसमें सहायक भूमिका निभाने लगी है।

सनद रहे कि मतांतरण केवल आस्था-विश्वास-उपासना पद्धति का ही रूपांतरण नहीं, वह राष्ट्रांतरण भी है। मतांतरित होते ही व्यक्ति की राष्ट्र, समाज और संस्कृति के प्रति धारणा और भावना बदल जाती है। वह अपने पुरखों, परंपरा और विरासत के प्रति हीनता की ग्रंथि पाल लेता है। इससे उसकी कल्पना का आदर्श समाज, आकांक्षाएं और भविष्य के सपने भी बदल जाते हैं। तीर्थ से लेकर प्रकृति-परिवेश के प्रति उसके सोच और श्रद्धा के केंद्र बदल जाते हैं। जीवन के आदर्श, मूल्य, गौरवबोध तथा अतीत और वर्तमान के जय-पराजय, मान-अपमान, शत्रु-मित्र के प्रति उसका संपूर्ण बोध और विचार बदल जाता है। देश पर आक्रमण करने वाले आक्रांता और देश को गुलाम बनाने वाली सत्ताएं उनके लिए पीड़ा-टीस-कलंक के नहीं, गौरव की विषयवस्तु बन जाते हैं। क्या यह सत्य नहीं कि अखंड भारत से विलग होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बनने तथा देश के भिन्न-भिन्न प्रांतो-हिस्सों में पलती-पनपती आतंकी-अलगाववादी गतिविधियों के मूल में यह मतांतरण ही है? यह अकारण नहीं कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जैसे महापुरुषों ने मतांतरण का पुरजोर विरोध किया था। सनातन घटा, देश बंटा-यह केवल धारणा या कल्पना नहीं, यथार्थ है।

(लेखक शिक्षा-प्रशासक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अनुशासन

किसी भी कार्य को सुचारु ढंग से गति देने के लिए जीवन में अनुशासन रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे जीवन में प्रगति का द्वार खुलता है और वह व्यक्ति उस कार्य में पारंगत हो जाता है। अनुशासन से हमारा तन-मन चुस्त-दुरुस्त और सकारात्मक बना रहता है। हालांकि जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, वे तय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। जहां यह कमजोरी है, वहां कोई भी बीमारी अपनी जगह जरूर बना लेती है। व्यक्ति तन-मन से अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थता जीवन के लिए मृत्यु है और स्वस्थता जीवन के लिए जीवंतता, चैतन्यता है। इसीलिए मन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले ध्यान और योग के पथ पर चलने की सलाह दी जाती है।

आत्मबल संपन्न व्यक्ति अनुशासनहीन नहीं हो सकता। वह किसी लोभ, मोह, वासना, कामना में न फंसकर लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। एक दिन उसे सफलता जरूर मिलती है। जो लोग वासना, कामना, लोभ और मोह वश अनुशासन को तोड़ देते हैं, उनका विवेक नष्ट हो जाता है। अनुशासन से ही पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर उस कार्य के लिए कितनी श्रद्धा एवं समर्पण की भावना है। पूर्ण समर्पण से ही भगवान की भक्ति संभव है। भगवान की भक्ति में भी अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। असली भक्त भगवान की भक्ति में जीवन को बलिदान कर देते हैं, पर भक्ति का नियम नहीं तोड़ते हैं। असली भक्त की यही मूल पहचान है।

अनुशासन से जीवन की गरिमा बढ़ती है। जो लोग स्वयं पर अनुशासन का बंधन नहीं रखते हैं, उनके जीवन में गतिरोध बना रहता है। याद रखें यह जीवन परमात्मा प्रदत्त उपहार है। यह नियम, अनुशासन में रहकर भगवद् भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। स्वयं के जीवन के साथ अगर कोई न्याय चाहता है तो उसे नियमपूर्वक समर्पित भाव से परमात्मा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है।

मुकेश ऋषि

सतत विकास लक्ष्य और भारत

सुधीर कुमार

सतत विकास संसाधनों के उपभोग का ऐसा मॉडल है, जो आवश्यकता के अनुसार संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपभोग पर बल देता है

हाल में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया है। इसके जरिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा लक्षित सतत विकास लक्ष्य-2030 को हासिल करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति की निगरानी की जाती है। सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष केरल शीर्ष, जबकि बिहार, झारखंड और असम निचले पायदान पर हैं।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अनुमोदित सतत विकास लक्ष्य एजेंडे के तहत 17 मुख्य तथा 169 सहायक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसका मकसद अधिक संपन्न, समतावादी तथा संरक्षित भविष्य की रचना करने के लिए 2030 तक भुखमरी, गरीबी तथा लैंगिक विषमता को शून्य स्तर तक लाना तथा बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी नागरिकों की समान पहुंच को सुनिश्चित करना है। भारत सहित दुनिया के 193 देशों द्वारा सतत विकास की अवधारणा को अपने देश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आज सततपोषणीय या धारणीय या टिकाऊ विकास पर इसलिए बल दिया जा रहा है, क्योंकि आर्थिक उन्नति की उत्तरोत्तर प्रक्रिया में सामाजिक हाशियाकरण और क्षीण होते पर्यावरण का मुद्दा पीछे छूटता चला गया है। संसाधनों के असमान बंटवारे ने गरीबी और अमीरी की खाई को और अधिक विस्तृत किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी उपलब्ध संसाधनों की मात्रा क्रमशः घटती जा रही है। इन समस्याओं का समाधान सतत विकास की अवधारणा में निहित है, जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है।

1987 की ब्रंटलैंड आयोग के अनुसार, 'विकास ऐसा होना चाहिए, जो वर्तमान की जरूरतों की पूर्ति इस प्रकार करे, जिससे भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता पर असर न हो।' दरअसल सतत विकास संसाधनों के उपभोग का ऐसा मॉडल है, जो आवश्यकता के अनुसार संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्ण उपभोग पर बल देता है। इस अवधारणा में सबको साथ लेकर चलने तथा पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का भाव समाहित है। सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में भारत विशिष्ट भूमिका निभा सकता है। भारत में प्राचीन काल से ही सतत विकास की अवधारणा किसी न किसी रूप में प्रचलित रही है। महावीर के पंच महाव्रत के अंतर्गत अपरिग्रह का सिद्धांत तथा महात्मा गांधी द्वारा दी गई मितव्ययिता की सीख में भी सतत विकास का आत्मा निहित रहा है। वहीं मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास के ध्येय ने सतत एवं समावेशी विकास को बल प्रदान किया है। प्रदूषण नियंत्रण, नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, भूमि क्षरण पर रोक, जलस्रोतों को गंदा होने से बचाकर तथा जागरूकता फैलाकर हम भी सतत विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

न्यायपालिका में सुधार का सवाल

'अपनी जवाबदेही तय करे न्यायपालिका' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में हृदयनारायण दीक्षित ने सही लिखा है कि कार्यपालिका और विधायिका की जवाबदेही तय है, लेकिन न्यायपालिका किसी निकाय या संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं है। हालांकि निचली अदालतों को संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट के प्रति जवाबदेह बनाया गया है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। निचली अदालतों से प्रतिवर्ष दो दर्जन से अधिक जज निर्णयों की समीक्षा के नाम पर हाई कोर्ट द्वारा घर बिठा दिए जाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह बेहतर अवसर है कि वह खुद को और हाई कोर्ट की कार्यविधि को संवैधानिक जवाबदेही की सीमा में बांध सकता है। अगर हाई कोर्ट के जज गलत या अनधिकृत निर्णयन के दोषी होते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट केवल चेतावनी देने या ट्रांसफर से आगे कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें हटाने के लिए केवल महाभियोग का प्रविधान है, जो आज तक किसी जज के विरुद्ध अमल में नहीं लाया जा सका। वहीं अदालतें सही और एक निश्चित समय सीमा में केसों का निपटारा करें इसके लिए भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर फैसले की गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की समस्या को छोड़ भी दें तो अभी विभिन्न अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। कई मामलों में अंतिम फैसला आने में 30 से 40 साल का समय लग रहा है। न्यायपालिका की यह एक ऐसी समस्या है, जिसका खामियाजा लोकतंत्र के दूसरे अंग भी भुगत रहे हैं। इसने हमारी प्रगति को एक तरह से जकड़ रखा है। चूंकि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः एक में खामी का असर दूसरे में भी नजर आने लगता है। विधायिका और कार्यपालिका में सुधार के निरंतर प्रयास होते रहे हैं। हालांकि ये अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं, पर न्यायपालिका में इसकी शुरुआत होना बाकी है। जाहिर है जब तक तीनों में एक-साथ बड़े पैमाने पर सुधार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक देश समस्याओं की जकड़न से नहीं निकल पाएगा।

विवेक श्रीवास्तव, पटना

मेलबाक्स

मानसून सत्र की तैयारी

लोकतंत्र का मंदिर संसद एक बार फिर अपने मानसून सत्र के लिए तैयार है। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनको हल करना अतिआवश्यक है। फिर चाहे वो देश की सुरक्षा को लेकर हों या फिर आम आदमी पर पड़ रहे महंगाई के बोझ को लेकर। बताया जा रहा है कि आगामी 19 जुलाई से, संसद का मानसून सत्र शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। यह सत्र कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि विपक्ष के पास सरकार को महंगाई के लिए कठघरे में खड़ा करने का मौका है। इसके साथ ही धरने पर बैठे किसान नेता व संगठनों ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को पत्र भेजकर सरकार का विरोध करने को कहा है। अब देखना होगा कि क्या मानसून सत्र सफलता पूर्वक पूर्ण होता है या फिर गतिरोध के कारण बीच में ही खत्म हो जाएगा।

अमन जायसवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

नेपाल में संकट से निदान की तलाश

चौतरफा गहरे संकट से घिरा नेपाल नामक संपादकीय आलेख मे केसी त्यागी द्वारा नेपाल के उठापटक भरे राजनीतिक माहौल के कारण वहां उपजे गंभीर हालात की वजह के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को केंद्र में रखते हुए अपना रुख प्रस्तुत किया है। देखा जाए तो नेपाल की जनता ने कई दशकों से जिस राणाशाही अथवा राजाशाही के तानाशाही अथवा मनमाने रवैये से परेशान होकर अपने यहां एक सफल, सुखद और प्रगतिशील लोकतांत्रिक अथवा जनतांत्रिक व्यवस्था का सपना देखा था वह भी वर्तमान राजनीतिक स्थिति और प्रधानमंत्री केपी ओली की मनमानियों के चलते चकनाचूर होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री जैसे एक मजबूत और जवाबदेह पद पर विराजमान केपी शर्मा अपने पद की गरिमा और नेपाल की जनता के दुख दर्द अथवा उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील होने के बजाय विवादित बयान देकर आए दिन अपने आप को सुर्खियों में रखने की चेष्टा करते हैं। यह ठीक नहीं है।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

2013 में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार और तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली वाले दिन 27 अक्टूबर को आतंकियों ने बम विस्फोट को अंजाम दिया था।


अवधेश कुमार

आजकल

आतंकवाद के व्यापक नेटवर्क का पर्दाफाश

बिहार में एक बड़ी आतंकी साजिश के पर्दाफाश होने की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। पिछले माह जब दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में विस्फोट हुआ था तो कम ही लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। किंतु बिहार पुलिस को इसमें आतंकवाद का पहलू दिखा। एनआइए द्वारा जांच के बाद जिस ढंग से बड़ी आतंकी साजिश की परतें खुल रही हैं और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तक इसके तार धीरे-धीरे पाकिस्तान से भी जुड़ने लगे हैं। ऐसे में उन्हें विस्मय की दृष्टि से देखा जाना स्वाभाविक है


दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों हुए विस्फोट की जांच करने पहुंचे सुरक्षा कर्मी। इंटरनेट मीडिया

पिछले माह बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए एक बम विस्फोट के मामले में एनआइए ने हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के शामली निवासी इमरान खान उर्फ इमरान मलिक और नासिर खान उर्फ नासिर मलिक को गिरफ्तार किया। इसके पहले उसने उत्तर प्रदेश के ही कैराना के दो अन्य संदिग्धों हाजी सलीम और कपिल को भी गिरफ्तार किया था। जिस पार्सल में दरभंगा स्टेशन पर विस्फोट हुआ वह सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से भेजा गया था। इसमें एक सेंसर भी लगाया गया था। वह केमिकल बम जितना शक्तिशाली हो सकता था, पर नहीं बन पाया। इस कारण पार्सल वैन में वह विस्फोट नहीं कर सका अन्यथा स्थिति भयावह हो सकती थी।

अब तक जितनी जानकारी सामने आई है उसके अनुसार नासिर वर्ष 2012 में पाकिस्तान गया था। वहां उसका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से हुआ। उसने लश्कर के निर्देश पर ट्रेनों में बड़े विस्फोट करने की योजना पर काम किया था। कैराना के गिरफ्तार दोनों संदिग्ध हाजी सलीम और कफील के बारे में जानकारी आई है कि कैराना का ही लश्कर आतंकी इकबाल काना पाकिस्तान में रह रहा है। वह भारत में आतंकियों की भर्ती करता है। काना ने ही केमिकल बम बनाने का फार्मूला सलीम के फोन पर भेजा था। इमरान और नासिर ने ही सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से पार्सल बुक किया था। संयोग कहिए कि सिकंदराबाद स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में ये चिन्हित हो गए। वहां से भेजे गए पार्सल में कपिल ने जो मोबाइल नंबर लिखाया वह शामली का ही था। पार्सल बम का फोटो पाकिस्तान के उसी नंबर पर भेजा जिससे वीडियो मिली थी और बताया कि काम हो गया। मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला है कि पुरानी दिल्ली के कुछ हवाला कारोबारियों के माध्यम से धन भेजे गए थे। पूरी जानकारी सामने आने में अभी समय लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि ये ट्रेन में बहुत बड़ा विस्फोट करना चाहते थे। फार्मूले को ठीक प्रकार से इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और केमिकल बम एक साधारण विस्फोटक बनकर रह गया। भयावह नुकसान से भले ही कम बच गए, लेकिन साफ हो गया कि भारत में जिहादी आतंकवाद का खतरा आज भी मौजूद है।

अब सवाल यह है कि दरभंगा ही बम पार्सल क्यों भेजा गया? जब भी दरभंगा मॉडल की चर्चा होती है तो अनेक लोग प्रश्न उठाते हैं कि इसमें दरभंगा नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से पूरा दरभंगा या कोई पूरा क्षेत्र आतंक की साजिश में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन वहां से अगर पिछले एक-डेढ़ दशक से संदिग्ध के साथ घोषित आतंकी पकड़े जा रहे हैं या उनके सूत्र मिल रहे हैं तो फिर चिंता का विषय यह होना चाहिए, न कि दरभंगा का नाम क्यों आ रहा है। आखिर भारत में अनेक विस्फोटों के अपराधी आतंकी भटकल बंधुओं का सूत्र दरभंगा से क्यों जुड़ा? यासीन भटकल जैसा आतंकी अगर दरभंगा में निकाह कर ले और नेपाल में रहने लगे तो यह गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। वर्ष 2014 से पहले हुए देश के कई विस्फोटों में जितने आतंकी पकड़े गए थे उनमें से एक दर्जन दरभंगा जिले के ही रहने वाले थे।

हालांकि आतंकवाद का तंत्र बिहार के अन्य जिलों तक विस्तारित है। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार का सीमांचल और मिथिलांचल इलाका आतंकियों के लिए सुरक्षित स्थान बन चुका है। नेपाल से सटे होने के कारण आतंकी इसे अपने लिए ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र मानते रहे हैं। वर्ष 2000 में ही सीतामढ़ी से हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकी मकबूल और जाहिर को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2006 मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोटों के बाद मधुबनी के मोहम्मद कमाल को गिरफ्तार किया गया था जो सिमी का सदस्य था। मोतिहारी से इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और अब्दुल असगर उर्फ हड्डी की गिरफ्तारी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि बिहार दुर्दांत आतंकियों का भी शरणस्थल बन चुका है। वर्ष 2008 दिल्ली विस्फोटों में मधुबनी के ही सलाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली विस्फोट मामले में 2009 में मधुबनी के आतंकी मदनी को भी दिल्ली में ही गिरफ्तार किया था। वर्ष 2011 में मधुबनी के अफजल और अहमद जमाली तथा दरभंगा के कतील सिद्दीकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2012 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट मामले में बिहार का मोहम्मद कफील अख्तर पकड़ा गया। वर्ष 2012 में ही दरभंगा के नदीम को दिल्ली विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया था।

27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार और तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना के गांधी मैदान में आयोजित रैली में सिलसिलेवार विस्फोट हुए। इसके बाद बोधगया में मंदिर परिसर में भी आतंकी हमला हुआ। यानी बिहार में आतंक का व्यापक तंत्र पहले से सामने है। दुर्भाग्य से जब-जब बिहार सरकार को आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए कहा गया तो प्रतिक्रिया नकारात्मक ही रही।

दरभंगा में हालिया विस्फोट की जांच में अभी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। संभव है पिछली आतंकी घटनाओं के भी कुछ नए तथ्य सामने आएं। निश्चित रूप से इनके आधार पर देश के स्तर पर कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि पिछली घटनाओं की छानबीन में जो प्रमाण सामने आए तथा पुख्ता संदेश चिन्हित हुए उन सबकी एक बार समीक्षा हो। प्रदेश सरकार को केंद्र से समन्वय बनाते हुए अधिकार संपन्न टीम से किसी शीर्ष अधिकारी या न्यायाधीश की निगरानी में समग्र जांच कराकर सफाई अभियान चलाने पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना प्रदेश की सुरक्षा के प्रति अपराध होगा और यह कभी भी हमारे लिए बड़े विध्वंस का कारण बन सकता है। इसके साथ इसमें समूचे देश के लिए तो ज्यादा सतर्क और चौकस रहने की चेतावनी है ही।

सीमा पर ड्रोन से जासूसी की साजिश


लोकमित्र
वरिष्ठ पत्रकार

जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट पिछले एक सप्ताह के दौरान पांच बार हवा में उड़ता ड्रोन दिखा। बीएसएफ की ओर से ड्रोन पर फायरिंग करने के बाद वह वापस चला गया। इससे यह पता चलता है कि 27 जून को जम्मू एयरबेस में जो दो ड्रोन के जरिये विस्फोट हुए थे, वे किसी गहरी साजिश का हिस्सा हैं। अगर यह शरारत स्थानीय कट्टरपंथियों की होती तो वह लगातार ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करते, जैसा देखने को मिला है। हालांकि इस ड्रोन हमले को समझने के लिए किसी बहुत जासूसी माइंड सेट की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आतंकी संगठन और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती राजनीतिक स्थिरता से बेचैन हैं, उससे सोचा जा सकता है कि वे इस बेचैनी को दोतरफा तनाव में बदलने के लिए क्या नहीं कर सकते?

हम सब जानते हैं कि आतंकवाद के मामले में हमारा देश मध्यपूर्व के देशों से कम पीड़ित नहीं है। सीरिया, इराक, लीबिया और लेबनान में हाल के वर्षों में ज्यादातर आतंकी घटनाएं ड्रोन के इस्तेमाल के जरिये ही अंजाम दी गई हैं। सवाल है कि हम कर क्या रहे हैं? पिछले लगभग एक सप्ताह से बार-बार ड्रोन आते हैं, कुछ नहीं तो अपनी मौजूदगी दिखाकर वहां के परिवेश में एक मनोवैज्ञानिक सनसनी पैदा करते हैं और भाग जाते हैं। भले ही ये कोई नुकसान न पहुंचा पाते हों, लेकिन बार बार अपनी मौजूदगी से जिस तरह आम जनता से लेकर सुरक्षाबलों तक में एक मनोवैज्ञानिक भय पैदा कर रहे हैं, ऐसा भय पैदा करना दुश्मन की कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। दुश्मन की चाहे जो भी मंशा हो, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सेना के बारे में कहा जाता है कि वह हर पल सीखती है तो क्या उसने इन ड्रोन से निपटने का कोई उपाय नहीं सीखा? निश्चित रूप से सेना के पास इसके उपाय होंगे। लेकिन तमाम सैन्य प्रतिक्रियाएं चूंकि राजनीतिक और नौकरशाही के माध्यम से नियंत्रित होती हैं, इसलिए सेना त्वरित जवाब शायद नहीं दे पा रही। वरना 30-35 किमी की रफ्तार से उड़ने वाले ऐसे ड्रोंस को मार गिराने में क्या मुश्किल है?

वर्ष 2016 के बाद से ही आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इसके जरिये हथियार और विस्फोटक की डिलीवरी भी करते रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना और पुलिस ने ऐसी घटनाओं से निपटने का अब तक शायद कोई मजबूत ब्लू प्रिंट नहीं बनाया है और अगर बनाया भी है तो उसे अमल में नहीं लाया गया है। ऐसे में समय आ गया है कि हम आंतकियों की ऐसी हरकतों का इतना करारा जवाब दें ताकि वे पलटकर वार करने का हौसला ही खो दें। लेकिन जिस तरह से हम ड्रोन हमले या ड्रोन साजिश को लेकर ढीला ढाला रवैया अपनाए हुए हैं, उससे तात्कालिक रूप से तो सेना और सुरक्षा एजेंसियों की किरकिरी हो ही रही है, स्थानीय लोगों में यह सोच भी मजबूत होती जा रही है कि चरमपंथी सेना और पुलिस से मुकाबला कर सकते हैं या कि सेना की इतनी विपुल मौजूदगी के बीच भी वे आतंकवादी जब चाहे आम लोगों को टारगेट बना सकते हैं। ये नैरेटिव हमारी वास्तविक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सुरक्षा एजेंसियों को ड्रोन जैसे हमलों से न सिर्फ कड़ाई से, बल्कि इन्हें नेस्तनाबूद करने के अंदाज में निपटना चाहिए। एक बार देश के दिलोदिमाग में यह बात बैठ गई कि सामने आए बिना भी रिमोट कंट्रोल के जरिये आतंकी सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे सकते हैं तो यह लड़ाई कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लब्बोलुआब यह कि सेना को आतंकवादियों को इतना मौका नहीं देना चाहिए कि वह मुकाबले का मुगालता पाल लें। इसलिए जितना जल्दी हो इस लुकाछिपी के खेल को खत्म किया जाना चाहिए। (ईआरसी)

खरी-खरी

अभिनय सीखने के लिए नेता को आवेदन

राजेंद्र देवधरे

परम आदरणीय गिरगिटानंद सर,
पूर्व अध्यक्ष समझौता पार्टी, उससे पूर्व अध्यक्ष जुगाड़ पार्टी, उससे भी पूर्व अध्यक्ष मतलबी पार्टी, वर्तमान अध्यक्ष दलदल पार्टी,

विषय- अभिनय सीखने हेतु।

निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक बालीवुड में किस्मत आजमाना चाहता हूं। मैं आपके उत्कृष्ट अभिनय का कायल हूं। आपकी अभिनय क्षमता से मैं इतना प्रभावित हूं कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज आपके सामने पानी भरते नजर आते हैं। आपकी अभिनय कला मौलिक है, जन्मजात है, ईश्वर प्रदत्त है। आप अपने अद्भुत कौशल से कठिन सीन को भी बिना रीटेक के ओके कर देते हैं। इसलिए मैं आप जैसे नेचुरल एक्टर से अभिनय सीखने का अभिलाषी हूं। मैं आपकी रंग बदलने की कला से बहुत प्रभावित हूं। रंगकर्म के प्रति आपके समर्पण भाव के कारण ही मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं।

आपकी नाट्य प्रतिभा ने मुझे बेहद प्रभावित किया है। आपकी संवाद अदायगी काबिले तारीफ है। जितनी तालियां किसी अभिनेता की डायलॉग डिलीवरी पर नहीं पिटती, उतने आपके बयान पर आपके विरोधी अपना सिर पीट लेते हैं। लंबे समय तक मीडिया में आपके संवादों पर चर्चा होती है। लंबी-लंबी बहस होती है, जिसमें पूरा देश डूब जाता है। ऐसे देश डुबाऊ डायलॉग आपकी जुबान से ही निकल सकते हैं। इसलिए मैं संवाद कला आपसे सीखने का अभिलाषी हूं।

एंग्री यंग मैन की भूमिका में आपका जवाब नहीं है। जब आप विधानसभा या संसद में विरोधियों को निपटाते हैं, किसी बिल के चिंदे-चिंदे कर देते हैं तो लगता है कि इस देश के असली हीरो आप ही हैं। इसलिए आपकी संगति में आकर मैं बालीवुड का हीरो बनना चाहता हूं।

चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह आप सुबह से शाम तक यहां से वहां निरंतर अथक डांस करते हैं, उससे प्रसन्न होकर लोग आपके पक्ष में वोट डालते हैं। किंतु चुनाव जीतते ही आप डांसर से डांस डायरेक्टर बन जाते हैं। और पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचाने लगते हैं। आपकी यह अद्भुत कला सीखकर मेरा मन मयूर नाचने को उतावला है।

ट्वीट-ट्वीट

भारत बहुत जादुई देश है। यहां सख्त लॉकडाउन के दौरान तो कोविड के मामलों में भारी बढ़ोतरी हो जाती है, वहीं बंदिशें हटाने के बाद मामले घट जाते हैं।
निमिष दुबे@nimishdubey

इसमें बात में कोई संदेह नहीं कि डेल्टा कोरोना वायरस का बेहद खतरनाक स्वरूप है, लेकिन हमारे पास उससे निपटने के उपाय मौजूद हैं। मास्क और शारीरिक दूरी के अलावा कम से कम पांच ऐसी वैक्सीन हैं, जो डेल्टा के खिलाफ प्रभावी हैं।
एरिक टोपोल@EricTopol

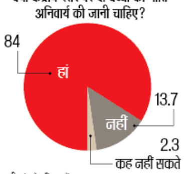

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार की अटकलों के बीच यही कहूंगा कि कोई भी नरेंद्र मोदी के मन की थाह नहीं ले सकता। फिर भी इस बड़े हलचल भरे दौर में उन्हें अपनी टीम को नए सिरे से संगठित कर उसमें नई प्रतिभाओं को मौका देना चाहिए। अगले आम चुनाव से पहले यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है।
संदीप घोष@SandipGhose

माता-पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हों, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है, वह दुनिया के किसी स्कूल में नहीं।
अरुण गोविल@arungovil12

कृपया उन लोगों के साथ किसी प्रकार की बहस में अपना समय व्यर्थ न करें, जो अपने झूठ में ही यकीन रखते हैं।
पाउलो कोएलो@paulocoelho

जागरण जनमत
कल का परिणाम

क्या केंद्रीय स्तर पर दो बच्चों की नीति अनिवार्य की जानी चाहिए?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या आप मोहन भागवत के इस बयान से सहमत हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पुन: भुनाने चल पड़े वह अपना राफेल,
जबकि पहले हो चुके हैं वह इसमें फेल।
हैं वह इसमें फेल खेल का नियम न जानें,
पिट कर भी हर बार चैंपियन खुद को मानें।
वह अपना नुकसान करें जाने-अनजाने,
बचा न दाना एक चले हैं पुन: भुनाने!
- ओमप्रकाश तिवारी


जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

'शून्य' सुना रहा अहंकार के हश्र की दास्तां


बंगाल विधानसभा के बाहर और भीतर का दृश्य। इंटरनेट मीडिया

समय बड़ा बलवान है। बंगाल में 17वीं विधानसभा का प्रथम सत्र गत शुक्रवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। भाजपा ने शोर-शराबा किया तो तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने नारे से जवाब दिया। परंतु इस हंगामे के बीच सदन में एक 'शून्य' भी था, जो अहंकार के हश्र की दास्तां सुना रहा था। 'हम 235 हैं, वे 30 हैं।' अहंकार भरी यह बात करीब 15 साल पहले बंगाल के तत्कालीन वामपंथी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कही थी। उनके मुंह से अनायास यह नहीं निकला था। उन्होंने वामपंथी सरकार के मुखिया के रूप में 2006 के विधानसभा चुनाव में 235 सीटों पर भारी जीत दर्ज करने और तृणमूल को महज 30 सीटें मिलने पर यह कहा था, जिसमें अहंकार साफ झलक रहा था। पर डेढ़ दशक में ही काल का चक्र ऐसे घूमेगा, इसका शायद ही किसी को भान होगा। बंगाल विधानसभा का यह प्रथम अधिवेशन है, जिसमें 'मैं हूं वामपंथी' और 'लाल सलाम' कहने वाला कोई नहीं है। साथ ही एक भी कांग्रेसी नहीं है। एक-दूसरे से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने के बावजूद वामपंथियों की झोली में एक ओर बड़ा शून्य आया तो दूसरी ओर चुनावी इतिहास में पहली बार कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला। इस विधानसभा ने बुद्धदेव से पहले दिग्गज ज्योति बसु का प्रभाव और सुभाष चक्रवर्ती व श्यामल चक्रवर्ती जैसे कामरेडों का जोर भी देखा है। कई कद्दावर वामपंथी नेताओं के राजनीतिक जीवन में उतार-चढ़ाव आया, लेकिन ऐसा शून्य कभी नहीं देखा था। यह शून्य डेढ़ दशक बाद बुद्धदेव की बातों को याद दिलाते हुए कह रहा है, अहंकारियों का अंत ऐसे ही होता है।

भारत को आजादी मिलने से कुछ माह पहले बंगाल विधानसभा के चुनाव में पहली बार वामपंथी नेताओं को जीत मिली थी। वर्ष 1946 के चुनाव में ज्योति बसु, रतनलाल ब्राह्मण और रूपनारायण रॉय जीते थे। स्वतंत्रता के बाद पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ तो उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) को 28 और फारवर्ड ब्लाक के दो समूहों को 13 सीटों पर जीत मिली। फिर वामदलों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बंगाल में धीरे-धीरे उनकी ताकत बढ़ती गई। वर्ष 1964 में भाकपा टूटकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) माकपा बनी। हालांकि, वामपंथी दलों की सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। इसमें 1972 का चुनाव अपवाद जरूर है, क्योंकि उस चुनाव में निष्पक्षता को लेकर कई सवाल उठे थे।

आजादी के बाद बंगाल में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। बीच में संयुक्त मोर्चा की दो सरकारों के संक्षिप्त कार्यकाल को छोड़ दें तो कांग्रेस यहां आजादी के बाद से 1977 तक सत्ता में रही। परंतु जैसे-जैसे वामपंथी दलों की ताकत बढ़ती गई, वैसे-वैसे कांग्रेस कमजोर होती गई और इस बार तो बिल्कुल खत्म हो गई। पर वामपंथी दलों का पतन अचानक ही माना जाएगा। वर्ष 1977 से लेकर अप्रैल, 2011 तक करीब 34 वर्षों तक एकछत्र राज करने वाले वामपंथी दलों का सत्ता से बाहर होने के महज एक दशक में ऐसा हश्र होगा, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। बंगाल विधानसभा की इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और 'लाल सलाम' के नारे 'भारत माता की जय', 'जय श्रीराम' और 'जय बांग्ला' में तब्दील हो चुके हैं।

वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में वाममोर्चा को 235 सीटों वाली बड़ी जीत मिली थी। उनमें से सिर्फ चार बड़े दलों माकपा, भाकपा, आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक को ही 227 सीटें मिली थीं। लेकिन इसके पांच साल बाद 2011 में वाममोर्चा 62 सीटों पर सिमट गया। चार बड़े सहयोगी दलों के खाते में महज 60 सीटें ही आईं। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल सिर्फ 32 सीटें ही जीत सके और डेढ़ दशक पहले तक 'लाल दुर्ग' कहे जाने वाले बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में वामपंथी दल शून्य पर आ गए। खुद को वाम विरोधी नेता के रूप में स्थापित करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा था, 'मैं नहीं चाहती कि कोई शून्य हो जाए। उन्होंने (वाम) खुद को भाजपा की ओर इतना धकेल दिया कि वे खुद एक साइनबोर्ड हो गए। भाजपा के बदले उन्हें (वाम) सीटें मिली होती तो कुछ बेहतर होता।' दूसरी तरफ पुरजोर कोशिश के बावजूद इस बार भाजपा सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन 34 वर्षों तक शासन करने वाले वामपंथी दलों का सत्ता से बाहर होने के महज 10 साल के भीतर यह हाल कल्पना से परे है। यह शून्य उन सभी दलों व नेताओं के लिए एक सबक है जो चुनाव जीतने के बाद खुद को भाग्य विधाता मानने लगते हैं। ऐसे अहंकारियों का अंत 'शून्य' ही होता है।

मंथन


मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

पॉडकास्ट की बढ़ती लोकप्रियता

इंटरनेट मीडिया पर अपनी बात रखने के लिए लिखने के साथ ही अब ध्वनियों का भी इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है, लेकिन इससे अनेक चुनौतियां भी जुड़ी हैं

इंटरनेट पर हमेशा वीडियो और चित्रों का राज रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले जहां ध्वनियां यानी पॉडकास्ट तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, भारत में वीडियो के प्रति दीवानगी बरकरार रही। कोरोना महामारी और वर्क फ्रॉम होम जैसी न्यू नार्मल चीजों ने काफी कुछ बदला है। इसी दौर में लोगों की इंटरनेट पर पसंद वीडियो के साथ साथ ध्वनियों ने भी जगह बनाई और पॉडकास्ट की लोकप्रियता बढ़ने लगी। ऑडियो ओटीटी रिपोर्ट कंटार और वीटीआइओएन के अनुसार संगीत और पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पोटीफाई, गाना जियो सावन में मार्च 2020 में समय बिताने की संख्या में 42 प्रतिशत का इजाफा हुआ। ग्लोबल इंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 के अंत में भारत में मासिक रूप से पॉडकास्ट सुनने वाले लोगों की संख्या चार करोड़ रही। यह संख्या साल 2017 के आंकड़ों से 57.6 प्रतिशत ज्यादा रही। मासिक श्रोताओं की संख्या से आशय ऐसे श्रोताओं से है जो महीने में कम से कम एक पॉडकास्ट जरूर सुनते हैं। रिपोर्ट के पूर्वानुमान के मुताबिक ये आंकड़े साल 2023 तक 34.5 प्रतिशत की दर के साथ बढ़कर 17.61 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। इन आंकड़ों के साथ भारत पॉडकास्ट की दुनिया का चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बाजार बन गया। इसी रिपोर्ट के अनुसार देश में संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट का बाजार साल 2014 में 3890 करोड़ रुपये का था जो साल 2018 में बढ़कर 5573 करोड़ रुपये का हो गया।

भारत के विविधता वाले बाजार में पॉडकास्ट एक शहरी प्रवृत्ति बन कर रह गया था और इसके बाजार में जितनी तेजी से वृद्धि होनी चाहिए उसका बड़ा कारण इन आडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्टिविटी का खासा अभाव था। इंटरनेट की तेज दुनिया में अब कोई इंतजार नहीं करना चाहता और इसीलिए पॉडकास्ट को वह लोकप्रियता नहीं मिल रही थी जितनी इंटरनेट मीडिया साइट्स को मिली। जबकि ध्वनियों का मामला इंटरनेट के एक आम उपभोक्ता के लिए वीडियो के मुकाबले ज्यादा सरल है और इसमें डाटा भी कम खर्च होता है। भारत जैसे देशों में, जहां इंटरनेट की स्पीड काफी कम होती है, वीडियो के मुकाबले पॉडकास्टिंग ज्यादा कामयाब हो सकती है। भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में जहां निरक्षरता अभी भी मौजूद है, पॉडकास्ट लोगों तक उनकी ही भाषा में संचार करने का एक सस्ता और आसान विकल्प हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' कार्यक्रम का पॉडकास्ट काफी लोकप्रिय है। पॉडकास्ट की सबसे बड़ी खूबी है इसकी वैश्विक पहुंच यानी अगर आप कुछ ऐसा सुना रहे हैं जिसे लोग सुनने चाहते हैं तो किसी चैनल के लोकप्रिय होते देर नहीं लगेगी। भारत श्रोत परंपरा वाला देश रहा है जहां हमारे सामाजिक जीवन में कहानियां बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कोरोना महामारी से उपजी पीड़ा और चिंताओं ने लोगों को कहानियां कहने और सुनने दोनों के लिए प्रेरित किया।

आजकल इंटरनेट मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए लोग लिखने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसका विकल्प ध्वनियां ही हो सकती हैं। फेसबुक (लाइव ऑडियो रूम) और ट्विटर (स्पेक्स) आवाज की दुनिया में पहले ही कदम रख चुके हैं। इसी कड़ी में मई में देश में लॉन्च होते ही 'क्लबहाउस' लोगों की चर्चा का केंद्र बन गया। क्लबहाउस ध्वनि आधारित एक इंटरनेट नेटवर्किंग साइट है, जो लोगों को 'किसी भी चीज' और 'हर चीज के बारे में' बात करने की सुविधा देता है। लांच होने के बाद ही ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वैसे भारत में इसके कितने उपभोक्ता हैं आधिकारिक तौर पर इसका आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।

इसकी लोकप्रियता से उत्साहित होकर आडियो स्ट्रीमिंग में उपभोक्ताओं की पहले ही पसंद बन चुकी कंपनी स्पोटीफाई ने क्लबहाउस को टक्कर देने के लिए इसी माह आवाज पर आधारित एक इंटरनेट नेटवर्किंग एप ग्रीन रूम लांच कर दिया है। माना जा रहा है कि लाइव आडियो मार्केट में एक कदम आगे निकलते हुए ग्रीन रूम कलाकारों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगा और इसके लिए कंपनी जल्द ही एक क्रिएटर फंड बनाने जा रही है जिससे ऑडियो क्रिएटर को यूट्यूब की तर्ज पर अपने लोकप्रिय काम के पैसे भी मिलेंगे।



बिना लिखे हुए अपनी बात संप्रेषित करने के लिए पॉडकास्ट का प्रचलन बढ़ रहा है। प्रतीकात्मक

रेडशीर कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में पांच प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप के कुल उपभोक्ता आधार का मात्र एक प्रतिशत ही सशुल्क उपभोक्ता हैं जो कुल राजस्व का करीब 40 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को अपने उपभोक्ता आधार में कम से कम छह प्रतिशत को सशुल्क उपभोक्ता बनाना पड़ेगा तभी ये मुनाफा कमा पाएंगी। पॉडकास्ट में विज्ञापनों से आय दूसरा साधन है। वर्ष 2014 में पॉडकास्ट विज्ञापनों से पांच लाख डॉलर का विज्ञापन राजस्व आया था जो साल 2018 में बढ़कर 72 लाख डॉलर हो गया। प्राइस वाटर कूपर्स के एक आकलन के अनुसार यह राजस्व साल 2023 में 58.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 73 लाख डॉलर हो जाएगा।

देश में ध्वनि आधारित इस तरह की सेवाओं की परंपरा नहीं है। ऐसे में इस तरह के एप पर क्या बोलें और क्या न बोलें जैसी समस्या से लोगों को दो-चार होना पड़ेगा। इंटरनेट पर हुई वीडियो क्रांति के अनुभव बताते हैं कि वीडियो कंटेंट में बहुत अश्लीलता, फूहड़ मजाक और फेक न्यूज की बाढ़ भी आ गई है।

चूंकि इंटरनेट पर किसी तरह का कोई सेंसर नहीं है, ऐसे में बच्चों को अवांछित ऑडियो कंटेंट से कैसे बचाया जाएगा? उपभोक्ताओं द्वारा बोले गए शब्द कंटेंट का क्या होगा? उसकी निजता की रक्षा कैसे की जाएगी? इसके अलावा, नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे दुरुपयोग की निगरानी के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमी के कारण इस तरह के एप कैसे अपने उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर ध्वनि की दुनिया में सुरक्षित अनुभव दे पाएंगे इसका फैसला होना अभी होना है।

155 करोड़ रुपये प्रचार पर खर्च किए हैं 16 महीनों में महाराष्ट्र सरकार ने। मुंबई के आरटीआइ कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय ने यह बताया।

उत्तराखंड

युवा नेतृत्व के हाथ में राज्य की कमान

उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नई सरकार वजूद में आ गई। भाजपा ने उत्तराखंड में चार महीने में दूसरी बार नेतृत्व परिवर्तन किया है। इससे पार्टी में अंदरखाने हलचल भी दिखी। इस बार विधायक दल की बैठक में युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी तो भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों में नाराजगी नजर आई। दरअसल धामी दूसरी बार के विधायक हैं और पिछली तीरथ सरकार में जितने मंत्री थे, उनमें से अधिकांश उनसे वरिष्ठ हैं। इनमें से पांच मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ये कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। इनमें से सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत काफी वरिष्ठ हैं। पिछली बार और अब भी ये दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल थे। संभवतया इसी वजह से इनमें निराशा और नाराजगी झलकती दिखी।

भाजपा नेतृत्व को शायद इस तरह का अंदेशा था, इसलिए नेता विधायक दल चुनने के लिए शनिवार को हुई बैठक से पहले ही इन्हें शीर्ष नेतृत्व के स्तर से फोन कर एकजुट रहने को कहा गया। रविवार शाम को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, लेकिन इससे पहले पूरा दिन मान मनुहार में गुजरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही सांसद अजय भट्ट ने इसकी कमान संभाली। महत्वपूर्ण यह रहा कि शपथ से पहले सबकुछ ठीकठाक कर लिया गया और मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों को भी शपथ दिला दी गई। यह इस छोटे से राज्य के भविष्य के लिहाज से भी जरूरी था, क्योंकि मनमुटाव कायम रहने से अस्थिरता को बढ़ावा मिलता। पिछली तीरथ सरकार का हिस्सा रहे सभी 11 मंत्रियों को धामी की टीम में भी जगह दी गई है।

> पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। अगले सात-आठ महीने में जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए उन्हें मेहनत भी अधिक करनी होगी

अगर भाजपा मंत्रियों के चेहरे में बदलाव से बची तो इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि अब इस विधानसभा का केवल साढ़े आठ महीने का ही कार्यकाल बाकी है। आखिरी दो महीने वैसे ही चुनाव में निकल जाएंगे। यानी काम करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास महज छह महीने का समय है। अगर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता तो उसके पास स्वयं को साबित करने के लिए बहुत कम समय रहता। इसमें से काफी वक्त तो नए मंत्री को विभागों को समझने में ही लग जाता।

इतना ही नहीं, पिछली तीरथ सरकार में शामिल तीनों राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को धामी की टीम में पदोन्नति मिली है और अब ये भी कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए और युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जनता की कसौटी पर कितना खरा उतरती है।

पंजाब

कायम रहे यह उत्साह

प्रदेश में शनिवार को वैक्सीनेशन के प्रति जिस तरह का उत्साह लोगों में देखा गया, भविष्य में भी वैसे ही उत्साह की जरूरत है। एक ही दिन में 5.14 लाख लोगों को टीका लगाया गया। इससे पहले 26 जून को एक दिन में सबसे ज्यादा 1.38 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। जाहिर सी बात है कि प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों और सामाजिक संगठनों की मदद से ही यह संभव हो सका है। चूंकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि यथाशीघ्र ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। पिछले चार दिनों से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में वैक्सीनेशन का काम ठप था।

प्रदेश सरकार इसके पीछे यही वजह बता रही थी कि केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की सप्लाई नहीं भेजी जा रही है। केंद्र द्वारा वैक्सीन उपलब्ध करवाने के बाद जिस तरह लंबी-लंबी कतारें टीकाकरण केंद्रों पर देखी गईं उससे लोगों की जागरूकता का भी पता चलता है। चूंकि प्रदेश में अब तक 78 लाख डोज ही लगी है, इसलिए किसी भी तरह की उदासीनता ठीक नहीं होगी। प्रदेश की आबादी करीब पौने तीन करोड़ है। आधी आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य भी अभी बहुत दूर है। प्रदेश सरकार को यह देखना होगा कि टीकाकरण की गति को कैसे बढ़ाया जाए।

> टीकाकरण का लक्ष्य जितना शीघ्र हासिल कर लिया जाएगा उतनी ही राहत की बात होगी। वैक्सीन ही कोरोना के खतरे को टाल सकती है या कम कर सकती है



टीकाकरण पर समग्र फोकस से ही बनेगी बात। फाइल

यह अच्छी बात है कि शनिवार को टीकाकरण केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई। सबसे ज्यादा 308 केंद्र लुधियाना में बनाए गए जिसका नतीजा भी बेहतर रहा। लुधियाना में सबसे ज्यादा 82,677 लोगों को टीका लगा। होशियारपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बधाई की पात्र है जहां एक ही दिन में 77,970 लोगों को टीका लगाया गया। टीकाकरण का कार्य जितना शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा उतनी ही राहत की बात होगी।

राज्य में इस समय सियासी पार्टियों और विभिन्न विभागों के मुलाजिमों की ओर से आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चिंताजनक यह कि इन पदर्शनों के दौरान कोरोना प्रोटोकाल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यदि इस तरह की लापरवाही जारी रहती है तो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का जोखिम पैदा होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। वैक्सीन ही कोरोना के खतरे को टाल सकती है या कम कर सकती है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को ऐसे प्रदर्शनों को लेकर गंभीरता से सोचना होगा। यदि हालात फिर से बिगड़ते हैं तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा।

हरियाणा

असली दोषी कौन

फरीदाबाद के एनआइटी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा के आवास के कुछ हिस्से में तोड़फोड़ की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला द्वारा की गई आलोचना स्वाभाविक है। यह तोड़फोड़ फरीदाबाद नगर निगम ने की है। निगम का कहना है कि विधायक ने अपने आवास का कुछ हिस्सा नियमों के विपरीत बनवाया था। इस हिस्से पर जो निर्माण हुआ, वह अनधिकृत था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तोड़फोड़ के पहले विधायक को नोटिस देना चाहिए था। उनका तर्क उचित है।

यह प्रश्न भी उठता है कि जब विधायक ने निर्माण कराया तब अधिकारी क्या कर रहे थे? संभव है कि निर्माण उस समय हुआ हो, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अधिकारियों ने यह जानते हुए भी कि अवैध निर्माण हो रहा है, कार्रवाई से मुंह मोड़ लिया हो। यह कोई नई बात नहीं है। केवल हरियाणा में ही नहीं सारे देश में ऐसा होता है। सत्तापक्ष के लोग ही नहीं अन्य प्रभावशाली लोग भी, जिनके पास बाहुबल-धनबल होता है, अवैध निर्माण करा लेते हैं और अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। जब शासन की भृकुटि तनती है अथवा संबंधित व्यक्ति का किसी अधिकारी से विवाद हो जाता है तो नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई कर दी जाती है। इस प्रकरण में भी विधायक आरोप लगा रहे हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने नगर निगम कार्यालय में कुछ अधिकारियों द्वारा की जा रही अवांछनीय गतिविधियों के विरोध में आवाज उठाई थी, निगम के अधिकारियों ने उसी से क्षुब्ध होकर प्रतिक्रिया में ऐसा किया है। इससे यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि जब तक विधायक ने निगम के अधिकारियों की पोल नहीं खोली, वे मौन रहे।

> जब प्रभावशाली लोग अवैध निर्माण करा रहे होते हैं तो अधिकारी क्यों मौन रहते हैं? उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए



प्रभावशाली लोगों के अपकृत्यों पर मौन अधिकारी। फाइल

जब विधायक ने उनकी पोल खोल दी तो उन्हें विधायक का अपकृत्य याद आ गया। तात्पर्य यह कि इस मामले में दोनों ही दोषी हैं। दोनों को दंडित किया जाना चाहिए। विधायक का निर्माण तो ढहा दिया गया है। उन्हें दंड मिल गया। लेकिन अधिकारियों ने निर्माण ढहाने के पहले नोटिस क्यों नहीं दिया, उनसे यह अवश्य पूछा जाना चाहिए और जब निर्माण हो रहा था तो वे क्यों मौन रहे, इसका भी जवाब उनसे मांगा जाना चाहिए।

बंगाल

राज्य में बदहाली की ओर कांग्रेस

दो दशक से अधिक समय तक बंगाल में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज बदहाल स्थिति में है। वैसे तो देखा जाए तो कुछ राज्यों को छोड़ दें तो पूरे देश में कांग्रेस बैसाखी के सहारे ही चुनावी नैया पार करने की कोशिश करती आ रही है। अपने संगठन और नेताओं को मजबूत नहीं कर भाजपा विरोधी दलों के साथ जैसे भी हो हाथ मिलाया जाए, इसी फार्मूले पर काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि भाजपा विरोधी दलों से हाथ मिलाने के लिए अपने ही नेताओं के पर कतरने को भी पार्टी तैयार हो जा रही है। ऐसी ही एक खबर रविवार को बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं लोकसभा में संसदीय दल के नेता अधीर चौधरी को लेकर सामने आई। कहा गया कि मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी में बड़े बदलाव कर सकती हैं। इसे कांग्रेस की ओर से तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिशों को मजबूती देने के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि यह खबर आने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ऐसे किसी बदलाव से साफ इन्कार कर दिया है। परंतु यहां सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी कोई बात ही नहीं थी तो बदलाव एवं तृणमूल से हाथ मिलने की खबर कहां से आई? वैसे भी बंगाल में कांग्रेस का वाममोर्चा और मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था। साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे। बावजूद इसके कांग्रेस ही नहीं वामपंथी दलों का भी खाता नहीं खुला, यहां तक कि एक-दो प्रत्याशियों की छोड़कर सबकी जमानत तक जब्त हो गई। इसके बाद वाममोर्चा व आइएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे।

> बंगाल को लेकर कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व लंबे समय से भ्रम की स्थिति में है। इसका उदाहरण विधानसभा चुनाव के दौरान स्पष्ट दिखा जब राहुल गांधी नाम के लिए यहां आए

इस बीच अधीर चौधरी ने आइएसएफ से गठबंधन तोड़ने की बात कह दी तो वामपंथियों के साथ भी गठबंधन नहीं रखने की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि कांग्रेस के ही कद्दावर नेता अब्दुल मन्नान ने पार्टी हाई कमान में वामपंथियों के साथ गठबंधन रखने के पक्ष में पत्र लिख दिया। परंतु बंगाल को लेकर कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज है। इसका उदाहरण विधानसभा चुनाव के दौरान स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। पूरे चुनाव में कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की चुनावी रैली बंगाल में नहीं हुई। राहुल गांधी नाममात्र के लिए बंगाल में चुनाव प्रचार करने आए। लगता है कांग्रेस एक और बैसाखी तलाश रही है। लेकिन वह अपने ही नेताओं को पार्टी में बनाए रखने में नाकाम होती भी दिख रही है।

बनारस के गंगाजल की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव

हिमांशु अस्थाना, वाराणसी

- बीएचयू के डाक्टरों व विज्ञानियों की टीम ने लखनऊ भेजे थे गंगाजल के 16 सैंपल

बनारस में गंगा में कोविड-19 वायरस नहीं पाया गया है। यह पहले भी सत्यापित हो चुका है कि बहाव वाले जल में कोरोना वायरस नहीं पाया जाता, लेकिन बीएचयू और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के विज्ञानियों द्वारा दो माह तक किए गए संयुक्त परीक्षण में गंगाजल की जो कोरोना रिपोर्ट अभी निगेटिव आई है, उसकी विशेष बात यह है कि सैंपल उन जगहों से भी इकट्ठा किए गए थे, जहां गंगाजल का ठहराव था। वहीं, वाटर ट्रीटमेंट (उपचार) के बाद भी लखनऊ में गोमती में गिरने वाले 80 फीसद नालों की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई है।

बनारस में गंगाजल की सैंपलिंग मई में की गई थी, जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी। इसमें 16 जगहों से 16 सैंपल इकट्ठा किए गए थे। उस समय भी जल लिया गया था, जब गंगा में लाशें प्रवाहित हो रही थीं। बीएचयू के विज्ञानियों व डाक्टरों की टीम ने एक के बाद एक क्रमवार सैंपल लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में जांच के लिए भेजा। करीब एक माह तक चले परीक्षण में सभी 16 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस सफलता से उत्साहित वैज्ञानिकों की टीम अब देशभर की अलग-अलग नदियों के जल का परीक्षण कर पता लगाएगी कि क्या वायरस को नष्ट करने की क्षमता एकमात्र गंगा में है या फिर कोई अन्य नदी इसमें सक्षम है।

शोध टीम में शामिल बीएचयू के जीन विज्ञानी प्रो.ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि गंगा के जल की आरटीपीसीआर जांच की गई। किसी भी सैंपल में आरएनए वायरस (कोविड-19 आरएनए वायरस है) का अस्तित्व नहीं मिला। हालांकि अन्य कई नदियों और सीवेज के जल परीक्षण में आरएनए वायरस होने के प्रमाण मिल चुके हैं। परिणाम में कोई त्रुटि न हो, इसके लिए न्यूरोलाजिस्ट प्रो.विजयनाथ मिश्रा के साथ सैंपलिंग लेते समय काफी सावधानी बरती गई। हर सप्ताह दो-दो सैंपल अलग-अलग जगहों से लिए गए। गंगा के मध्य, किनारे और सीवेज से 10 मीटर की दूरी से सैंपल लिए गए थे। अध्ययन के अगले चरण में गंगा में मिलने से पहले और गिरने के तत्काल बाद सीवेज के पानी में कोरोना की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। इसके लिए सैंपल लिया जा चुका है।

> गंगाजल में पाए जाने वाले फेज वायरस (जीवाणु भोजी) किसी अन्य वायरस के संपर्क में आते ही सक्रिय हो जाते हैं। कोविड वायरस के साथ भी यही हुआ है। गंगा के पानी में कोरोना का अस्तित्व क्यों नहीं है, इस पर शोध कर सबसे सस्ती औषधि बनाई जा सकती है।
> -प्रो.विजयनाथ मिश्रा, न्यूरोलाजिस्ट, बीएचयू

गोमती में कोरोना वायरस मिलने की पूरी आशंका : बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के एंशिएंट डीएनए लैब और कोविड लैब के प्रमुख डा.नीरज राय के अनुसार गोमती के जिस बिंदु पर नाले मिलते हैं, वहां कोरोना वायरस पाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। गंगा में आरएनए वायरस का न मिलना सुखद आश्चर्य है।

संगमनगरी में बोले थे डा. मुखर्जी, हम बनाएंगे सशक्त राष्ट्र

अमलेंदु त्रिपाठी, प्रयागराज

राष्ट्रवादी विचारधारा के सशक्त हस्ताक्षर डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद) से आत्मीय नाता रहा था। उनके अध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रणवानंद के चार प्रमुख आश्रमों में एक यहीं पर है, साथ ही यह जमीन वैचारिक दृष्टिकोण से उर्वरा थी। संगमनगरी में ही उन्होंने मिलने आए लोगों से कहा था-'हम बनाएंगे सशक्त राष्ट्र'।

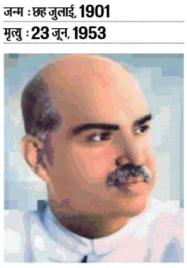
जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर, 1951 को जनसंघ की स्थापना की। पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 29 से 31 दिसंबर, 1952 में कानपुर के फूलबाग में हुआ। यहीं डा. मुखर्जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और पं. दीनदयाल उपाध्याय को महासचिव बनाया गया। अधिवेशन के तुरंत बाद उन्हें कलकत्ता (मौजूदा कोलकाता) जाना था, लेकिन वह पं. दीनदयाल उपाध्याय को लेकर प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद) आ गए। यहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसी बनर्जी के निवास पर ठहरे और समान विचारधारा के लोगों से मिले। संगठन तथा कार्यकर्ताओं के लिए संसाधन जुटाने की कार्ययोजना बनाई। सभी से आग्रह किया कि 'एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र' के लिए जो बन पड़े, जरूर करें। कुछ नहीं तो संगठन के लिए कार्य करने वालों के ठहरने और भोजन की ही व्यवस्था करें। जनसंघ नेता स्व. पंडित हरिनाथ पांडेय से सुने गए वृत्तांत के आधार पर पं. देवीदत्त शुक्ल-पं.रामदत्त शुक्ल शोध संस्थान के सचिव व्रतशील शर्मा बताते हैं कि डा. मुखर्जी ने सभी को पं. दीनदयाल उपाध्याय से परिचित कराया और उनसे मुखातिब होते हुए कहा- 'अब तुम्हें ही सब देखना है, तुम जनरल सेक्रेट्री हो, आगे बढ़ो।'

काशी में हिंदुत्व के प्रचार प्रसार की दीक्षा : प्रो. शिवाधार पांडेय ने अपने संस्मरण में उल्लेखित किया है कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद बहुत प्रभावित थे। अकाल के दौरान कोलकाता में डा. मुखर्जी के सेवा कार्य को उन्होंने देखा और सराहा था। काशी स्थित आश्रम में 1937 में स्वामी प्रणवानंद ने उन्हें राष्ट्र सेवा और हिंदुत्व के प्रचार-प्रसार की दीक्षा दी। प्रयागराज में भी भारत सेवाश्रम संघ का कार्यालय था। उसे स्वामी प्रणवानंद ने ही स्थापित किया था, इसलिए भी डा. मुखर्जी का इस धरती से अगाध प्रेम था।

जन्मतिथि पर विशेष

जन्म : छह जुलाई, 1901

मृत्यु : 23 जून, 1953



डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर, 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी। फाइल फोटो

स्मृतियां

- प्रो. एसी बनर्जी के निवास पर मिले थे शहर के लोगों से
- पार्टी बनाने के बाद पं. दीनदयाल उपाध्याय के साथ आए थे

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के प्रचार में आए

1952 में हुए लोस चुनाव में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र (तब फूलपुर संसदीय सीट नहीं थी। एक ही क्षेत्र से दो प्रतिनिधि चुने जाने थे) से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी चुनाव मैदान में थे। उनका मुकाबला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से था। ब्रह्मचारी को कई हिंदू संगठनों ने समर्थन दिया था। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी समर्थन देने पहुंचे और समान विचारधारा के लोगों से मिलकर यहीं से चुनाव अभियान की शुरुआत की। हालांकि ब्रह्मचारी को इसमें पराजय मिली।

चित्रकूट के पहाड़ों पर धमाके, पाताल में पहुंचा जलस्तर

हेमराज कश्यप, चित्रकूट

चित्रकूट के भरतकूप के पहाड़ों में हो रही हैवी ब्लास्टिंग का दुष्प्रभाव भूगर्भ जलस्तर पर पड़ा है। जिस पौराणिक भरतकूप का पानी भीषण सूखे में भी कम नहीं होता था, अब साल दर साल उसका जलस्तर पांच से छह फीट पाताल में जा रहा है। तमाम कुएं व हैंडपंप सूख चुके है। भयावह होते हालात से वाकिफ होने के बाद भी प्रशासन ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड की 10 साल की रिपोर्ट (2009 से 2019) के अनुसार चित्रकूट में मई माह में चार मीटर से ज्यादा जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। 70 फीसद कुंओं में चार मीटर से ज्यादा जलस्तर में गिरावट पाई गई है। यह स्थिति आने वाले समय में और भयावह हो सकती है। पर्यावरणविद गुंजन मिश्र कहते हैं कि पहाड़ों में ऐसी एक्टूफर (पानी रोकने वाली चट्टानें) होती है जो वर्षा जल को अपनी परतों को बीच में रोककर रखती है। वही पानी धीरे-धीरे जमीन में जाकर जलस्तर को बढ़ाता है जहां पहाड़ों में खनन अधिक होता है वहां जलस्तर प्रभावित होता है। खास कर बड़ी मशीनों और हैवी ब्लास्टिंग से एक्टूफर टूट जाती है। उससे जलस्तर गिरता जाता है। यही स्थिति राजस्थान की है वहां पर भी ग्रेनाइट के पहाड़ों में हैवी ब्लास्टिंग होती है।

चिंताजनक

- पौराणिक भरतकूप का जलस्तर भी तेजी से गिर रहा
- केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड के मुताबिक 10 साल में चार मीटर गिरा जलस्तर
- हैवी ब्लास्टिंग में ध्वस्त हो रही है एक्टूफर (पानी रोकने वाली चट्टानें)

पांच साल से गिर रहा जलस्तर

भरतकूप मंदिर के महंत लवकुश महराज कहते हैं कि भरतकूप वह पौराणिक कूप है जिसमें सभी तीर्थों का जल लाकर भरत जी ने डाला था। अनादिकाल से भरतकूप के पानी को लोग पीने और अन्य प्रयोग में इस्तेमाल करते थे लेकिन बीते पांच साल से जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। गर्मी में तो पांच से 10 फीट पानी कम हो जाता है।

> बुंदेलखंड में वैसे भी भूगर्भ जलस्तर तेजी से गिरता है। पहाड़ की चट्टानें पानी रोकती हैं, लेकिन इधर देखने में आ रहा है कि पानी काफी तेजी से खिसक रहा है। इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) को भेजेंगे।
> – जगदंबिका प्रसाद, अभियंता, केंद्रीय भूजल बोर्ड

जागरण विशेष

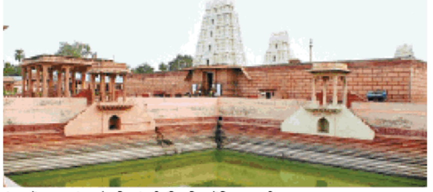
रंग जी मंदिर में 183 साल से सहेजा जा रहा बारिश का पानी

इसके लिए यहां बनाया गया है 100 मीटर लंबा और इतना ही चौड़ा पुष्करणी सरोवर, तीन कुओं के जरिये होता है पानी का संरक्षण

विपिन पाराशर • वृंदावन (मथुरा)

भूजल के बेहिसाब दोहन से हालात बिगड़े हैं। भविष्य की चिंता में वर्तमान समय में बारिश की बूंदों का संचयन करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वृंदावन का रंग जी मंदिर प्रबंधन काफी पहले ही जल संकट को लेकर सचेत हो गया था। यहां 183 साल पहले ही बारिश के पानी को सहेजने का काम शुरू हो गया था। मंदिर के विशाल पुष्करणी सरोवर (तालाब) में बारिश का पानी एकत्र किया जाता है।

दक्षिण भारतीय संस्कृति के रंग जी मंदिर का यहां 1833 में निर्माण शुरू हुआ था। करीब पांच साल में विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ। खास बात यह है कि मंदिर निर्माण के साथ यहां बारिश के पानी को सहेजने के लिए ही 100 मीटर लंबे और इतने ही चौड़े पुष्करणी सरोवर का निर्माण भी हुआ था। बारिश के दिनों में पूरे मंदिर परिसर का पानी पुष्करणी में ही जमा हो जाता है।



वृंदावन में रामानुज संप्रदाय के प्रसिद्ध रंग जी मंदिर परिसर में स्थित पुष्करणी • जागरण

25 बीघा में छोटे-बड़े 13 मंदिर : 25 बीघा क्षेत्रफल में बने रंग जी मंदिर परिसर में छोटे-बड़े 13 मंदिर हैं। पूजन के दौरान मंदिर में इस्तेमाल होने वाला पानी भी पुष्करणी में ही जाता है। पुष्करणी में तीन कुएं हैं, प्रत्येक की गहराई सौ मीटर बताई जाती है। बारिश का पानी पुष्करणी से इन कुंओं के जरिये भूगर्भ में जाता है। समय-समय पर पुष्करणी की सफाई भी कराई जाती है, ताकि गंदा पानी भूगर्भ में न जाए।

इसलिए कहा जाता है दिव्यदेश: पुराणों में भगवान नारायण के लोक को दिव्यदेश की संज्ञा दी गई है। इसके लिए परिसर में गरुड़ स्तंभ, गोपुरम, पुष्करणी, पुष्प उद्यान व गोशाला होना अनिवार्य है। रंग जी मंदिर में ये पांचों हैं। उत्तर भारत का यह पहला दिव्यदेश मंदिर है। दूर-दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं।

25 तिरुमाली, हर मकान में कुआं: मंदिर परिसर में 25 तिरुमाली (मकान) बने हैं। एक मकान में मंदिर प्रबंधन से जुड़े चार परिवार रहते हैं। प्रत्येक मकान में एक कुआं भी है, जिसके पानी का इस्तेमाल परिवार करता है।

> 183 साल पहले ही रंग जी मंदिर में बारिश के पानी को सहेजने का काम शुरू हुआ था। नियमित देखरेख के चलते पुष्करणी का जल इतना साफ है कि उसे दैनिक उपयोग में भी ला सकते हैं। बारिश का पानी पुष्करणी के जरिये कुंओं में जाता है।
> **अनघा श्रीनिवास**, सीईओ, रंग जी मंदिर प्रबंधन



जल है तो कल है

जल संरक्षण दैनिक जागरण के सात सरोकारों में शुमार है। इसी क्रम में हम जल प्रहरियों के प्रेरक कार्यों को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन प्रहरियों से प्रेरणा ले ज्यादा से ज्यादा लोग जल संरक्षण के काम में सहभागी बनें।

स्कैन करें और पढ़ें 'सहेज लो, हर बूंद' अभियान की अन्य सामग्री।

महिला जज को बार-बार मैसेज व फोन करने पर हाई कोर्ट सख्त

जागरण संवाददाता, नैनीताल

नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार के लक्सर बार एसोसिएशन के सचिव नवनीत तोमर द्वारा महिला न्यायिक अधिकारी को बार-बार मैसेज व फोन करने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय करते हुए आरोपित को स्वयं या अन्य अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आरोपित अधिवक्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। परिवार न्यायालय लक्सर की जज ने 10 जून को लक्सर थाने में दी तहरीर में कहा था कि लक्सर बार एसोसिएशन के सचिव नवनीत तोमर उन्हें बार-बार फोन व मैसेज कर रहे हैं। नंबर ब्लाक किए जाने के बाद वह दूसरे नंबरों से फोन कर रहे हैं। तोमर ने उनके साथ एक समारोह में फोटो खींची थी, जिन्हें प्रिंट कराकर बुके व गिफ्ट के साथ उनके घर भेजने की कोशिश की। वह एक दिन घर भी आ गए, जहां उनके पति ने रोका। स्टाफ द्वारा रोके जाने के बावजूद वह कोर्ट परिसर स्थित चेंबर में भी आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपित अधिवक्ता नवनीत तोमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

आरोपित नवनीत तोमर ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि वह बार एसोसिएशन के सचिव हैं और इसी हैसियत से उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज को फोटोग्राफ व बुके देने का प्रयास किया। उनके चेंबर व घर पर मिलने गए। साथ ही फोन व मैसेज किए। याचिका को कोर्ट ने पहले ही निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने उनके वाट्सएप संदेशों का स्वतः संज्ञान लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की है। पिछले सप्ताह ही उत्तराखंड बार काउंसिल ने भी तोमर को वकालत के पेशे से निलंबित कर दिया था।

72 फीसद से अधिक आबादी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुका है। यूएई सेशेल्स को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा आबादी को दोनों डोज लगाने वाला देश बन गया है।

साइबर हमला कर सैकड़ों कंपनियों से मांगी सात करोड़ डालर की फिरौती

वाशिंगटन, रायटर : एक डार्क वेबसाइट के जरिये हैकरों ने विश्व की सैकड़ों कंपनियों से सामूहिक फिरौती मांगते हुए साइबर हमला किया है। रूस से संबद्ध हैकर ग्रुप ने रविवार को विभिन्न कंपनियों से सात करोड़ डालर (करीब 5.21 अरब रुपये) की फिरौती मांगी है। साथ ही कहा है कि रकम देने पर ही वह कंपनियों का हैक किया डाटा बहाल करेंगे।

डाटा पर डाका
- हैकर समूह ने 17 देशों को निशाना बनाया
- रेविल रैनसमवेयर से प्रभावित हुए हजारों उपभोक्ता


बढ़ रहे हैं साइबर हमला के मामले। फाइल/इंटरनेट मीडिया

रेविल साइबर क्राइम गैंग को साइबर क्षेत्र में फिरौती वसूलने वाले सबसे कामयाब गैंग के रूप में देखा जाता है। साइबर सुरक्षा कंपनी 'रिकार्डेड फ्यूचर' की एलन लिस्का ने कहा, यह गैंग अक्सर किसी न किसी से संबद्ध होकर काम करता है और इसीलिए यह तय करना मुश्किल है कि हैकरों की तरफ से कौन बात कर रहा है। रेविल रैनसमवेयर के शुक्रवार को किए हमले में नाटकीय तरीके से इसकी शिकार कंपनियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है।

हालांकि एपी के अनुसार, साइबर सुरक्षा टीम ने रिकार्ड पर एकल सबसे बड़े वैश्विक रैंसमवेयर हमले के प्रभाव को रोकने के लिए रविवार को उत्साहपूर्वक काम किया। मेमोरियल डे हमले के बाद मीट प्रोसेसर कंपनी जेबीएस से 1.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर जबरन मंगवाने के लिए कुख्यात रेविल गिरोह ने शुक्रवार को 17 देशों में हजारों लोगों को प्रभावित किया।

एफबीआइ ने कहा, वह हमले की जांच कर रहा था, लेकिन घटना की व्यापकता पर प्रत्येक पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना असंभव हो सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को सुझाव दिया कि अगर रूसी सरकार जांच में पूरी तरह से शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। उन्होंने खुफिया एजेंसियों से इस बारे में विवरण मांगा है। हालांकि रूस ने इस संबंध में किसी भी प्रकार का संपर्क होने से इन्कार किया है।

बाइडन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर रेविल और अन्य रैंसमवेयर गिरोहों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने से रोकने के लिए दबाव डाला है, जो लगातार हमले कर रहे हैं जिसे अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस के अनुसार वित्तीय सेवाओं, यात्रा, अवकाश और सार्वजनिक क्षेत्र सहित सभी महाद्वीपों पर नवीनतम हमलों से विभिन्न व्यवसाय और सार्वजनिक संस्थान प्रभावित हुए हैं।

रैंसमवेयर अपराधी आपके नेटवर्क में सेंध लगाते हैं और मैलवेयर फैलाने के लिए आपके सभी डाटा को खंगालते हैं जिसकी सक्रियता के दौरान आपका नेटवर्क खराब हो जाता है। भुगतान के समय पीड़ितों को एक डिकोडर कुंजी मिलती है। स्वीडिश किराना चेन कॉप ने कहा कि उसके कैशियर सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता की खराबी के कारण रविवार को उसके अधिकांश 800 स्टोर बंद रहे। स्वीडिश फार्मेसी चेन, गैस स्टेशन चेन, राष्ट्रीय रेलवे और सार्वजनिक प्रसारक एसवीटी भी प्रभावित हुए।

जर्मनी में एक अज्ञात आइटी सेवा कंपनी ने अधिकारियों को बताया कि हजारों ग्राहक जोखिम में हैं। रिपोर्ट किए गए पीड़ितों में वेल्जआर्ट और दो प्रमुख डच आइटी सेवा कंपनियां होप्पन और ब्राउवर टेकनीक भी शामिल थे। अधिकांश रैंसमवेयर पीड़ित सार्वजनिक रूप से हमले की रिपोर्ट नहीं करते हैं।

समझौता साफ्टवेयर कंपनी कासेया के सीईओ फ्रेड वोकोला ने अनुमान लगाया कि साइबर हमले का शिकार होने वालों की संख्या हजारों में होगी। उनमें से ज्यादातर छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमी हैं, जैसे दंत चिकित्सालय, वास्तु फर्म, प्लास्टिक सर्जरी केंद्र, पुस्तकालय आदि। वोकोला ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर सुरक्षा व्यवस्थाओं को स्वचालित करता है और बैकअप और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं था कि रेविल ने चार जुलाई के अवकाश सप्ताहांत की शुरुआत में हमला किया।

'टीका लगवाना सबसे बड़ी देशभक्ति'

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- स्वतंत्रता दिवस के साथ कोरोना से जल्द आजाद होने का भी जश्न मनाएं

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर नागरिकों से कहा है कि चार जुलाई हमारी स्वतंत्रता का दिन है, इसके साथ ही हम कोरोना महामारी से आजाद होने के भी करीब हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देशभक्ति जताने का सबसे बेहतर माध्यम है। आप वैक्सीन लगवाकर देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम स्वतंत्रता दिवस का उत्सव पूरे जोश के साथ मनाएं, लेकिन ध्यान रहे कि महामारी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

राष्ट्रपति बाइडन ने पहली बार व्हाइट हाउस में एक हजार लोगों के बीच स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन किया। महामारी में राष्ट्रपति की यह पहली सबसे बड़ी सभा थी। इसमें वैक्सीन लगवा चुके लोगों ने बिना मास्क के भाग लिया। इसमें शामिल होने वालों में फ्रंट लाइन वर्कर व जरूरी सेवाओं में काम करने वाले लोग भी शामिल थे।

बाइडन ने कहा कि हम गर्व से कह सकते हैं कि अमेरिका महामारी से पहले की स्थिति में लौट रहा है। इसके लिए हमने वैक्सीन को प्राथमिकता दी और अब धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है।

बाइडन ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस चार जुलाई तक 70 फीसद वयस्कों को कम से कम वैक्सीन की एक खुराक दिए जाने का लक्ष्य रखा था, हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।



खुशी के पल : अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान वाशिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडन, प्रथम महिला जिल बाइडन, सेल्फी लेती पुत्री अश्लेए और पौत्री फिन्नेगन (बाएं से दूसरी) और नाओमी (बाइडन के बराबर में)। रायटर

लगभग 67 फीसद तक लक्ष्य प्राप्त हो सका। बाइडन ने 16 महीने से जारी कोरोना महामारी में छह लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि वे हर रोज मरने वालों और उनके परिजनों को लेकर दुखी होते रहे। अभी भी अमेरिका में हर रोज 200 लोगों की मौत हो रही है।

उन्होंने कहा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाएं। यही नहीं लोग आतिशबाजी करें।

न्यूज गैलरी

चीन अंतरिक्ष से करेगा मौसम की निगरानी

बीजिंग : चीन ने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह 'एफवाई-3ई' को सोमवार को उसकी तय कक्षा में स्थापित कर दिया। इस उपग्रह का इस्तेमाल 11 रिमोट सेंसिंग पेलोड ले जाने और देश के मौसम की सटीक भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में काम करेगा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि सिजुआन प्रांत के शिचांग केंद्र से प्रक्षेपित यह उपग्रह मौसम विश्लेषण, पूर्वानुमान, कृषि, विमानन, समुद्र तथा पर्यावरणीय संरक्षण समेत कई क्षेत्रों के लिए सूचना सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराएगा (प्रेट्र)

बैंकाक की फैक्ट्री में विस्फोट, एक की मौत, 11 घायल

बैंकाक : बैंकाक शहर के बाहरी क्षेत्र में एक फोम व प्लास्टिक की फैक्ट्री में विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 11 लोग घायल हुए हैं। इस फैक्ट्री से जहरीली धुएं की आशंका में पास के हास्पीटल सहित कुछ क्षेत्रों को खाली करा लिया गया। विस्फोट के तुरंत बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी खतरे का अलार्म बज गया। कोई खतरा न होने के बाद फ्लाइट सामान्य रूप शुरू कर दी गईं। विस्फोट इतना जबर्दस्त था कि आसपास के घरों की खिड़कियां उड़ गईं। पुलिस ने आग बुझाने के लिए हेलीकाप्टर का इस्तेमाल किया। (एपी)

स्वेज नहर में फंसने वाले जहाज के मामले में हुआ समझौता

काहिरा : साल के शुरूआत में स्वेज नहर में जापानी कंपनी के स्वामित्व वाले जहाज के फंसने के मामले में मुआवजे को लेकर समझौता हो गया है। अधिकारियों के अनुसार स्वेज नहर में फंसने वाला जहाज एवर गिवेन जापान की शोई किसेन काइशा लिमिटेड का था। कंपनी का यह जहाज क्षतिपूर्ति के विवाद को लेकर यहीं खड़ा हुआ था। अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। यह समझौता कितनी धनराशि में हुआ, इसको गोपनीय रखा गया है। (एपी)

पाक में पानी की कमी से हो सकते हैं अकाल जैसे हालात

इस्लामाबाद : विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्या का हल नहीं किया गया तो पाकिस्तान में पानी की कमी से अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज ने विशेषज्ञों की इस रिपोर्ट को विस्तार से प्रकाशित किया है। रिपोर्ट के अनुसार, कम वर्षा के कारण देश की नदियों के सूखने से खतरे की घंटी बज गई है। अखबार के अनुसार देश में प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता बहुत ही कम या कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। पंजाब प्रांत में तो भूमिगत जल 600 फीट तक नीचे उतर गया है, जो पहले 50 फीट दूरी पर था। (एएनआइ)

यौन उत्पीड़न में मालदीव के पूर्व मंत्री श्रीलंका में गिरफ्तार

कोलंबो : मालदीव के एक पूर्व मंत्री को एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए आरोप में श्रीलंका में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मालदीव के पूर्व वित्त राज्य मंत्री मुहम्मद अशमाली और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि करीब तीन महीने से भी अधिक समय से माउंट लविनीया में 15 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। पुलिस प्रवक्ता और सीनियर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अजीत रोहाना ने बताया कि लड़की की मां समेत इस मामले में 32 लोग संदिग्ध हैं। इसी मामले में उत्तरी मध्य प्रांत से एक नेता और एक प्रमुख रत्न व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया है। (प्रेट्र)

तालिबान के डर से ताजिकिस्तान भागे एक हजार फौजी

निर्णायक जंग ▸ कंधार पर कब्जे की फिराक में आतंकी, अन्य क्षेत्रों में लड़ाई तेज

अफगान सेना से 700 ट्रक, बख्तरबंद वाहन भी कब्जाए

कंधार, एएनआइ : अफगानिस्तान में सुरक्षा बल और तालिबान के बीच लड़ाई निर्णायक दौर में है। तालिबान से युद्ध में कमजोर पड़ रहे एक हजार से अधिक सैनिक पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग गए। इनके वहां पहुंचने की अधिकारियों ने पुष्टि की है।

तालिबान ने ताजकिस्तान की सीमा से लगे छह जिलों पर कब्जा कर लिया है। कंधार के महत्वपूर्ण जिले पंजवेई पर भी तालिबान का नियंत्रण हो गया है। आतंकियों की साफ मंशा है कि किसी भी कीमत पर पूरे सूबे को अपने कब्जे में ले लिया जाए। दक्षिणी प्रांत में पंजवेई पर यह कब्जा अमेरिका और नाटो सेना के बगराम हवाई अड्डा खाली करने के दो दिन बाद हुआ है। इस हवाई अड्डे के खाली करने के बाद तालिबान के हमले तेज हो गए हैं। बदख्शान में यवान जिले पर कब्जे के दौरान 150 अफगान सैनिक आत्मसमर्पण करके तालिबानी आतंकियों के साथ शामिल हो गए हैं।

आइएएनएस के अनुसार इंटरनेट मीडिया के अध्ययन से चौंकाने वाली जानकारी मिली है। तालिबान ने जून माह में ही अफगान सुरक्षा बलों से करीब सात सौ ट्रक और बख्तरबंद वाहनों को छीन लिया है। इनमें काफी संख्या में टैंक भी हैं।

150 सैनिक समर्पण कर आतंकी संगठन में हुए शामिल

अफगानिस्तान के उत्तर क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई की योजना तैयार कर ली गई है। जल्द ही तालिबान से जिलों को मुक्त करा लिया जाएगा।
–हमदुल्लाह मोहिब
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अफगानिस्तान


बदख्शान प्रांत के कई जिलों में तालिबान के कब्जे के बाद राजधानी फैजाबाद में सुरक्षा के लिए पहुंचा अफगान कंमाडो का दस्ता। रायटर

पाकिस्तानी आतंकी भी तालिबान के साथ

एएनआइ के अनुसार, अफगान सेना के मेजर जनरल हिबातुल्लाह अलीजाई ने कहा है कि तालिबानी आतंकियों के साथ पाकिस्तानी भी अफगान सेना से युद्ध कर रहे हैं। ये आतंकी ज्यादातर पंजाब से हैं। इनमें से सैकड़ों आतंकी मारे जा चुके हैं। आइएएनएस के अनुसार कुंदुज प्रांत में अफगान सेना के हवाई हमले में 15 तालिबानी आतंकवादी मारे गए।

सितंबर के बाद अफगानिस्तान में विदेशी सैनिक मिले तो उन्हें खतरा

आइएएनएस के अनुसार, तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा है कि सितंबर बाद विदेशी सैनिक अफगानिस्तान में मिले तो उन पर हमले का खतरा रहेगा। अमेरिका ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया तो तालिबान कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

अफगानिस्तान से वार्ता चुनौतियों को लेकर, हथियार आपूर्ति पर नहीं : एएनआइ के अनुसार रूस ने कहा है कि पिछले सप्ताह अफगानिस्तान के एनएसए से मुलाकात में वहां की चुनौतियों के संबंध में वार्ता हुई थी। हथियारों की आपूर्ति करने के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। ज्ञात हो कि अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्लाह मोहिब रूस गए हुए हैं, जहां उनकी वार्ता वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) निकोलाइ पात्रुशेव से हुई है।

ईरान, तुर्की ने उत्तरी अफगानिस्तान में वाणिज्य दूतावास किए बंद : एएनआइ के अनुसार उत्तरी अफगानिस्तान में हिंसा में तेजी के बाद सुरक्षा की दृष्टि से ईरान और तुर्की ने अपने बाल्ख प्रांत के वाणिज्य दूतावासों को बंद कर दिया है। यहां तालिबान ने कई जिलों पर कब्जा कर लिया है। दूतावास के सभी लोगों को काबुल भेज दिया गया है।

पाक के लिए खतरा बना तालिबान, सीमा और अंदरूनी क्षेत्रों में हमले

- अफगानिस्तान सीमा पर आतंकियों ने मारे तीन पाक सैनिक
- ग्वादर में चीन के लिए भी बढ़ने लगीं दिक्कतें

बीजिंग, प्रेट्र : अब तक अफगानिस्तान में शांति वार्ता की आड़ में राजनीति और दोगलापन कर रहा पाकिस्तान अब चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान सीमा पर आंतकी उसके सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। गत 24 घंटे में वजीरिस्तान के निकट तीन पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों का शिकार हो गए।

हांगकांग स्थित चाइना मार्निंग पोस्ट के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान को ताकत मिलते ही पाक के अंदरूनी क्षेत्रों में टीटीपी समेत कुछ विद्रोही दल फिर तेजी से सिर उठा रहे हैं। ये विद्रोही खैबर पख्तनूख्वा प्रांत के आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उनका बाकायदा वहां पर कब्जा है। तालिबान के खास टीटीपी प्रमुख नूर बली महसूद ने रणनीति के तहत अपने लड़ाकों की तैनाती नए सिरे से शुरू कर दी है। ये पाकिस्तान के उन सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय हैं, जहां पाकिस्तान के सुरक्षा बल कमजोर स्थिति में हैं।

इधर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बलूचों के हमले भी तेज हो गए हैं। बलूचों ने टीटीपी से सड़क किनारे हमले की तकनीक सीख ली है। चार बलूच विद्रोही दल बलूच राजी आजोई संगर के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में ग्वादर पर चीन की योजना का विरोध कर रहे हैं। यहां चीन-पाक आर्थिक गलियारे पर काम हो रहा है। इस परियोजना के लिए बलूच बड़ा खतरा बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार टीटीपी के पांच हजार आतंकी केवल अफगानिस्तान में ही हैं। इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान में फैले हुए हैं।

उच्चस्तरीय वार्ता के लिए ब्रिटेन पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे

लंदन, प्रेट्र : सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को ब्रिटेन पहुंचे हैं। इस दौरान वह अपने ब्रिटिश समकक्ष तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से वार्ता करेंगे और वहां की सैन्य संरचनाओं का दौरा करेंगे। यूरोप दौरे के पहले चरण में जनरल नरवणे ब्रिटेन के रक्षा राज्यमंत्री बेन वालेस, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निक कार्टर व चीफ आफ जनरल स्टाफ जनरल सर मार्क कार्लेटन-स्मिथ से मुलाकात करेंगे। भारतीय उच्चायोग की तरफ से जारी बयान के अनुसार, जनरल नरवणे ब्रिटिश सैन्य संरचनाओं का दौरा करने के साथ-साथ आपसी हित के विषयों पर बातचीत भी करेंगे।

इटली में करेंगे इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन : यूरोप दौरे के दूसरे चरण में जनरल एमएम नरवणे सात जुलाई को इटली पहुंचेंगे। इस दो दिवसीय दौरे में वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हजारों भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। इटली की राजधानी रोम के दक्षिण-पूर्व में स्थित फ्रोसिनोन प्रांत के मोंटे कैसीनो में इस स्मारक का उद्घाटन भारतीय सैनिकों की शहादत के करीब 77 साल बाद किया जाएगा। इटली अभियान में ब्रिटेन व अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत के ही सैनिक शामिल हुए थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इटली की आजादी के लिए 19-22 साल के करीब 50 हजार भारतीय जवानों ने शहादत दी थी।

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने को पाक का पैंतरा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। इस सूची से निकलने के लिए उसकी एक नई पैंतरेबाजी सामने आई है। उसने दिखावे के लिए एंटी मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग सेल गठित की है। पाकिस्तान जून, 2018 से आतंकी फंडिंग को लेकर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी फंडिंग रोकने और इसकी निगरानी के लिए स्थापित एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस में है।

डॉन अखबार में सोमवार को छपी खबर के अनुसार, पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने यह सेल बनाई है। एनएबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एंटी-मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग से मुकाबले के लिए गठित यह सेल एफएटीएफ के साथ समन्वय बनाकर मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने का काम करेगी। अखबार के मुताबिक, सेल की मुख्य जिम्मेदारी आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच होगी।



पाक ने दिखावे के लिए बनाई एंटी मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग सेल। फाइल/इंटरनेट मीडिया

ग्रे लिस्ट में रखा है बरकरार

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की पिछले महीने बैठक हुई थी। इसमें मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने में पाकिस्तान को नाकाम पाया गया था। ऐसे में उसे ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। साथ ही इस्लामाबाद को यह आदेश दिया गया कि वह हाफिज सईद और मसूद अजहर समेत संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित आतंकी संगठनों के सरगनाओं और आतंकियों की जांच करे और उन पर मुकदमे चलाए। एफएटीएफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकी फंडिंग की रोकथाम के उपायों में पाई गईं खामियों का समाधान करे।

जुमा बोले, कोविड में मुझे जेल भेजना मौत की सजा जैसा

जोहानिसबर्ग, एएनआइ : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें जेल भेजना मौत की सजा के बराबर है। जुमा ने कांडला स्थित अपने घर से रविवार शाम पत्रकारों को संबोधित किया। इससे पहले देश की शीर्ष अदालत ने उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा, ताकि उनकी 15 साल कैद की सजा पूरी हो सके।

जुमा ने कहा, 'वैश्विक महामारी का कहर चरम पर होने के दौरान मेरी उम्र के शख्स को जेल भेजना मौत की सजा के बराबर है। द. अफ्रीका में 1995 में मौत की सजा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।'

डेल्टा कहर के बीच ब्रिटेन में लाकडाउन में ढील की तैयारी

- पीएम जानसन बोले, खत्म नहीं हुई है महामारी

लंदन, रायटर : ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट के बढ़ते कहर के बीच लाकडाउन में और ढील देने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जानसन इस संबंध में योजना का एलान करने के साथ ही मास्क पहनने, शारीरिक दूरी के नियमों और घर से काम करने के बारे में दिशा-निर्देश भी जारी करेंगे। 19 जुलाई से ज्यादातर पाबंदियों को खत्म करने की तैयारी है। 12 जुलाई को इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

जानसन ने एक बयान में कहा, 'हम इस वायरस के साथ जीना सीख रहे हैं। हमें कोरोना के खतरे के बारे में सचेत रहना चाहिए। महामारी खत्म नहीं हुई है।' ब्रिटिश सरकार के डाटा से जाहिर होता है कि पाबंदियों में ढील देने के साथ नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि टीकाकरण में तेजी आने से मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने और मौत के मामलों में कमी है। बीते 24 घंटे में 27 हजार 714 नए मामले पाए गए। इनमें से 331 को अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। ब्रिटेन में डेल्टा वैरिएंट के चलते संक्रमण बढ़ रहा है।

नेपाल : आइएएनएस के मुताबिक, काठमांडू घाटी में सभी पाबंदियों को हटा लिया गया है। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद यह कदम उठाया गया है।

बांग्लादेश : रायटर के अनुसार, डेल्टा वैरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देशभर में लाकडाउन को 14 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

संक्रमित के संपर्क में आई केट: समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, ब्रिटिश प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। ब्रिटिश मीडिया की खबरों के मुताबिक, 39 वर्षीय केट वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी हैं। प्रिंस विलियम गत वर्ष अप्रैल में कोरोना के संपर्क में आए थे।

नेपाल में संसद बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संसद (प्रतिनिधि सभा) की बहाली के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली। फैसला संभवतः अगले सप्ताह आएगा। मामले में वादी और प्रतिवादी पक्षों ने संविधान पीठ द्वारा तय समय सीमा में अपने-अपने तर्क दिए हैं। चार न्याय मित्रों ने भी मामले में अपनी कानूनी राय व्यक्त कर दी है। माना जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ 12 जुलाई को फैसला सुनाएगी। पीठ ने संसद की बहाली के लिए दायर 30 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की है। उल्लेखनीय है कि अल्पमत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद भंग कर दी थी।

उधर, नेपाल के चुनाव आयोग ने नवंबर में निर्धारित तिथियों पर मध्यावधि चुनाव कराने के लिए 15 जुलाई से प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। विस्तृत चुनाव कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में घुली आम की मिठास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शेख हसीना ने भारतीय नेताओं को भेजे 2,600 किलो आम

भारत और बांग्लादेश के बीच बेहद मित्रवत रिश्तों में सोमवार को आमों की मिठास भी घुल गई। पीएम शेख हसीना ने मैंगो डिप्लोमेसी को परवान चढ़ाते हुए भारतीय नेताओं को बांग्लादेश की मशहूर हरिभंगा की दर्जनों पेटियां भिजवाई हैं। शेख हसीना की तरफ से राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द, पीएम नरेंद्र मोदी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब को कुल 2,600 किलो आम भिजवाए गए हैं। ढाका से आमों की पेटियां पहले नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग भिजवाई गईं और वहां से सोमवार दोपहर विदेश मंत्रालय भिजवाई गईं। बांग्लादेश ने कहा है कि उसके आमों की मिठास अनूठी होती है और वह इन फलों की मिठास को भारत जैसे मित्र देश के साथ बांटना चाहता है।

दक्षिण एशियाई देशों में पूर्व में भी आमों को कूटनीति में इस्तेमाल करने की परंपरा रही है। भारत के पीएम की तरफ से भी पूर्व में कुछ देशों को आम भिजवाए जाते रहे हैं। हालांकि इस साल किसी भी देश को आम या दूसरा कोई फल भारत के शीर्ष नेताओं की तरफ से नहीं भिजवाए गए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हाल ही में चीन, अमेरिका व कुछ अन्य देशों को अपने आम जरूर भिजवाए थे, लेकिन इन देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया था। इससे अंतरराष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान की बड़ी भद पिटी थी। इन देशों ने कोरोना की वजह से पाकिस्तान का आम स्वीकार करने से मना कर दिया था। बताते चलें कि कुछ साल पहले तक भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच आमों का आदान प्रदान होता रहा है। अंतिम बार 2018 में पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को वहां के मशहूर आम भिजवाए थे। तब दोनों देशों के रिश्ते खराब थे और एलओसी पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। 2017 में भी जब भारत ने विदेश सचिव स्तरीय वार्ता को रद किया था तब भी शरीफ की तरफ से पीएम मोदी व तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आम भिजवाए गए थे। शरीफ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी उनके कार्यकाल में और सत्ता से हटने के बाद भी उन्हें आम भेजा करते थे। शरीफ ने कई वर्षों तक पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी आम भेजा था।

रूस में बच्चों पर किया जा रहा स्पुतनिक वैक्सीन का परीक्षण

मास्को, एपी : रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण शुरू हो गया है। राजधानी मास्को में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। मास्को की डिप्टी मेयर अनास्तासिया राकोवा ने बताया कि ट्रायल में 100 बच्चों को शामिल किया गया है। इनमें से कोई भी पूर्व में कोरोना संक्रमित नहीं हुआ था। वे सभी स्वस्थ बच्चे हैं। इन सभी प्रतिभागियों को स्पुतनिक वी वैक्सीन की छोटी डोज दी जाएगी। रूस में यह ट्रायल ऐसे समय शुरू किया गया, जब रूस में संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। इस देश में बीते 24 घंटे में 24 हजार 353 नए मामले पाए गए और 654 पीड़ितों की मौत हो गई। यहां भी डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ रहा है।

रूसी चर्च ने कहा, वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो होगा पछतावा : रायटर के अनुसार, कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए दुनियाभर में टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रूस के चर्च ने टीका लगवाने से इन्कार करने वालों को फटकार लगाते हुए कहा कि वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो पछतावा होगा। चर्च ने टीका नहीं लगवाने वालों को पापी करार दिया है।



जार्जियो चिएलिनी फाइल फोटो, एएफपी

आज रात 00:30
सोनी नेटवर्क

टूर्नामेंट में अजेय रही स्पेन और इटली की टीमों के बीच खेला जाएगा यूरो कप का पहला सेमीफाइनल

शेर का सामना सवा शेर से

लंदन, एपी : स्पेन यूरो कप में इस बार ऐसी टीम है जो अभी तक हारी जरूर नहीं है, लेकिन उसे जीत भी आसानी से नहीं मिली और उसे जीत अतिरिक्त समय, पेनाल्टी शूटआउट में जाकर हासिल करनी पड़ी है। वहीं, दूसरी ओर इटली की टीम ने पिछले 32 मैचों से हार का मुंह नहीं देखा है और वह इस टूर्नामेंट में आसानी से निर्धारित समय में जीत हासिल करने में सफल रही है। बस प्री-क्वार्टर फाइनल में ही उसे अतिरिक्त समय में जीत हासिल करनी पड़ी थी। ऐसे में स्पेन टूर्नामेंट में शेर है तो इटली सवा शेर है। अब ये दोनों टीमें मंगलवार देर रात को पहले सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी।

32 मैच से इटली की टीम ने कोई भी नहीं गंवाया है और अब वह स्पेन के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी

13 मैचों से स्पेनिश टीम को शिकस्त नहीं मिली है

6 बार यूरो में स्पेन-इटली भिड़े हैं जिसमें दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले जीते हैं और दो ड्रा रहे हैं

यहां तक कैसे पहुंचे

स्पेन : स्पेन का प्री-क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबला शानदार रहा था और टीम ने अतिरिक्त समय में जीत हासिल की थी। लेकिन, अगले मैच में स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए पेनाल्टी शूटआउट तक सहारा लेना पड़ा था, जिसमें गोलकीपर पेड्री ने टीम को हार से बचा लिया। ग्रुप स्तर के मैचों में भी टीम को काफी परेशानी हुई थी।

इटली : इटली ने क्वार्टर फाइनल में विश्व नंबर एक बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था। इटली ने मैच की शुरुआत से लेकर अंत तक अपना नियंत्रण बनाया था और इस टूर्नामेंट में टीम का पहला टेस्ट बेल्जियम के साथ ही था। इटली के कोच राबर्टो मानसिनी की टीम ने गेंद के साथ अच्छा काम किया, जबकि गोलकीपिंग भी बेहतर थी। इटली ने अपने प्रदर्शन से भी दिल जीता है। हालांकि, उसे आस्ट्रिया के खिलाफ अंतिम-16 का मैच अतिरिक्त समय तक खेलना पड़ा था।

जीत का मंत्र

इटली : इटली के पास दो ऐसे हथियार हैं जिससे वह सेमीफाइनल मुकाबला जीत सकती है, जिसमें पहला मिडफील्ड और दूसरा डिफेंस है। वे मिडफील्ड में पूरी ताकत से खेलते हैं और इस टूर्नामेंट में भी वे स्पेन या किसी अन्य टीम की तुलना में सर्वश्रेष्ठ हैं। मार्को वेराट्टी, जोर्गिंहो और निकोलो बारेला ने मिडफील्ड में शानदार काम किया है। रचनात्मक जादू, चतुराई, गेंद पर नियंत्रण जैसी चीजों में वे आगे रहे हैं। इसके अलावा इटली पूरे टूर्नामेंट में डिफेंस में भी मजबूत है और सेंटर-बैक लियोनार्डो बोनुची और जार्जियो चिएलिनी जैसे खिलाड़ियों से इटली के प्रशंसकों को सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन की आस रहेगी। इसके साथ ही चिएलिनी स्पेनिश स्ट्राइकर अल्वारो मोराता की कमियों को अच्छे से जानते होंगे, जिसका फायदा टीम को मिल सकता है। दोनों खिलाड़ी इटली के क्लब जुवेंटस के लिए खेलते हैं। हालांकि, मिडफील्डर लियोनार्डो स्पिनाजोला के चोटिल होने से इटली को नुकसान हुआ है और उनकी भरपाई मुश्किल है।

स्पेन : कोच लुइस एनरिक की टीम के पास मिडफील्ड में कोके और सर्जियो बसक्वेट्स हैं जिन्हें इटली के खिलाफ सेंट्रल एरिया में काम करना होगा। अगर ये दोनों खिलाड़ी सेंट्रल एरिया में अच्छा करने में सफल रहे तो इटली के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा स्पेन इस मैच को जीतने के लिए अपने स्ट्राइकरों के भरोसे भी रहेगा, क्योंकि उनके पास मोराता, गेरेड मोरेनो, फेरान टोरेस, पाब्लो सराबिया और डानी ओल्मा हैं। अगर ये चले तो स्पेन मैच जीतने में सफल हो जाएगा।

आमने-सामने

कुल मैच	स्पेन	इटली	ड्रा
22	8	7	7

मैच का एक्स फैक्टर

सबसे पहले पांच स्थानापन्न खिलाड़ी हैं, जिनका इस्तेमाल निर्धारित समय तक किया जाएगा और अगर मैच अतिरिक्त समय में गया तो यह संख्या छह हो सकती है। अंतिम-16 के मैच में आस्ट्रिया के खिलाफ फेडरिको चिएसा और माटेओ पेसिना ने इटली की तरफ से खेलते हुए मैच में अंतर पैदा कर दिया था। वहीं, स्पेन के लिए माइकल ओयारजाबैल और पाउ टोरेस ने भी क्रोएशिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमों के चतुर मैनेजर इस मैच को कैसे मैनेज करते हैं।



स्पेन के स्ट्राइकर मोराता • फाइल फोटो, एपी

17 देशों ने दिखाई आइसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी में रुचि

दुबई, प्रेट्र : भारत, आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उन 17 सदस्य देशों में शामिल हैं, जिन्होंनेआइसीसी के 2024 से 2031 तक के अगले आठ साल के भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) के चक्र में सीमित ओवरों की प्रतियोगिता की मेजबानी करने में दिलचस्पी जताई है। आइसीसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आइसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, मलेशिया, नामीबिया, न्यूजीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, स्काटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, यूएई, अमेरिका व जिंबाब्वे से आइसीसी को प्रारंभिक प्रस्तुतियां मिली हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआइ ने पिछले महीने तीन वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के लिए दावा पेश करने का फैसला किया है, जिसमें छोटे प्रारूपों के दो विश्व कप भी शामिल हैं। साल 2024 से शुरू होने वाले अगले एफटीपी चक्र के दौरान बीसीसीआइ किसी भी मेजबानी शुल्क का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है। बीसीसीआइ के लिए एक अहम मुद्दा कर छूट का भी होगा, जो उसे किसी भी आइसीसी आयोजन की मेजबानी के लिए अपनी सरकार से हासिल करना जरूरी है।

अर्जेंटीना को फाइनल का टिकट दिलाने उतरेंगे मेसी

ब्रासीलिया, एपी : अर्जेंटीना के सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी ने राष्ट्रीय टीम के लिए अपना पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने की उम्मीदें जीवंत रखी हुई हैं और उन्होंने कोपा अमेरिका में दमदार प्रदर्शन करके टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया है। अब वह बुधवार की सुबह जब राष्ट्रीय टीम की ओर से अपना 150वां मैच खेलने उतरेंगे तो उनकी कोशिश इस सेमीफाइनल मुकाबले में कोलंबिया के खिलाफ जीत हासिल करके टीम को फाइनल का टिकट दिलाने की रहेगी।

34 वर्षीय मेसी ने ग्रुप स्तर के पहले मैच में चिली के खिलाफ गोल करके टूर्नामेंट में अच्छा आगाज किया था। फिर उरुग्वे के खिलाफ 1-0 की जीत में उन्होंने गोल करने में मदद की थी। फिर बोलविया के खिलाफ 4-1 की जीत में उन्होंने दो गोल दागे थे, जबकि गोमेज के गोल में उन्होंने मदद की। इसके अलावा पिछले मैच में इक्वाडोर के खिलाफ 3-0 की जीत में पहले उन्होंने दो गोल करने में मदद की और फ्री किक पर शानदार गोल करके कोलंबिया के लिए चिंता बढ़ा दी। अभी तक टूर्नामेंट में मेसी मैजिक देखने को मिला है और सेमीफाइनल में भी टीम को उनसे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। इक्वाडोर के खिलाफ उनका बार्सिलोना से करार खत्म होने के बाद पहला मैच था। कोलंबिया के लिए उन्हें रोकना चुनौती जरूर रहेगी, लेकिन यह टीम उलटफेर करने माहिर भी है। कप्तान मेसी भी कह चुके हैं कि कोलंबिया मजबूत टीम है और हम उन्हें हल्के में नहीं लेंगे। अर्जेंटीना के खिलाफ गोल का दारोमदार कोलंबिया के स्ट्राइकर मिगुएल बोर्जा के कंधों पर होगा जिन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में तीन गोल दागे हैं। इस मैच को जीतने वाली टीम ब्राजील व पेरू के बीच सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगी। अगर ब्राजील जीतता है तो मेसी बनाम नेमार का रोमांचक फाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि मेसी व नेमार बार्सिलोना के लिए भी साथ खेल चुके हैं।

आमने-सामने

कुल मैच	अर्जेंटीना	कोलंबिया	ड्रा
33	19	7	7

ब्राजील vs पेरू		पहला सेमीफाइनल
सुबह 4:30 बजे	दिन : मंगलवार	
अर्जेंटीना vs कोलंबिया		दूसरा सेमीफाइनल
सुबह 6:30 बजे	दिन : बुधवार	
सोनी नेटवर्क		



लियोन मेसी • फाइल फोटो, एएफपी

50वीं बार ग्रैंडस्लैम के क्वार्टर फाइनल में जोकोविक

लंदन, एपी : मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविक ने सोमवार को अपनी प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आसान जीत के साथ 50वीं बार किसी ग्रैंडस्लैम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविक ने 17वीं वरीयता प्राप्त क्रिस्टियन गारिन को 6-2, 6-4, 6-2 से हराया। वह विंबलडन में 12वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं।

विंबलडन में सर्वाधिक बार अंतिम आठ में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में रोजर फेडरर (18) और जिम्मी कोनर्स (14) के बाद वह आर्थर गोरे के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पुरुष वर्ग में तीन खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इनमें रूस के 25वें नंबर के कारेन खचानोव भी शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को उनके 21वें जन्मदिन पर 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8 से हराया। आखिरी सेट में इन दोनों ने 13 बार एक-दूसरे की सर्विस तोड़ी।

खचानोव का अगला मुकाबला 10वें नंबर के डेनिस शापोवालोव से होगा जिन्होंने 15 ऐस लगाकर आठवें नंबर के राबर्टो बातिस्ता आगुट को 6-1, 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। खचानोव और शापोवालोव के अलावा सातवें नंबर के मैटियो बेरेटिनी भी पहली बार विंबलडन के अंतिम-आठ में पहुंचे। उन्होंने इलिया इवाश्का को 6-4, 6-3, 6-1 से हराया। वह पिछले 23 वर्षों में यहां क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी हैं।

महिलाओं के वर्ग में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी एश्ले बार्टी भी पहली बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। उन्होंने फ्रेंच ओपन चैंपियन बारबोरा क्रेजिकोवा को 7-5, 6-3 से हराया। ट्यूनिशिया की ओंस जाबेर विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली अरब देशों की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने 2020 की फ्रेंच ओपन की चैंपियन इगा स्वियातेक को कड़े मुकाबले में 5-7, 6-1, 6-1 से परास्त किया। दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका भी पहली बार ग्रैंडस्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। उन्होंने इलेना रिबाकिना को 6-3, 4-6, 6-3 से हराया। आठवें नंबर की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने लियुडमिला समसोनोवा को 6-2, 6-3 से पराजित किया।



मैच जीतने के बाद खुश जोकोविक • रायटर

नतीजे अच्छे मिलें तो शास्त्री को हटाने की क्या जरूरत : कपिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव का मानना है कि अगर रवि शास्त्री अच्छे नतीजे दे रहे हैं तो उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से हटाने की कोई वजह नहीं है। अक्टूबर-नवंबर में यूएई में होने वाले टी-20 विश्व कप के बाद शास्त्री का करार खत्म होने वाला है। उनका आगे इस पद पर बने रहना इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह फिर से आवेदन करना चाहते हैं या नहीं। अटकलें हैं कि बीसीसीआइ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के मौजूदा प्रमुख राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच बना सकता है जो इस समय सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं। कपिल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि इस बारे में अभी बात करने की जरूरत है। देखते हैं कि श्रीलंका में प्रदर्शन कैसा रहता है। नए कोच को तैयार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर शास्त्री अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें हटाने की भी कोई वजह नहीं है।'

मेरी कोम व मनप्रीत होंगे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक

आठ अगस्त को होने वाले समापन समारोह में बजरंग निभाएंगे ध्वजवाहक की भूमिका

ओलंपिक

नई दिल्ली, प्रेट्र : छह बार की विश्व चैंपियन और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज एमसी मेरी कोम और पुरुष हाकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह 23 जुलाई से टोक्यो में शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पूनिया आठ अगस्त को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे।

भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने इन खेलों की आयोजन समिति को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जबकि ओलंपिक में भारत के दो ध्वजवाहक (एक पुरुष और एक महिला) होंगे। आइओए प्रमुख नरेंद्र बत्रा ने हाल ही में आगामी टोक्यो खेलों में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए इस की जानकारी दी थी। कोविड के कारण एक साल के लिए स्थगित हुए ओलंपिक में 100 से अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेंगे। आइओसी ने पिछले साल कार्यकारी बोर्ड की बैठक में उद्घाटन समारोह में महिला व पुरुष ध्वजवाहकों के लिए प्रविधान किया था।



यह मेरे लिए बहुत बड़ा पल होगा, क्योंकि यह मेरा आखिरी ओलंपिक है। मेरे लिए यह भावनात्मक पल हो सकता है। उद्घाटन समारोह में दल की अगुआई करने का मौका पाकर मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रही हूं और मेरा चयन करने के लिए मैं खेल मंत्रालय और आइओए को धन्यवाद देती हूं। यह मेरे लिए प्रेरणा होगी। मैं पदक के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा करती हूं। **एमसी मेरी कोम**



यह शानदार है और मेरे पास इसकी खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। मुझे लगता है कि दिग्गज मेरी कोम के साथ उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक नामित किया जाना बड़ा सम्मान है। मैं इस शानदार अवसर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को धन्यवाद देता हूं और मैं टोक्यो ओलंपिक के दौरान उद्घाटन समारोह में अपनी जिम्मेदारी निभाने का इंतजार कर रहा हूं। **मनप्रीत सिंह**



एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करे। मेरे लिए यह अति सौभाग्य का पल होगा जब मैं टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह का हिस्सा बनूंगा। एक खिलाड़ी होने के नाते भारतीय होने के अहसास को हर पल जीना उसकी जिम्मेदारियों को और भी बढ़ाता है। निश्चित ही ओलंपिक में हर भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने वाला है। **बजरंग पूनिया**

पृथ्वी और पडीक्कल को इंग्लैंड नहीं भेजने को लेकर सवालों में घिरी चयनसमिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंग्लैंड में भारतीय टीम प्रबंधन युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शा और देवदत्त पडीक्कल को टीम में रखना चाहता था, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या चयनसमिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा भी ऐसा चाहते थे?

सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बंगाल के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु मिथुन को 2019-20 के रणजी सत्र में लचर प्रदर्शन करने और भारत-ए के न्यूजीलैंड दौरे में भी रन नहीं बनाने के बावजूद इंग्लैंड गई टीम में कैसे स्टैंडबाई रखा गया? इसमें कोई दो राय नहीं कि ईश्वरन टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं थे तथा शा और पडीक्कल जैसे खिलाड़ियों पर उन्हें प्राथमिकता देने से कई लोगों की भौंहे तन गई हैं।

बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा, 'शुभमन गिल चोटिल होने के कारण इंग्लैंड के पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं। उन्हें फिट होने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। पिछले महीने टीम के प्रशासनिक प्रबंधक ने पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को पत्र भेजकर दो अन्य सलामी बल्लेबाजों को ब्रिटेन भेजने के लिए कहा था।'

गिल के चोटिल होने पर भारतीय टीम प्रबंधन चाहता था शा और देवदत्त को इंग्लैंड बुलाना

गिल की चोट की स्थिति जानने के बावजूद माना जा रहा है कि शर्मा ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर खास ध्यान नहीं दिया। अब देखना यह है कि क्या टीम प्रबंधन शा और पडीक्कल को भेजने के लिए बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह से औपचारिक अनुरोध करता है। शाह चयनसमिति के संयोजक भी हैं। सूत्र ने कहा, 'शा और पडीक्कल को भेजने के लिए बीसीसीआइ अध्यक्ष को अभी तक औपचारिक अनुरोध नहीं मिला है। ये दोनों बल्लेबाज अभी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका में हैं, लेकिन 26 जुलाई को यह दौरा समाप्त होने के बाद दोनों इंग्लैंड जा सकते हैं। लेकिन, मुझे लगता है कि टीम प्रबंधन उन्हें पहले टीम में जोड़ना चाहता है।'

असल में शर्मा ने यदि पिछले महीने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर गौर किया होता तो शा और पडीक्कल अभ्यास मैच के लिए सही समय पर इंग्लैंड पहुंच सकते थे। क्या टीम प्रबंधन ने विशेषकर शा को भेजने के लिए कहा है, इस सवाल पर सूत्र ने कहा, 'उन्हें आधिकारिक मेल करने दो और फिर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इंग्लैंड दौरे पर 23 खिलाड़ी गए हैं और यदि हम ईश्वरन को नहीं भी गिनते तब भी उनके पास तीन विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज हैं।'

पृथ्वी के बजाय ईश्वरन को प्राथमिकता देने पर एक पूर्व चयनकर्ता ने कहा, 'उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी कौशल के मामले में ईश्वरन से मीलों आगे हैं और यह नहीं भूलना चाहिए कि वह टेस्ट शतक लगा चुके हैं और अभी अच्छी फार्म में हैं।'

पहलवान सुमित दो साल के प्रतिबंध को देंगे चुनौती

मलिक सजा में कटौती कर इसे छह महीने करने की मांग करेंगे, डोप के मामले में मिली है सजा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारतीय पहलवान सुमित मलिक ने डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर उन पर लगाए गए दो साल के प्रतिबंध को चुनौती देने का फैसला किया है और वह सजा में कटौती की मांग करेंगे, ताकि अगले साल राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकें।

राष्ट्रमंडल खेल 2018 के स्वर्ण पदक विजेता सुमित पर युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने शुक्रवार को दो साल का प्रतिबंध लगा दिया, जब उनके दूसरे नमूने में भी प्रतिबंधित पदार्थ के अंश पाए गए।

टोक्यो ओलंपिक में 125 किग्रा में क्वालीफाई कर चुके सुमित ने स्वीकार किया कि वह शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ पाए जाने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बेईमानी नहीं था। वह अपील करेंगे कि उनकी सजा घटाकर छह महीने की कर दी जाए। सुमित के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने एक खास सप्लीमेंट अमेरिका में जांच के लिए भेजा है। इसके साथ ही वह दवा भी भेजी है जो सुमित ने ली थी, ताकि यह पता किया जा सके कि क्या वह पदार्थ इनके जरिये उनके शरीर में आया है। सूत्र ने कहा, 'हम बचाव तैयार कर रहे हैं और दो साल के प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। सुमित एक सप्लीमेंट और कोरोना की दवा ले रहे थे। शायद उनके जरिये वह पदार्थ उनके शरीर में आया हो। हम सजा में कटौती की मांग करेंगे। हमने वाडा से और सूचना मांगी है। सुमित के ए नमूने में पदार्थ की मात्रा नाममात्र की थी। हमने बी नमूने का ब्योरा भी मांगा है।'

सुमित का प्रतिबंध तीन जून से शुरू हुआ है और इसके छह महीने का होने पर ही वह बर्मिंघम में अगले साल 28 जुलाई से होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकेंगे।

ओलंपिक पदक की उम्मीदों को पूरा करने के लिए फिर तैयार सिंधू

शुभम पांडेय • नई दिल्ली

पदक के दावेदार
TOKYO 2020
17 दिन शेष

भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में साल 2001 एक सुनहरा पल लेकर आया, जब पुलेला गोपीचंद ने आल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। उसी समय हैदराबाद में घर में बैठी एक लड़की ने मन में बैडमिंटन खेलने की ऐसी ठानी कि उसने पूरी दुनिया को अपने जलवे से रूबरू करा दिया। हम बात कर रहे हैं पुसारला वेंकटा सिंधू यानी पीवी सिंधू की, जो रियो ओलंपिक में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हारकर स्वर्ण पदक जीतने से एक कदम पीछे रह गईं। इसके बावजूद भारत को बैडमिंटन में सिंगल्स स्पर्धा का ओलंपिक रजत पदक जिताने वाली वह पहली खिलाड़ी बनीं। सिंधू हाथ में रैकेट लेकर ओलंपिक पदक की करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक बार फिर तैयार हैं।

खुलकर खेलने देना होगा : मारिन के टोक्यो ओलंपिक से हटने के बाद क्या सिंधू स्वर्ण पदक की दावेदार हैं, जब भारत के पहले एशियाई चैंपियन (1965) और पूर्व खिलाड़ी दिनेश खन्ना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने दैनिक जागरण को बताया कि अगर हम सिंधू को उम्मीदों के बोझ से हल्का रखेंगे तो वह ऐसा जरूर कर सकती हैं। दिनेश ने कहा, 'रियो की तरह ही हमें इस बार भी उनसे कम उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि जब वह रियो में खेलने गई थीं तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वह पदक जीतेंगी। लेकिन, उन्होंने फाइनल में जगह बनाई और रजत पदक जीता। इसी तरह हमें इस बार भी उन्हें ओलंपिक में खुलकर खेलने देना चाहिए।'

फिटनेस पर करना होगा काम : रियो ओलंपिक के बाद सिंधू को कई टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना पड़ा, जिससे उबरते हुए उन्होंने 2019 में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली भी वह पहली भारतीय महिला बन गईं। हालांकि, इस जीत के बाद वह कुछ कमाल नहीं कर सकीं और फिर कोरोना के चलते सब कुछ बंद हो गया। दिनेश ने सिंधू के प्रदर्शन को आंकते हुए कहा, 'रियो में सिंधू ने एक नया शाट सभी को दिखाया था। वह यह कि बैकहैंड में कोर्ट के पीछे से जाकर वह क्रास रिटर्न करती थीं। इस शाट ने सबका मन मोह लिया था। उसके बाद 2019 का खिताब जीतकर सिंधू ने आपनी दावेदारी मजबूत की और फाइनल में हारने के सूखे को खत्म किया। लेकिन, इस प्रतियोगिता के बाद उनके लिए फिटनेस एक समस्या बन गई। उम्मीद करता हूं कि सिंधू अपनी फिटनेस पर काम करेंगी और टोक्यो में भी आक्रामकता के साथ नया अंदाज लेकर आएंगी।'

इनसे मिलेगी चुनौती : मारिन की गैरमौजूदगी में सिंधू को किससे चुनौती मिल सकती है, इस बारे में दिनेश ने कहा, 'शीर्ष-10 में नोजुमी ओकुहारा, ताई त्जु यिंग, अकाने यामागुची और रत्चानोक इंतानोन जैसी खिलाड़ी किसी भी दिन किसी को हरा सकती हैं। इन सभी के खेल में काफी सामानता है। सिंधू के लिए चीनी शटलर सबसे बड़ी चुनौती बन सकती हैं, क्योंकि उनका खेल किसी ने देखा नहीं है और कोरोना के चलते वह खेली भी नहीं हैं। ऐसे में उसके लिए सिंधू को तैयार रहना होगा।'

पूर्व एशियाई चैंपियन दिनेश खन्ना ने कहा, पीवी के पदक की राह में सबसे बड़ी बाधा चीन

आठ साल की उम्र में ही थाम लिया था रैकेट

सोमवार को 25 साल की हुई सिंधू ने आठ साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने महबूब अली की देखरेख में बैडमिंटन की बेसिक ट्रेनिंग सिकंदराबाद के रेलवे इंस्टीट्यूट आफ सिग्नल इंजीनियरिंग ग्राउंड से शुरू की थी। इसके बाद सिंधू ने पुलेला गोपीचंद की हैदराबाद स्थित गोपीचंद अकादमी में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। इन दिनों वह हैदराबाद में ही गाचिबाउली स्टेडियम में अभ्यास कर रही हैं।

सिंधू की उपलब्धियां

ओलंपिक	रजत पदक (2016)
विश्व चैंपियनशिप	स्वर्ण पदक (2019), रजत पदक (2017 व 2018), कांस्य पदक (2013 व 2014)
एशियाई खेल	रजत पदक (2018)
राष्ट्रमंडल खेल	रजत पदक (2018), कांस्य पदक (2014)
एशियाई चैंपियनशिप	कांस्य पदक (2014)



पीवी सिंधू • फाइल फोटो, ट्विटर



निर्झरिणी



ज्ञानी उस व्यक्ति को कहते है, जो भूत और भविष्य से ध्यान हटाकर वर्तमान का अच्छी तरह अवलोकन करता है और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ही आचरण करता है।

-आचार्य विनोबा भावे

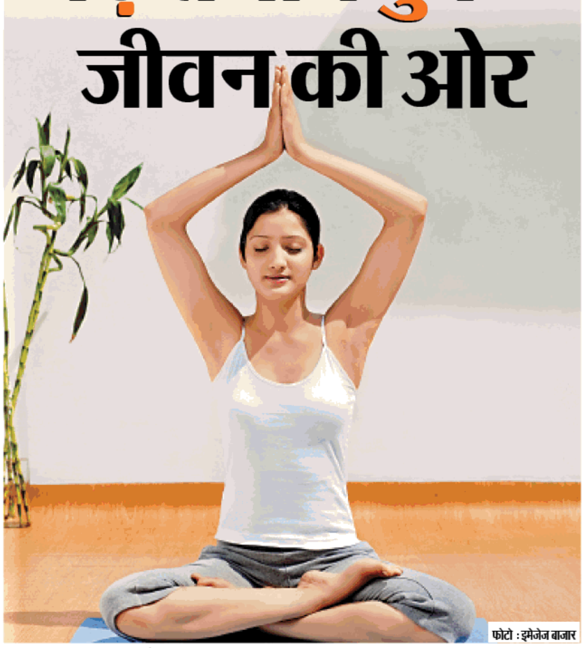
बढ़ें तनावमुक्त जीवन की ओर

कोरोना काल में मन को तनाव रहित रखना ही होगा, क्योंकि मन का स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डालता है। ऐसे में उत्साह, सतर्कता, ध्यान निद्रा आदि के माध्यम से हम तनावमुक्त रह सकते हैं...

जीवन दर्शन



श्री श्री रविशंकर
आध्यात्मिक गुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता



फोटो : इमेजेज बाजार

एक बार मुल्ला नसरुद्दीन दुर्घटना में घायल हो गए। उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। केवल आंखें दिख रही थीं। एक मित्र उनसे मिलने आए और पूछा, 'कैसे हो, मुल्ला?' उन्होंने कहा, 'मैं ठीक हूं, बस जब हंसता हूं तो दर्द होता है।' मित्र ने पूछा, 'इस हालत में आप हंस कैसे सकते हैं?' मुल्ला ने जवाब दिया, 'अगर मैं अब नहीं हंसूंगा तो जिंदगी में कभी हंस नहीं पाऊंगा।' यह अविरत उत्साह संपूर्ण स्वास्थ्य में रहने का आयाम है। संस्कृत में स्वास्थ्य के लिए शब्द है 'स्वस्ति' अर्थात वह प्रबुद्ध व्यक्ति, जो स्व में स्थित है। स्व में बने रहने की पहली निशानी है उत्साह। वह उत्साही व्यक्ति, जो हंसकर यह कह सके कि 'आज कोई काम नहीं बना।' यह कह सकने के लिए ऐसी मानसिक स्थिति चाहिए, जो तनाव-मुक्त हो।

हम एक ऊर्जा के बादल में संपुटित हैं, जिसे चेतना कहते हैं। यह एक मोमबत्ती और बाती जैसा है। जब हम मोमबत्ती पर माचिस की तीली लगाते हैं, तो बाती में ज्योति प्रकट होती है। मोमबत्ती में भी वही हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जब उसे प्रज्वलित किया जाता है, तब ज्योति केवल उसकी चोटी पर टिमटिमाती है। हमारा शरीर भी मोमबत्ती की उसी बाती की तरह है। इसके आसपास चेतना है, जो हमें जीवित रखती है। इसलिए हमें अपने मन और आत्मा का ध्यान रखना चाहिए।

हमारे अस्तित्व के सात स्तर हैं - शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहं और आत्मा। मन चेतना में विचार और अनुभूति की समझ है, जो निरंतर बदलती रहती है। आत्मा हमारी अवस्था और अस्तित्व का सूक्ष्मतम पहलू है। मन और शरीर को हमारी सांस जोड़ती है। जैसे हमारा शरीर बदलाव से गुजरता है, वैसे ही मन, बुद्धि, समझ, धारणाएं, स्मृति, अहं भी। लेकिन हमारे भीतर जो नहीं बदलता, उसे आत्मा कहते हैं, जो सब बदलावों का संदर्भ बिंदु है। जब तक हम इससे नाता नहीं जोड़ेंगे, आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं माने जाएंगे।



गहरा विश्राम है ध्यान

तनावमुक्त होने और अपनी ऊर्जा को पुन: प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने एक अंतर्निहित व्यवस्था बनाई है, जो है निद्रा। किसी हद तक निद्रा तुम्हारी थकान मिटाती है, लेकिन प्राय: शरीर प्रणाली में तनाव रह जाता है। इस प्रकार के तनावों को काबू में रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान के तरीके हैं। ये तनाव और थकान से मुक्ति देते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं, ये तंत्रिका तंत्र और मन को मजबूत बनाते हैं। ध्यान एकाग्रता ही नहीं है, यह एक गहरा विश्राम है और जीवन को एक अधिक विशाल दृष्टि से देखने का प्रयोजन भी है। इसे पाने के तीन स्वर्णिम नियम हैं - मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं करता हूं और मैं कुछ नहीं हूं।

स्वास्थ्य की दूसरी निशानी है सचेतता। सतर्क और जागरूक रहना। मात्र सतर्क रहना ही काफी नहीं है। इसके साथ ही तनाव-मुक्त भी होना चाहिए। इन दोनों के योग की स्थिति को ज्ञानोदय कहते हैं। भावनात्मक अस्थिरता तनाव के कारणों में से एक है। हरेक भावना के लिए हमारे श्वास की विशेष लय है। धीमे और लंबे श्वास आनंद और उग्र श्वास तनाव का संकेत देते हैं। अगर विफलता मिलती है तो क्या हुआ? हरेक विफलता एक नई सफलता की ओर कदम है। अपना उत्साह बढ़ाएं। आपमें यदि कुशलता है तो किसी भी परिस्थिति को हास-परिहास में बदल सकते हैं। तनावयुक्त होना छोड़ें। पशु जब गीले हो जाते हैं तो वे अपना शरीर झकझोरते हैं और सब कुछ बाहर निकाल फेंकते हैं। हम क्यों तनाव को लादे रहें। किसी कुत्ते, पिल्ले या बिल्ली को देखकर हमें सब कुछ झकझोरना आना चाहिए। जब आप आफिस में आते हैं, तो घर को झकझोर दें। जब आप घर वापस जाएं, अपने कंधों से आफिस को झकझोर दें।

अपनाएं सांस्कृतिक मूल्य

प्रासंगिक चिंतन



डा. अविनाश कुमार श्रीवास्तव
अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग
प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विवि, प्रयागराज



मानव अस्तित्व के मौजूदा विपदा काल में बौद्धिकों, विचारकों और मनस्वियों का यह प्रधान दायित्व और कर्तव्य बन जाता है कि वे स्वयं के साथ अखिल विश्व को इस महामारी से बचने-बचाने का मार्ग दिखाएं। इसी के साथ ही प्रभावी समाधान के तौर पर हमें स्वतः ही आध्यात्मिक मूल्य अपनाकर मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। कोविड-19 जैसे छलावा वायरस को शिकस्त देने के लिए तमाम चिकित्सीय उपचारों के साथ-साथ हमें अपनी वैचारिकी, अपनी आध्यात्मिक मूल्यसंपदा, प्रकृति के साथ तादात्म्य वाली जीवन शैली को पुनः एक बार अपनी जीवन कला में समाहित करते हुए सार्थक गति देनी ही होगी।

दरअसल, भारतीय जीवन में आध्यात्मिक प्रयोजन का स्थान सदा ही सर्वोपरि रहा है। भारत में धर्म की रुचि मनुष्य के आत्मा में है। जब दृष्टि बाहर की ओर (यानी सांसारिक भोग-विलास की तरफ होती है) तो निरंतर बदलती हुई घटनाओं का प्रवाह ध्यान आकृष्ट कर लेता है। इसके विपरीत कठोपनिषद का सूत्र 'आत्मानं वृद्धि' अर्थात अपने आत्मा को पहचानो, यही भारत में आध्यात्मिक जागरण का शंखनाद है। कोरोना जैसी महामारी हमें निश्चित रूप से यह सुअवसर प्रदान कर रही है।

प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंसटीन ने भी कहा है कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। वस्तुतः यह हमारी वैचारिक प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है कि हम संकट से ग्रस्त होते हैं या संकट पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने को और अधिक सशक्त बनाते हैं।

भौतिक जगत में जिसे कानून कहा जाता है, सदाचार जगत में उसे ही धर्म कहते हैं और यही धर्म हमारे आध्यात्मिक मूल्यों और मानसिक स्वास्थ्य का आधार बिंदु है। महामारी के इस विपत्ति काल में हमें अपनी समृद्ध, उत्कृष्ट, उन्नत और श्रेष्ठ वैचारिकी की तरफ लौटना होगा। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, 'प्राणारामं मन आनंद शांतिसमृद्धम अमृतम्' अर्थात जीवन एवं मन को आह्लाद देने वाली शांति एवं नित्यता ही पूर्णता है।

निम्न स्तर के लक्ष्यों को तिलांजलि देते हुए ईशा उपनिषद के इस भाव को हमें अपने जीवन में पूर्णतः चरितार्थ करना ही पड़ेगा, जो कहता है कि तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः अर्थात त्याग भाव से तुम भोग करो।

प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संवेदनहीन दोहन और मानव मन की जगत-विजय की विवेकशून्य, अंतहीन लालसा ही कोरोना जैसी महामारियों को निमंत्रण देती है। यदि हमें इसे परास्त करना है तो प्रकृति के साथ स्वयं को आत्मसात करते हुए अपने आध्यात्मिक मूल्यों के संग, सकारात्मक, जाग्रत और स्वस्थ वैचारिकी को अपनी जीवन शैली में समाहित करना होगा।

ज्ञान-आलोक

पुस्तक : सफलता पाने के सात आध्यात्मिक सिद्धांत
लेखक : डा. दीपक चोपड़ा
प्रकाशन : प्रभात प्रकाशन

उन्नति का आध्यात्मिक पथ



वक्ता व विचारक डा. दीपक चोपड़ा ने एक किताब लिखी है, 'द सेवन स्पिरिचुअल लाज आफ सक्सेस'। हिंदी में यह किताब 'सफलता पाने के सात आध्यात्मिक सिद्धांत' के रूप में अनूदित हुई है। कुछ लोग अपना लक्ष्य पाने में असफल हो जाते हैं, तो उनके मन में निराशा का भाव जन्म ले लेता है। लेखक ने कहा है कि व्यक्ति यदि कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों या नियमों को अपना ले, तो वह न केवल सफल होगा, बल्कि उसका जीवन भी शांतिपूर्ण ढंग से बीतेगा। ये सभी नियम प्रकृति द्वारा बनाये नियमों पर ही आधारित हैं। इन्हीं नियमों से हमारी प्रकृति संचालित होती है और संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर गतिमान होता रहता है।

जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले चेतना या चैतन्य होने की चर्चा की जाती है। डा. दीपक ने भी माना है कि हमारी चेतना ही सभी संभावनाओं का द्वार है। इसलिए हमें चैतन्य होना होगा। इसे हम मौन, ध्यान और साधना के अभ्यास से ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम दान का है। यदि कोई व्यक्ति खुश रहना चाहता है या प्रेम पाना चाहता है, तो दूसरों को भी खुशी प्रदान करे या प्रेम दे।

लेखक ने बिना परिणाम की चिंता किए हुए कर्म करते रहने को तीसरा आध्यात्मिक सिद्धांत माना है। अल्प प्रयास को चौथा सिद्धांत माना गया है। इसके अनुसार, व्यक्ति जिस परिस्थिति में है, उसे स्वीकार करे। व्यक्ति के उद्देश्य और इच्छा का पांचवां सिद्धांत है, जो बताता है कि यदि इच्छा पूरी नहीं होती है, तो इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा-इस वक्तव्य पर विश्वास रखे। कुछ भी प्राप्त करने के प्रति मोह त्याग ही है अनासक्ति का छठा नियम। धर्म का पालन है सातवां सिद्धांत। स्वयं की योग्यता का उपयोग मानव सेवा में करना ही सभी व्यक्तियों का धर्म है।

स्मिता सिंह

प्रेरक प्रसंग

उत्साह में न खोएं अपना होश

एक दंत कथा है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उसमें दो हंस भी रहते थे, जिनकी कछुए से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हंस उस कछुए को हमेशा दूर देशों, वनों और पहाड़ों की अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाया करते थे। वे यह भी बताते कि आसमान से देखने पर धरती कितनी सुंदर लगाती है। उनकी बातें सुनकर कछुए का मन भी बाहर निकलने को होने लगा। वह भी बादलों में घूमना चाहता था। उसने हंसों से निवेदन किया कि वे उसे भी आसमान की सैर कराएं। हंस एक छड़ी लेकर आए और कछुए से कहा कि वह उसे बीच में मुंह से पकड़ ले। हंसों ने कहा कि वे उस छड़ी को दोनों तरफ से अपनी-अपनी चोंच से पकड़ कर रखेंगे और आसमान में उड़ जाएंगे। हालांकि हंसों ने कछुए से यह ध्यान रखने को कहा कि उड़ान भरते समय उसे अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना वह धरती पर आ गिरेगा। इस तरह से कछुए की रोमांचकारी उड़ान शुरू हो गई। पलक झपकते ही हंस हवा से बातें करने लगे। कछुए के लिए यह किसी स्वप्न सरीखा था। जब वे किसी गांव के ऊपर से उड़ रहे थे, तो वहां के लोगों ने आसमान में यह अद्भुत दृश्य देखा कि दो हंस कछुए को आसमान की सैर करा रहे हैं। कछुआ सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वह अपने उल्लास को जाहिर करने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और उसके प्राण पखेरू उड़ गए।

कथामर्म : उत्साह में हमें अपने विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए।

सप्ताह के पर्व-त्योहार



10 जुलाई : स्नान-दानादि की अमावस्या
12 जुलाई : जगन्नाथपुरी रथयात्रा प्रारंभ

जगन्नाथपुरी रथयात्रा पर विशेष

एकांतवास के बाद दर्शन देंगे महाप्रभु

भगवान विष्णु के दशावतारों में माने जाने वाले महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथयात्रा का शुभारंभ पुरी में 12 जुलाई से हो रहा है। इस यात्रा में देश-विदेश से अपार श्रद्धालु हिस्सा लेते रहे हैं, किंतु गत वर्ष से यह कोरोना की गाइडलाइन के अनुरूप ही संपन्न हो रहा है। देखा जाए, तो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी की कथा में कोरोना जैसी महामारियों के प्रति जागरूकता प्रदान की गई है...



भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा को स्नान कराने का दृश्य (फाइल फोटो)। ●जागरण



ओडिशा के पुरी में यात्रा के लिए तैयार किए जा रहे रथ। ●जागरण

सदियों पूर्व जब कोरोना नाम की बीमारी नहीं थी, तब बुखार होने पर 14 दिनों के क्वारंटाइन और पौष्टिक खानपान जैसी सावधानी बरतने का संदेश महाप्रभु जगन्नाथ दे चुके हैं। उनसे जुड़ी कहानी में इसकी बानगी देखी जा सकती है। कहानी यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ ने जैसे ही पूर्णिमा को ठंडे पानी से स्नान किया, तो वे बीमार पड़ गए। बुखार से तपने लगे। तब उन्होंने 14 दिनों के लिए एकांतवास (क्वारंटाइन) का निर्णय लिया। इस दौरान वह जड़ी-बूटियों का सेवन करने लगे। वे 14 दिन में पूरी तरह स्वस्थ होकर 15वें दिन सबके सामने आए।

आज भी ओडिशा के पुरी में हर साल जो भव्य रथयात्रा का आयोजन होता है, उसके दौरान महाप्रभु जगन्नाथजी की वही कहानी दोहराई जाती है। कोरोना संक्रमण के दौर में यह कहानी तो और भी प्रासंगिक हो जाती है। इस बार 12 जुलाई को पुरी में रथयात्रा का आयोजन प्रस्तावित है। इस साल भी यह आयोजन कोविड के नियमों को ध्यान में रखकर ही संपन्न होगा। इस बार भी रथयात्रा से पूर्व महाप्रभु बीमार चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें 108 घड़ों के जल से स्नान कराया गया है। जगन्नाथ जी को 35 स्वर्ण कलश शीतल जल, उनके बड़े भाई बलभद्रजी को 33 स्वर्ण कलश, 22 स्वर्ण कलश से बहन सुभद्रा जी को तथा 18 स्वर्ण कलश शीतल जल से सुदर्शनजी को स्नान कराया गया है। इस कारण ये सभी बीमार हैं, ऐसा माना जाता है। श्रीमंदिर में वे क्वारंटाइन यानी एकांतवास में हैं। उनका आयुर्वेदसम्मत उपचार किया जा रहा है। पुरी जगन्नाथ मंदिर का कपाट दर्शन के लिए बंद है। 14 दिन की अवधि पूर्ण कर जब सभी स्वस्थ होंगे तो 15वें दिन यानी 12 जुलाई को वे रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे।

बदल गया रथयात्रा का स्वरूप : पुरी को जगन्नाथ धाम कहा जाता है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि में विष्णु के दशावतारों में से एक महाप्रभु जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथयात्रा निकाली जाती है। इस दिन अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा एवं सुदर्शन के साथ तीन अलग-अलग रथों पर सवार होकर जगन्नाथ महाप्रभु मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में भक्त रथ की रस्सी खींचने को लालायित रहते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष से रथयात्रा का स्वरूप बदल गया है। बिना भक्तों के ही रथयात्रा निकाली जा रही है। इस बार भी ऐसा ही होगा। हालांकि, ओडिशा सरकार ने टीवी जैसे संचार माध्यमों से महाप्रभु के दर्शन की व्यवस्था कर रखी है।

भोई सेवक करते हैं तीनों रथों का निर्माण : प्रतिवर्ष भोई सेवक तीनों नये रथ बनाते हैं। पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। रथों के निर्माण के लिए हर वर्ष वसंत पंचमी से लकड़ी संग्रह का काम दशपल्ला के जंगलों में शुरू हो जाता है। रथ निर्माण का कार्य वंश परंपरानुसार भोई सेवायतगण अर्थात श्रीमंदिर से जुड़े बढ़ई कारीगर ही करते हैं। कुल 205 सेवायत इस कार्य में उनका सहयोग करते हैं।

जिस प्रकार पांच तत्वों के योग से मानव शरीर का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार पांच तत्वों काष्ठ, धातु, रंग, परिधान तथा सजावटी सामग्री के योग से इन रथों का निर्माण होता है। यह रथयात्रा घोष यात्रा, गुंडिचा यात्रा, पतित-पावन यात्रा, जनकपुरी यात्रा, नवदिवसीय यात्रा तथा दशावतार यात्रा के नाम से चर्चित है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ कलियुग के एकमात्र पूर्णदारुब्रह्म हैं। उन्हें भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक माना जाता है। रथ निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया (इस बार 15 मई) से आरंभ होता है, जिसमें करीब दो महीने का समय लगता है।

-शेषनाथ राय

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 6 जुलाई, 2021 मंगलवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष द्वादशी का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 03:00 बजे से 04:30 बजे तक।
आज का दिशाशूल: उत्तर।

मेष: पारिवारिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। आर्थिक योजना फलीभूत होगी। शासन सत्ता का सहयोग लेने में सफल होंगे। पिता अथवा धर्म गुरु का सहयोग मिलता रहेगा।

वृष: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक योजना फलीभूत होगी। किया गया प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

मिथुन: बहुप्रतिक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बुधादित्य योग आर्थिक दृष्टि से प्रगति का द्वार खोलेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।

कर्क: अधीनस्थ कर्मचारी, भाई या बहन से तनाव मिल सकता है। संयम से काम लें। आर्थिक तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यावसायिक कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी।

सिंह: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।

कन्या: रिश्तों में मधुरता आएगी। उच्च अधिकारी या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। पिता का आशीर्वाद फलीभूत होगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य पूर्ण होगा।

तुला: स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

वृश्चिक: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में बाधा आएगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। जीवनसाथी का सहयोग एवं सान्निध्य मिलेगा।

धनु: आर्थिक मामलों में सुधार होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

मकर: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ रोग या विरोधी तनाव देगा। उदर विकार के प्रति सचेत रहें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आपसी संबंध मधुर होंगे।

कुंभ: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

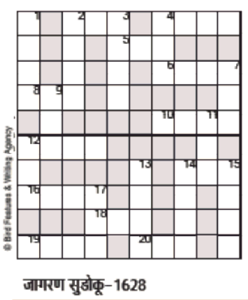
मीन: पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। नए संबंध बनेंगे।

कल 7 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: उत्तर।
विशेष: प्रदोष, बुध मिथुन राशि में।
कल की भद्रा: रात्रि के 03:21 बजे से 08 जुलाई को शाम 04:22 बजे तक।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 उत्तरायन, उत्तरगोल, ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 27 घंटे 21 मिनट तक, तत्पश्चात् चतुर्दशी रोहिणी नक्षत्र 18 घंटे 19 मिनट तक, तत्पश्चात् मृगशिरा नक्षत्र गण्ड योग 15 घंटे 34 मिनट तक, तत्पश्चात् वृद्धि योग वृष में चंद्रमा।

वर्ग पहेली-1628

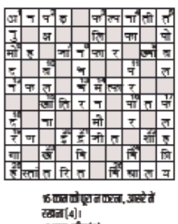


© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
2 [illegible] (3)।
4 [illegible] (4)।
5 [illegible] (3)।
6 [illegible] (4)।
8 [illegible] (3)।
10 [illegible] (2,2)।
12 [illegible] (4)।
14 [illegible] (3)।
16 [illegible] (4)।
18 [illegible] (3)।
19 [illegible] (4)।
20 [illegible] (3)।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] (4)।
2 [illegible] (4)।
3 [illegible] (4)।
4 [illegible] (3)।
7 [illegible] (3)।
9 [illegible] (3)।
11 [illegible] (3)।
12 [illegible] (3)।
13 [illegible] (4)।
14 [illegible] (4)।
15 [illegible] (4)।
17 [illegible] (3)।

कल का हल



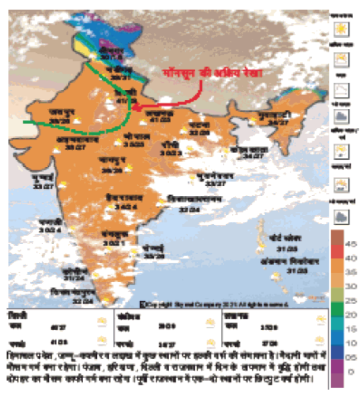
जागरण सुडोकू-1628

		7		6		9		5
3	8				9			6
		9	3		7	4	1	
1			8			5		7
7	4	3			2		6	
	6			4				2
9			6			1		
	1	8		7			5	
5			2			7	8	9

कल का हल

2	5	1	7	9	8	6	3	4
3	8	9	5	6	4	7	2	1
7	6	4	3	2	1	5	8	9
4	7	5	1	3	9	2	6	8
1	9	2	6	8	5	3	4	7
8	3	6	2	4	7	1	9	5
9	1	3	8	7	2	4	5	6
5	2	8	4	1	6	9	7	3
6	4	7	9	5	3	8	1	2

मौसम





ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी



ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी को आज ही के दिन वर्ष 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। लिबरल पार्टी से संसद में पहुंचे नौरोजी ने भाषण के दौरान अंग्रेजी हुकूमत की उस दलील को खारिज कर दिया था कि उसके शासन में भारत का विकास हो रहा है।

रैबीज रोधी टीके का पहली बार किया गया इस्तेमाल



वर्ष 1885 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने पहली बार रैबीज (कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी) के टीके का नौ साल के बच्चे पर इस्तेमाल किया था। भारत में इसके चलते सालाना बीस हजार लोगों की मौत होती है, जो वैश्विक मौतों का 36 फीसद है।

62 साल से निर्वासन में रह रहे आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा



वर्ष 1935 में आज ही के दिन चौदहवें दलाई लामा (तेनजिन ग्यात्सो) का जन्म हुआ था। वे तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। चीन की घुसपैठ के चलते अपने लोगों को प्रताड़ित होता देख वह अप्रैल 1959 को भारत आ गए थे। तब से वह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दरअसल, दलाई लामा एक उपाधि है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा शिक्षक जो आध्यात्मिक रूप से गहरे समुद्र के समान है।

इधर-उधर की

फेसबुक के जरिये सालों पहले खोई अंगूठी मिली

वाशिंगटन, एजेंसी : समय-समय पर हम इंटरनेट मीडिया के फायदे के बारे में सुनते रहते हैं। कई बार यह हमारे इतना काम आता है, जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। अमेरिका के टेक्सास में एक ऐसा ही वाकया हुआ, जहां पर एक महिला को फेसबुक पोस्ट के जरिये 15 साल पहले खोई अंगूठी मिल सकी। दरअसल, ग्रेग काउंटी शेरिफ आफिस ने कुछ दिनों पहले एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि उन्हें एक महिला ने अंगूठी लाकर दी है। उसे यह हाईवे के पास गत अप्रैल महीने में मिली थी। अंगूठी की डिजाइन को देखकर लगता है यह किसी लड़की की है और इस पर लेसी नाम अंकित है। टेक्सास में ही रहने वाली लेसी को जब दोस्तों के जरिये इस बारे में पता चला तो वह शेरिफ आफिस गई और अंगूठी ले ली। लांग व्यू न्यूज जर्नल से बात करते हुए लेसी एकर्स ने कहा कि शुरुआत में तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने यह अंगूठी पिछले 15 सालों से नहीं देखी थी।



यह अंगूठी तब खोई थी जब लेसी हाईस्कूल में थीं • इंटरनेट मीडिया

चेहरा याद रखने वाले सेल की खोज

मिलेगी मदद ▸ राकफेलर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को मिली बड़ी कामयाबी

चेहरा भूलने वाली बीमारियों का खोजा जा सकता है उपचार

वाशिंगटन, एएनआइ : एक इंसान दूसरे का सबसे पहले चेहरा ही देखता है। यही उसकी पहली और मुख्य पहचान भी होती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक बार किसी का चेहरा देखने के बाद जब दोबारा वो सामने आता है तो आप उसे कैसे पहचान लेते हैं। निःसंदेह इसके पीछे हमारा मस्तिष्क है, लेकिन अब विज्ञानियों ने इस दिशा में कुछ और स्पष्टता ला दी है। दरअसल, उन्होंने मस्तिष्क में याददाश्त से संबंधित खास कोशिकाओं (सेल) की पहचान की है, जो चेहरों को याद रखने का काम करती हैं। विज्ञानियों का मानना है कि इस खोज से चेहरों को न पहचान पाने से जुड़ी बीमारियों का उपचार हो सकता है।

राकफेलर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा की गई यह खोज 'साइंस' जर्नल में प्रकाशित की गई है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, मस्तिष्क के टेंपोरल पोल क्षेत्र में एक खास किस्म के न्यूरान पाए जाते हैं, जो चेहरों को लंबे समय तक याद रखने से जुड़े होते हैं। इस शोध में बताया गया है कि मस्तिष्क किस प्रकार से किसी करीबी का चेहरा अपने में संयोजित कर लेता है।

राकफेलर यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस एंड बिहेवियर के प्रोफेसर विनरिच फ्रीवाल्ड के मुताबिक, न्यूरोसाइंस में हम अब तक ग्रैंडमदर न्यूरान को एक परिकल्पना बता कर खारिज करते आए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब हमने पाया है कि ग्रैंडमदर न्यूरान से मिलते-जुलते सेल्स पाए जाते हैं, जो चेहरों को याद रखने में सक्षम होते हैं। ग्रैंडमदर न्यूरान की अवधारणा सबसे पहले पिछली शताब्दी के पांचवें दशक में सैद्धांतिक मस्तिष्क कोशिकाओं के रूप में सामने आई थी और माना गया कि यह किसी खास जटिल संकल्पना का कोड हो सकता है। ग्रैंडमदर की याददाश्त के लिए एक न्यूरान होता है और दूसरे के लिए कोई अन्य तथा इसी प्रकार यह क्रम चलता है। इस तरह से ब्रेन सेल और किसी वस्तु या संकल्पना के बीच एक-एक का अनुपात बनता है और इसी दिशा में यह रहस्य सुलझाने की कोशिश होती है कि पूरे मस्तिष्क में किस प्रकार से लंबे समय तक याददाश्त बनी रहती है। विज्ञानियों ने ऐसे बहुत सारे संवेदी न्यूरान खोजे हैं, जो चेहरे से जुड़ी सूचनाओं की प्रोसेसिंग के लिए विशिष्ट होते हैं और कई ऐसे मेमोरी सेल्स होते हैं, जो इनका डाटा संग्रहित करते हैं। यह ग्रैंडमदर न्यूरान या हाइब्रिड सेल दृष्टिजन्य याददाश्त को संजोने में समर्थ होते हैं। फिर भी अभी तक विज्ञानियों के पास यह जानकारी नहीं थी कि मस्तिष्क कैसे और किस प्रकार से जाने-पहचाने चेहरे की प्रोसेसिंग करता है।

फ्रीवाल्ड और उनके सहयोगियों को हाल ही में इस बात की संभावना दिखी कि मस्तिष्क के टेंपोरल पोल (टीपी) रीजन का एक छोटा-सा हिस्सा चेहरे की पहचान में शामिल हो सकता है। इसकी पड़ताल के लिए टीम ने बंदरों के टीपी रीजन को जूम करने के लिए फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल किया और उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकार्ड किया।

यह आया सामने : शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि टीपी रीजन के न्यूरान की परिचित तथा अपरिचित चेहरों की तरफ प्रतिक्रिया बहुत ही विशिष्ट (सिलेक्टिव) होती है। इतना ही नहीं, परिचित और अपरिचित चेहरों में भेद करने की गति भी बहुत तेज होती है। दिलचस्प यह कि परिचित चेहरों के प्रति उन सेल्स की प्रतिक्रिया अपरिचित चेहरों के मामले से तीन गुना अधिक रही।

यह मिलेगा लाभ

दुनिया की करीब एक फीसद आबादी प्रोसोपैग्नोसिया से पीड़ित है। यह एक प्रकार की मस्तिष्क संबंधी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति को चेहरे पहचानने में परेशानी होती है। फ्रीवाल्ड के मुताबिक, इस बीमारी से ग्रसित लोग अक्सर अवसाद से ग्रसित होते हैं क्योंकि उन्हें अपने लोगों यहां तक कि अपने करीबियों को भी नहीं पहचान पाते। उम्मीद है कि इस खोज से उनका उपचार भी मिल पाएगा।



साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ राकफेलर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का अध्ययन। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया



10 मिनट में डकारे 76 हॉट डॉग...

सोचिए, कोई साधारण इंसान एक मिनट में कितने हॉट डॉग खा सकता है? यह जानकर आपको हैरत होगी कि अमेरिका के जॉय चेस्टनट (बाएं) ने 10 मिनट में 76 हॉट डॉग खाकर अपना ही विश्व रिकार्ड तोड़ दिया है। जॉय ने लगातार 13वीं बार अंतरराष्ट्रीय हॉट डॉग ईटिंग प्रतियोगिता जीती है। पिछले साल उन्होंने 75 हॉट डॉग खाकर यह प्रतियोगिता जीती थी। न्यूयार्क के नाथन में कोनी द्वीप में वर्ष 1916 में यह प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी। एएफपी

हड्डियों को प्रभावित कर सकता है ब्रेस्ट कैंसर

वाशिंगटन, एएनआइ : ब्रेस्ट कैंसर को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना हेल्थ साइंसेज के शोधकर्ताओं ने पाया है कि कैंसर सेल सख्त ऊतकों के संपर्क में आने से और भी आक्रामक हो जाते हैं और उनमें होने वाला बदलाव काफी लंबे समय तक बना रहता है।

सेल रिपोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित शोध 'ब्रेस्ट ट्यूमर स्टिफनस इंस्ट्रक्ट्स बोन मेटासिस वाया मेंटेनेंस आफ मैकेनिकल कंडिशनिंग' के मुताबिक, ब्रेस्ट ट्यूमर का कड़ापन कैंसर सेल में बदलाव पैदा कर सकता है और उसे हड्डियों तक फैलने के लिए ज्यादा आक्रामक बना सकता है। कैंसर सेल शरीर के दूसरे हिस्सों में किस प्रकार फैलेगा, इसमें ट्यूमर के सख्त या कड़े होने की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस कारण होने वाले बदलाव 'मैकेनिकल मेमोरी' के रूप में कायम रहते हैं, जिससे कैंसर सेल को हड्डियों में जाकर उसे कमजोर करने सिग्नल मिलता है। एक बार ऐसी स्थिति बनने पर अक्सर स्वतः ही फ्रैक्चर होने लगता है। इस शोध के वरिष्ठ लेखक व यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना कालेज आफ मेडिसिन में सेलुलर एंड मालिक्युलर मेडिसिन एंड कैंसर बायोलाजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर घासन मौनीम्ने का कहना है कि यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बोन मेटासिस सामान्यतौर पर तब तक पहचान में नहीं आता, जब तक कि वह एडवांस्ड स्टेज में नहीं पहुंच जाए। मेटासिस की प्रक्रिया में कैंसर सेल अपने प्राथमिक स्थान से टूट कर ब्लड या लिंफ सिस्टम (लसिका तंत्र) के जरिये दूसरे हिस्से में जाकर मूल स्वरूप जैसा ही ट्यूमर बनाता है।

अक्ल दाढ़ निकालने से बढ़ जाती है स्वाद क्षमता

वाशिंगटन, एएनआइ : अक्ल दाढ़, जिसे विज्ञान में दांतों के प्रकार में 'थर्ड मोलर' कहा जाता है, के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। यह भी अवधारणा रही है कि इसे निकाल दिए जाने का स्वाद क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब एक नए शोध से सामने आया है कि इसके निकालने जाने से स्वाद क्षमता घटती नहीं, बल्कि बढ़ जाती है और लगभग 20 वर्षों तक बनी रहती है।

न्यू पेन मेडिसिन का यह शोध निष्कर्ष केमिकल सेंसेस में प्रकाशित हुआ है। यूनिवर्सिटी आफ पेंसिल्वेनिया के स्मेल एंड टेस्ट सेंटर के निदेशक तथा इस शोध के वरिष्ठ लेखक रिचर्ड एल. डाटी के मुताबिक, पहले के अध्ययनों में अक्ल दाढ़ के निकाले जाने से स्वाद पर सिर्फ नकारात्मक असर होने की बातें की जाती थीं और माना जाता था कि लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। वहीं, हमारे अध्ययन में पाया गया कि असल में तो स्वाद क्षमता में हल्का सुधार ही आता है, जो सर्जरी के समय से लेकर तकरीबन 20 साल तक बना रहता है। यह एक आश्चर्यजनक, लेकिन दिलचस्प निष्कर्ष है। इसलिए इसकी पड़ताल के लिए और अधिक अध्ययन की जरूरत है।

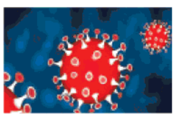
डाटी और सह लेखक डेन किम (यूनिवर्सिटी आफ पेंसिल्वेनिया स्कूल आफ डेंटल मेडिसिन के तृतीय वर्ष के छात्र) ने अपने शोध के लिए स्मेल एंड टेस्ट सेंटर में केमोसेंसरी जांच के लिए आए 1,255 लोगों के डाटा का विश्लेषण किया। इनमें से 891 लोगों की अक्ल दाढ़ निकाली जा चुकी थी और 364 लोग सामान्य थे। इनकी जांच (होल माउथ आइडेंटिफिकेशन) के क्रम में लोगों को सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, साइट्रिक एसिड तथा कैफीन की पांच विभिन्न सांद्रता वाले घोल की घूंट लेने, उसे मुंह में गलगलाने और फिर बाहर फेंकने को कहा गया। फिर उनसे घोल के स्वाद मीठा, नमकीन, खट्टा या तीखा के बारे में पूछा गया।

यह आया सामने : जांच में पाया गया कि जिन लोगों की अक्ल दाढ़ निकाली जा चुकी थी, चारों स्वाद के प्रति उनकी पहचान अच्छी थी और खास बात यह कि महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों के मुकाबले बेहतर था। स्वाद क्षमता में तीन से 10 फीसद तक इजाफा देखा गया।

▸ **अभी तक स्वाद क्षमता पर विपरीत प्रभाव की रही है अवधारणा**

कोरोना संक्रमण से मुकाबले के लिए नया उपचार तलाशा

अनुसंधान



जारी है कोरोना से जंग। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

कोरोना वायरस से जंग में नए उपचारों और दवाओं की तलाश में निरंतर शोध किए जा रहे हैं। इसी कवायद में शोधकर्ताओं को कोरोना संक्रमण से मुकाबले में एक उपचार की पहचान करने में सफलता मिली है। यह नया उपचार चूहों में वायरस की प्रतिकृति बनने से रोकने में प्रभावी पाया गया है। नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज की प्रोसिडिंग्स पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, कोरोना संक्रमित पशु माडल का एक प्रोटीज एंजाइम से इलाज किया गया। इसके माध्यम से हुए उपचार से बचने की संभावना में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ही फेफड़ों में वायरल लोड में कमी पाई गई। ये प्रोटीज इंहिबटर एंटीवायरल दवाओं का एक वर्ग है। इस वर्ग की दवाएं वायरल एंजाइम से जुड़ने के साथ प्रोटीन की सक्रियता को रोकने का काम करती हैं। संक्रामक वायरल पार्टिकल की उत्पत्ति के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अमेरिका की कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर युंजोंग किम ने कहा, 'हमने बिल्लियों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए प्रोटीज इंहिबटर जीसी376 विकसित किया है। यह अब व्यावसायिक इस्तेमाल के लिहाज से विकास की प्रक्रिया में है।' उन्होंने बताया, 'मौजूदा महामारी शुरू होने के बाद कई रिसर्च समूहों ने बताया कि यह इंहिबटर उस कोरोना वायरस के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है, जो कोविड-19 का कारण बनता है। इस समय उपचार के तौर पर प्रोटीज इंहिबटर के विकास पर कई शोध किए जा रहे हैं।' शोधकर्ताओं की टीम ने जीसी376 में बदलाव कर इसके प्रभाव को कोविड-19 के खिलाफ आजमाया। यह परीक्षण कोविड-19 का कारण बनने वाले सार्स-कोव-2 वायरस से संक्रमित चूहों पर किया गया। इसका नतीजा उत्साहजनक बताया गया है। -प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

खुद पर यकीन हो तो कुछ भी पा सकते हैं : देवोलीना



टीवी इंडस्ट्री में देवोलीना के 10 साल पूरे। इंस्टाग्राम

जीवन का संघर्ष हमेशा याद रहता है। टीवी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी का बचपन भी काफी मुश्किलों में बीता है। टीवी इंडस्ट्री में अपने 10 साल पूरे होने पर देवोलीना ने इस बारे में इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपने फैंस से बात की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में सवारे सबके सपने प्रीतो धारावाहिक से की थी। इसके बाद वह साथ निभाना साथिया, बिग बॉस 13 जैसे कई शोज कर चुकी हैं। देवोलीना ने कहा कि अगर आपको खुद पर यकीन हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। मैंने यही अपने इस सफर में सीखा है। यह एक दिन का सपना नहीं था। मैं 10वीं क्लास में थी, जब मैंने अपने पिता को खो दिया था। तब लगा था कि अब क्या करूंगी। मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। विज्ञान पढ़ना चाहती थी। मुझे समझ आ गया था कि अब कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना पूरा नहीं होगा। तब जेहन में आया था कि बड़ी होकर कुछ अच्छा करूंगी, ताकि पिता जहां से भी मुझे देख रहे हों, उन्हें मुझ पर गर्व हो। हम जो सोचते हैं, वही होता है। उस एक विचार की वजह से आज यहां पर हूं। मैंने कॉमर्स से पढ़ाई पूरी की, डांस सीखा। जो काम मिला, उसे मेहनत से करती गई। मेरा मंत्र हमेशा से यही रहा है कि ईश्वर के अलावा कभी किसी पर निर्भर नहीं होना है।

सैर-सपाटा और रोमांस...

अपने हमसफर के साथ दुनिया की सैर करने का एक अनोखा ही आनंद होता है। अभिनेत्री गौहर खान फिलहाल रूस में कुछ इसी तरह का आनंद ले रही हैं, जहां वह पति जैद दरबार के साथ हनीमून मनाने गई हैं। रविवार को गौहर ने इंस्टाग्राम पर रूस की राजधानी मास्को से कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह जैद दरबार के साथ बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ गौहर ने जैद को टैग करते हुए लिखा, 'मास्को में प्यार...।' इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जैद ने भी गौहर के प्रति अपना प्यार जताया। बता दें कि गौहर और जैद ने पिछले साल दिसंबर में शादी की थी। जैद संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं। दूसरी तरफ गौहर की आगामी फिल्म 14 फेरे की रिलीज डेट का भी एलान हो गया है। यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म जी5 पर 23 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म में विक्रांत मेस्सी और कृति खरबंदा मुख्य भूमिकाओं में हैं।



कॉमेडी फैक्ट्री में लाफिंग बुद्धा बनेंगी फराह

बदलते वक्त के साथ-साथ टेलीविजन के कॉमेडी रियलिटी शोज में भी कई अनोखे प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे ही प्रयोगात्मक कदम के तहत जी टीवी पर एक नया कॉमेडी रियलिटी शो कॉमेडी फैक्ट्री शुरू होने जा रहा है। कॉमेडियन अली असगर, सुगंधा मिश्रा, संकेत भोसले, गौरव दुबे, बलराज सियाल, सिद्धार्थ सागर, दिव्यांश द्विवेदी अभिनेता तेजस्वी प्रकाश, सिंगर और एंकर आदित्य नारायण तथा डांसर पुनीत जे पाठक बतौर प्रतिभागी इस शो का हिस्सा होंगे। इन सभी 10 प्रतिभागियों को पांच-पांच लोगों की दो टीमों में बांटा जाएगा, जिसमें दोनों टीमों के प्रतिभागी अपने स्टैंड अप कॉमेडी, विजुअल कॉमेडी, अनोखे करतब या फिर गाने के माध्यम से दर्शकों को हंसाएंगे। फिल्म निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान इस शो से बतौर लाफिंग बुद्धा जुड़ेंगी। लाफिंग बुद्धा के तौर पर वह न सिर्फ प्रतिभागियों की परफार्मेंस पर प्रतिक्रिया देंगी, बल्कि वह दोनों टीमों को उनकी परफार्मेंस के आधार पर अंक भी देंगी। शो के बारे में दैनिक जागरण से बातचीत में फराह ने कहा, 'इस शो की संकल्पना बहुत ही अनोखी है। दो कॉमेडियन के बीच सिर्फ कंपटीशन होने की बजाय इस शो में स्टैंडअप, स्पूफ, स्किट और पैरोडी (कॉमेडी के अलग-अलग प्रारूप) का एक मिला-जुला परफार्मेंस दिखेगा। हम चाहते हैं पूरा परिवार इस शो को एक साथ बैठकर देखे और देश के शीर्ष कॉमेडियन्स की परफार्मेंस का आनंद ले। शो में मुझे लाफिंग बुद्धा बुलाया जाएगा। प्रतिभागियों को मेरे साथ-साथ दर्शकों को हंसाना पड़ेगा। इन मुश्किल परिस्थितियों में मुझे सबसे बेस्ट काम मिला है।' इस शो का प्रसारण 31 जुलाई से हर शनिवार और रविवार जी टीवी पर किया जाएगा।



शो में निर्णायक की भूमिका में रहेंगी फराह। सौ. पीआर टीम

लाइगर की 65 फीसद शूटिंग पूरी

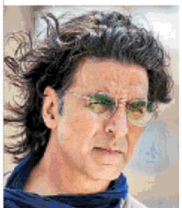
इस साल की शुरुआत में फिल्मकार करण जौहर ने अभिनेत्री अनन्या पांडे और तेलुगु अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म लाइगर का एलान किया था। इस फिल्म को नौ सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी और अब इस फिल्म को सितंबर में रिलीज किया जाना संभव नहीं दिख रहा है। एक इंटरव्यू में इस फिल्म के बारे में बात करते हुए अभिनेता विजय देवरकोंडा ने बताया कि फिल्म की 65 फीसद शूटिंग पूरी हो चुकी है। लाइगर को बड़े स्केल पर बनाया जाना ही इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें जुलाई-अगस्त तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने की उम्मीद है। फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं, जिनको शूट करने के लिए सेट पर लगभग एक हजार लोगों की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अभी ऐसे सीन की शूटिंग स्थगित की गई है। कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका को देखते हुए फिलहाल हमारी टीम ऐसे सीन की शूटिंग का हल निकालने में जुटी हुई है। पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बन रही लाइगर में मकरंद देशपांडे और रोनित रॉय भी अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं, अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने सोमवार से कोलकाता में अपनी हिंदी फिल्म उमा की शूटिंग शुरू कर दी है। तथागत सिंघा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को शुरू से लेकर अंत तक कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक ही शेड्यूल में शूट किया जाएगा। इस फैमिली ड्रामा फिल्म में काजल के साथ टीनू आनंद, हर्ष छाया और गौरव शर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं।



लाइगर से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करेंगे विजय। इंस्टाग्राम

निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि फिल्म की कहानी या लोकेशन के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसे उत्तर व दक्षिण भारत की अलग-अलग लोकेशन पर शूट किया जाएगा।

प्लान के मुताबिक शूट होगी राम सेतु



फिल्म में पुरातत्वविद का किरदार निभा रहे हैं अक्षय कुमार • इंस्टाग्राम

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म राम सेतु को लेकर खबरें थी कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन में बदलाव किया जाएगा। हालांकि, लोकेशन में बदलाव की खबरों को फिल्म के निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने अफवाह करार दिया है। दैनिक जागरण से बातचीत में इस फिल्म के बारे में अपडेट देते हुए उन्होंने कहा, फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद हमने मुंबई में पांच दिनों की शूटिंग की थी। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई और अक्षय कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो हमें फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। बहुत जल्द ही फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू होगी और यह फिल्म सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग लोकेशन बदलने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। राम सेतु जिस तरीके से पहले प्लान की गई थी, उसी के अनुसार शूट होगी। इस फिल्म को मुंबई के अलावा उत्तर और दक्षिण भारत के अलग-अलग लोकेशन पर शूट किया जाना है। फिल्म को कुछ इंटरनेशनल लोकेशन पर भी शूट किया जाना है, उसके लिए हमने अलग से एक इंटरनेशनल शेड्यूल तैयार किया है। किसी भी परिस्थिति में फिल्म की कहानी या लोकेशन के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फिल्म राम सेतु में अक्षय पुरातत्वविद की भूमिका निभा रहे हैं। वह फिलहाल अपनी एक अन्य फिल्म रक्षा बंधन की शूटिंग में व्यस्त हैं।

मर्डर मिस्ट्री बनाएंगे दिनेश विजन

अब निर्माता दिनेश विजन की आगामी फिल्म भी एक किताब पर आधारित होगी। स्त्री, बाला, हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों के निर्माता दिनेश ने लेखिका अनुजा चौहान के उपन्यास क्लब यू टू डेथ के राइट्स खरीद लिए हैं। यह एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म होगी। कहानी दिल्ली के पॉश टर्फ क्लब की है, जहां क्लब के चुनाव के दौरान एक पर्सनल ट्रेनर की गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। क्राइम ब्रांच की एसीपी भवानी सिंह को इस केस की जांच का जिम्मा सौंपा जाता है। इससे पहले अनुजा की किताब पर द जोया फैक्टर फिल्म बन चुकी है। दैनिक जागरण से बात करते हुए अनुजा ने कहा कि जितने लोग किताब पढ़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग फिल्में देखते हैं। ऑडियो-विजुअल फॉर्मेट को देखने वालों की संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी लेखक के लिए उसकी किताब पर फिल्म बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जितने लोग किताब को फिल्म के रूप में देखेंगे, उतना ही उनका ध्यान किताब पढ़ने की ओर जाएगा। मेरी किताब मर्डर मिस्ट्री है। मैंने देखा है कि कई बार मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्मों की शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन अंत तक फिल्म में रोमांच खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूं कि यह फिल्म उनसे अलग बनेगी। किताब पर बनी यह फिल्म पहले ही इसे पढ़ चुके लोगों के लिए कितनी रोमांचक होगी, इस पर कहती हैं कि मैंने अगाथा क्रिस्टी की किताबें पढ़ी हैं और उन किताबों पर बनी फिल्मों को भी देखा है। किताब जब फिल्म में रूपांतरित होती है, तो जादू हो जाता है।



दिनेश विजन की आगामी फिल्म होगी मर्डर मिस्ट्री • इंस्टाग्राम

यू टर्न में दिखेंगे ढेर सारे उतार-चढ़ाव

पिछले साल रिलीज हुई फिल्म जवानी जानेमन से सैफ अली खान के साथ हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने वाली अभिनेत्री अलाया एफ ने अपने करियर की तीसरी फिल्म साइन की है। इसके पहले उन्होंने जवानी जानेमन रिलीज होने के तुरंत बाद निर्माता जैकी भगनानी के साथ अपनी दूसरी फिल्म साइन की थी। हालांकि, उसके बाद कोरोना महामारी आ गई और उस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। अलाया की तीसरी फिल्म यू टर्न होगी, जिसे उन्होंने एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले साइन किया है। यह फिल्म साल 2016 में इसी नाम से बनी कन्नड़ फिल्म की हिंदी रीमेक होगी। कन्नड़ अभिनेता और फिल्मकार पवन कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को साल 2016 में तमिल और तेलुगु में भी बनाया गया था। जिसमें सामंथा अक्किनेनी प्रमुख भूमिका में थी। हिंदी में इस फिल्म का निर्देशन गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल और हॉफ गर्लफ्रेंड में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे आरिफ खान करेंगे। फिल्म की शूटिंग आज (मंगलवार) से शुरू होगी। इस फिल्म को लेकर दैनिक जागरण से बातचीत में एकता कपूर ने कहा, च्वेब्यू फिल्म में अलाया का काम शानदार था। उनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, जो उन्हें दर्शकों से जोड़ सकते हैं। यू टर्न में आपको ढेर सारे उतार-चढ़ाव और रोमांच देखने को मिलेगा।ज वहीं अलाया ने कहा, च्अपने करियर के इतने शुरुआती दौर में एकता मैम के साथ जुड़ना एक शानदार मौका है, खासतौर पर यू टर्न जैसे दिलचस्प प्रोजेक्ट में।



कन्नड़ फिल्म की रीमेक बना रही हैं एकता कपूर • जागरण आर्काइव

हीरा मंडी के लिए सोनाक्षी सिन्हा सीखेंगी कथक

बड़े प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग करने में वक्त लगता है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद अब संजय लीला भंसाली अपनी आगामी वेब सीरीज पर काम कर रहे हैं। हीरा मंडी नाम की यह वेब सीरीज बड़े स्केल पर शूट होने वाली है। हुमा कुरैशी पहले ही इस सीरीज में सेक्स वर्कर का किरदार करने के लिए फाइनल हो चुकी हैं। वहीं अब खबरों के मुताबिक इस सीरीज की दूसरी अभिनेत्री भी संजय को मिल गई है। खबरों की मानें तो सोनाक्षी सिन्हा हीरा मंडी में अहम किरदार कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय की इस वेब सीरीज में काम करने का सुझाव सोनाक्षी को उनके पापा शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया है। वह चाहते हैं कि सोनाक्षी संजय के साथ काम करें। वैसे इससे पहले सोनाक्षी भंसाली प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी फिल्म राउड़ी राठौर में अभिनय कर चुकी हैं। खबरों के मुताबिक सोनाक्षी हीरा मंडी के लिए कथक भी सीखने वाली हैं, क्योंकि उन्हें इसमें मुजरा करना होगा। संजय इस कोशिश में लगे हैं कि हीरा मंडी में दिखाया जाने वाला मुजरा पाकीजा और उमराव जान जैसी फिल्मों के मुजरे से अलग हो। वहीं कुछ वक्त पहले खबरें आई थी कि माधुरी दीक्षित भी इस सीरीज के लिए मुजरा शूट करेंगी, जो सीरीज का सबसे बड़ा हाइलाइट होगा।



भुज : द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगी सोनाक्षी • इंस्टाग्राम »